राष्ट्रीय संस्करण

वर्ष 9 अंक 323

दैनिक जागरण

मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शनिवार, 2 मई, 2026

www.jagran.com

पृष्ठ 14

भाषा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं
>> 5

लापरवाही के क्रूज ने ली नौ लोगों की जान, सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन

टीम नईदुनिया, जबलपुर

जबलपुर शहर के पास स्थित बरगी बांध में गुरुवार को क्रूज के डूबने से ही नहीं, बल्कि घोर प्रशासनिक लापरवाही के चलते भी नौ निर्दोष लोगों की जान गई। लापरवाही का आलम यह रहा कि कदम-कदम पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया गया। आंधी शुरू होते ही लोगों ने कैप्टन से क्रूज को किनारे ले चलने का अनुरोध किया, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर लोगों को मौत के मुंह में जाने का रास्ता बना दिया। यदि नियमों का पालन किया जाता और कैप्टन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाहन करता तो असमय काल के गाल में समा गए लोगों को बचाया जा सकता था।

बरगी बांध में प्रतिदिन शाम को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का क्रूज पर्यटकों को सवारी कराता है। गुरुवार शाम लगभग साढ़े पांच बजे क्रूज पर्यटकों को लेकर बांध की लहरों के बीच आगे बढ़ रहा था कि तभी मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं के चलते क्रूज में पानी भरने लगा और कुछ ही देर में वह नियंत्रण खोकर डूबने लगा। एसडीआरएफ का दल भी घटना के चार घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंचा। छोटे क्रूज के संचालन प्रोटोकाल में 50 किमी प्रति घंटा की गति की हवा भी अत्यंत खतरनाक मानी जाती है। ऐसे में क्रूज का संचालन करने वाले मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम को तेज हवा की चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन उसने इसकी अनदेखी की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस हादसे पर शोक जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के स्वजन को दो-दो लाख तथा घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। (पेज 6 भी देखें)

दर्दनाक घटना

- तेज हवा की चेतावनी की अनदेखी की गई, शुरू में किसी को नहीं पहनाई गई लाइफ जैकेट
- जबलपुर के पास बरगी बांध क्रूज हादसे में 28 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, चार लोग अब भी लापता

अभी तो तेज आंधी को ही हादसे का कारण माना गया है। जब हवा चली तो सभी लोगों ने लाइफ जैकेट पहन ली थीं। प्रथम दृष्टया यह समझ आया कि हवा चलने के दौरान ऊपर वाले पर्यटक भी नीचे बंद केबिन में आ गए थे, जो क्रूज डूबने के दौरान निकल नहीं पाए।
- धर्मेंद्र सिंह लोधी, पर्यटन मंत्री, मध्य प्रदेश

जबलपुर के बरगी बांध में हादसे के बाद शुक्रवार को एनडीआरएफ और अन्य बचाव कर्मियों ने दुर्घटनाग्रस्त क्रूज बोट को बाहर निकाला। प्रेट्र

पांच और पर्यटकों के शव मिले

डूबे क्रूज में सवार पांच और पर्यटकों के शव शुक्रवार सुबह मिले। इससे हादसे में मृतकों की संख्या नौ हो गई है। चार लोग अब भी लापता हैं। कुल 41 लोग सवार थे, जिनमें 28 को सुरक्षित बचा लिया गया। घटना के लगभग 21 घंटे के बाद शुक्रवार दोपहर क्रूज को तट तक लाया जा सका।

वृंदावन हादसे के बाद भी नहीं लिया सबक

जासं, मथुरा : गत 10 अप्रैल को वृंदावन स्थित यमुना में पैंटून पुल के पीपा से टकराकर मोटरबोट के पलटने से पंजाब के 16 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। किसी श्रद्धालु के पास लाइफ जैकेट नहीं था। जबलपुर के हादसे से पता चलता है कि वृंदावन हादसे से भी सबक नहीं लिया गया।

यहां हुई घोर लापरवाही

- नेशनल इंस्टीट्यूट आफ वाटर स्पोर्ट्स क्रूज संचालन के सुरक्षा नियमों के तहत प्रत्येक यात्री को एक लाइफ जैकेट पहनाई जानी चाहिए। बच्चों के लिए अलग साइज की जैकेट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था।
- बोट या क्रूज संचालन करने वाले स्टाफ को अपातकालीन स्थिति संभालने में प्रशिक्षित होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया। यदि मौसम खराब (तेज हवा, बारिश, तूफान) हो तो क्रूज का संचालन तुरंत रोक देना चाहिए। खराब मौसम के बावजूद क्रूज का संचालन किया गया।
- यात्रा शुरू होने से पहले सभी यात्रियों को आवश्यक सावधानी बरतने के बारे में बताना जरूरी है। खासकर लाइफ जैकेट कैसे पहनें, आपात स्थिति में क्या करें, इसके बारे में विस्तार से बताया जाए। इसका पालन नहीं हुआ। 15 पर्यटकों पर एक लाइफ गार्ड नियुक्त होना चाहिए, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसके पालन में भी लापरवाही सामने आई।

प्रथम दृष्टया हादसे के जिम्मेदार

विभागीय सूत्रों के अनुसार बांध में क्रूज का संचालन ठीक से कराने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन निगम जबलपुर के रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा, जल क्रीड़ा सलाहकार राजेंद्र निगम, क्रूज कैप्टन महेश पटेल और क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड सीधे तौर पर उत्तरदायी हैं।

इन पर हुई कार्रवाई

शुक्रवार को जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने क्रूज पायलट महेश पटेल, क्रूज हेल्पर छोटेलाल गोंड और टिकट काउंटर प्रभारी बृजेंद्र की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश दिए। होटल मैकल रिसार्ट और बोट क्लब बरगी के मैनेजर सुनील मरावी को कार्य में लापरवाही बरतने के कारण निलंबित किया गया। रीजनल मैनेजर संजय मल्होत्रा को मुख्यालय अटैच कर विभागीय जांच करवाई जा रही है।

यात्रा

आस्था और रोमांच के साथ यहां मिलती है आत्मिक शांति

बागेश्वर: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित मजुवा टाप की करें यात्रा, यहां हर तरफ है सुकून। • पेज-7

संपादकीय

आजीविका का संकट बढ़ाएगी बढ़ती गर्मी: गर्मी से रोजगार पर संकट का समाधान आवश्यक है, क्योंकि तेज गर्मी से श्रमिकों के साथ देश की उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है। **आदित्य सिन्हा** का विश्लेषण।

ओपेक के हाथ से फिसलता तेल बाजार: यूएई का ओपेक से अलग होना उत्पादन कोटे पर मतभेदों का नहीं, ऊर्जा संप्रभुता की बदलती परिभाषा का संकेत है। **रामिश सिद्दीकी** का आलेख। • पेज-8

विमर्श

दीर्घकालिक विकास में बाधक 'मुफ्त' की नीति: चुनावों के दौरान तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अनेक चीजें मुफ्त प्रदान करने का वादा करते हैं। **डा. विकास सिंह** का विश्लेषण।

ओटीटी ने बदली डबिंग की दुनिया: विदेशी भाषाओं की कहानियां डबिंग होकर भारत में देखी जा रही हैं। भारतीय कहानियां वैश्विक पहचान बना रही हैं। मनोरंजन वैश्विक संवाद और सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक बन रहा है। **डा. मुकुल श्रीवास्तव** का आलेख। • पेज-9

आइपीएल 19 धूम धड़ाका

आज का मैच

चेन्नई सुपर किंग्स vs मुंबई इंडियंस

शाम 7:30 **बजे** **स्थान :** चेन्नई

प्रसारण : स्टार स्पोर्ट्स/जियो हाटस्टार

दैनिक जागरण सप्तरंग

जोश नई राहों का

संभावनाओं से भरा क्षेत्र कोर इंजीनियरिंग

सीखें भविष्य का हुनर • पेज-13

बंगाल में आज 15 बूथों पर पुनर्मतदान कराने का फैसला

नई दिल्ली: बंगाल के मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों पर दो मई को दोबारा मतदान होगा। चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इन बूथों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। इनमें मगराहाट पश्चिम हाट के 11 और डायमंड हार्बर सीट के चार बूथ शामिल हैं। (पेज-4)

कमर्शियल सिलिंडर 993 रुपये महंगा, 'छोटू' के दाम भी बढ़े

पेट्रोल, डीजल की कीमतों में निकट भविष्य में वृद्धि की संभावना से इन्कार नहीं | होटल-रेस्तरां जैसे प्रतिष्ठानों पर बोझ पड़ेगा, बढ़ सकती हैं भोजन की कीमतें

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संघर्ष की तपिश अब भारतीय जनता भी कुछ ज्यादा ही महसूस करेगी। शुक्रवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों (ओएमसी) ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलिंडर (जिनका इस्तेमाल होटल, रेस्तरां और छोटे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है) की कीमत में एक साथ 993 रुपये का इजाफा कर दिया है। अब दिल्ली में यह रिकार्ड 3,071.50 रुपये प्रति सिलिंडर हो गया है, जबकि पहले यह 2,078.50 रुपये था। यह तीसरी लगातार मासिक बढ़ोतरी है। पांच किलोग्राम के छोटू सिलिंडर की कीमत भी 261 रुपये बढ़ गई है, जो खासकर गरीब परिवारों, मजदूरों और छात्रों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ओएमसी ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी (14.2 किलोग्राम के सिलिंडर) और पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आइओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल का कहना है कि कच्चे तेल व एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विनिमय दर के आधार पर कमर्शियल सिलिंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं। इसके पहले मार्च में 114.50 रुपये, अप्रैल में 195.50 रुपये और अब मई में 993 रुपये की बढ़ोतरी के साथ तीन महीनों में कुल 1303 रुपये प्रति सिलिंडर की वृद्धि हो चुकी है। होटल-रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इससे सीधा बोझ पड़ेगा, जिससे भोजन की कीमतें बढ़ सकती हैं और छोटे व्यवसाय प्रभावित हो सकते हैं।

प्रेट्र के अनुसार, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिलहाल भले ही कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद खुदरा दरों में चार साल से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इससे तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान के चलते निकट भविष्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

- कमर्शियल सिलिंडर की कीमत में यह अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी
- कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगातार तीसरे महीने बढ़ाई गई

जम्मू-कश्मीर में शुक्रवार को एक गैस एजेंसी में कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर जमा करते कर्मी। प्रेट्र

वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के बावजूद भारत ने चार साल और 60 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में स्थिरता बनाए रखी है। वैश्विक संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव के बावजूद भारत का ऊर्जा परिदृश्य स्थिर बना रहा, जबकि पड़ोसी देशों में ईंधन की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने प्रतिक्रिया देते हुए या घबराहट में आकर नीतिगत निर्णय लेने से परहेज किया है।

-हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

घरेलू एटीएफ की कीमतों में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली, प्रेट्र : घरेलू विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में शुक्रवार को कोई बदलाव नहीं किया गया। इससे स्थानीय कंपनियों को राहत मिली है। घरेलू यात्रियों को भी फिलहाल किराये में वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ेगा। घरेलू विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन की कीमत 1,04,927.18 रुपये प्रति किलोलीटर पर स्थिर रखी गई है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए विमान ईंधन की कीमत 7,255.36 रुपये प्रति किलोलीटर (5.33 प्रतिशत) बढ़ाकर इसे 1,43,297.42 रुपये प्रति किलोलीटर कर दिया गया है।

'एलपीजी की किल्लत की वजह से श्रमिक लौट रहे हैं गांव' पेज>>5

अप्रैल में 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंचा जीएसटी संग्रह

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

पश्चिम एशिया संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था भले ही प्रभावित हो रही हो, लेकिन घरेलू अर्थव्यवस्था में पहले की तरह मजबूती जारी है। चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले महीने अप्रैल का जीएसटी संग्रह इस मजबूती को साफ तौर पर दर्शा रहा है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 8.7 प्रतिशत बढ़कर करीब 2.43 लाख करोड़ रुपये के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल अप्रैल में 2.23 लाख रुपये का जीएसटी संग्रह किया गया था जो अब तक का सर्वाधिक संग्रह था।

जीएसटी संग्रह सीधे तौर पर घरेलू बिक्री से जुड़ा है। घरेलू बिक्री जितनी अधिक होगी, जीएसटी का संग्रह उतना ही अधिक होगा। हालांकि, अप्रैल के जीएसटी संग्रह में आयातित माल से मिलने वाले संग्रह की हिस्सेदारी अधिक है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल में घरेलू लेनदेन से सकल राजस्व 4.3 प्रतिशत बढ़कर 1.85 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जबकि आयात से जीएसटी संग्रह 25.8 प्रतिशत की तेज वृद्धि के साथ 57,580 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अप्रैल में केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) संग्रह 52,140 करोड़ रुपये और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह 61,331 करोड़ रुपये रहा। एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) से राजस्व संग्रह 1.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। इस अवधि में रिफंड 19.3 प्रतिशत बढ़कर 31,793 करोड़ रुपये हो गया। रिफंड समायोजन के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 7.3 प्रतिशत बढ़कर लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपये रहा। सितंबर 2025 से लागू हुए व्यापक जीएसटी सुधारों के तहत करीब 375 वस्तुओं पर कर दरें घटाई गईं और चार स्लैब को मिलाकर पांच एवं 18 प्रतिशत के दो कर स्लैब कर दिए गए। हालांकि कुछ विलासिता वाले एवं तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत की उच्च दर बरकरार रखी गई है।

- पश्चिम एशिया संकट के बावजूद घरेलू अर्थव्यवस्था में पहले की तरह मजबूती जारी
- 2.23 लाख करोड़ रुपये रहा था जीएसटी संग्रह पिछले साल की समान अवधि में

प्रतीकात्मक

यह तो तय है कि घरेलू लेनदेन बढ़ रहा है। भले ही यह आयातित माल के ट्रांजेक्शन से प्रेरित है। डालर के मुकाबले रुपये में गिरावट से भी आयातित माल से जुड़े जीएसटी संग्रह अधिक दिख रहे हैं। घरेलू स्तर पर जिन सेक्टर की बिक्री कम हुई है, आने वाले महीनों में उन पर विचार करने की जरूरत है।
-हरप्रीत सिंह, (अप्रत्यक्ष कर), डेलाइट पार्टनर

गुजरात में देश का पहला बैरियर मुक्त टोल प्लाजा शुरू

नई दिल्ली: नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर अब आपको न तो रुकना पड़ेगा और न ही लंबी कतार के झंझट में पड़ना पड़ेगा। फर्राटा भरते हुए आप वहां से निकल सकेंगे। टोल स्वत: कट जाएगा। भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे (एनएच-48) पर सूरत और भरूच के बीच चौरियासी खंड पर शुक्रवार को चालू हो गया। (पेज-3)

बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट से परेशान महिला ने दी जान

बिजनौर : उत्तर प्रदेश के बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट से परेशान होकर महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। स्वजन डिजिटल अरेस्ट किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस ब्लैकमेलिंग का अंदेशा जता रही है। बिजनौर के एसपी अभिषेक झा ने कहा कि अभी तक की जांच में डिजिटल अरेस्ट का तथ्य सामने नहीं आया है। पुलिस की तीन टीमों ने जांच शुरू कर दी है। (पेज-6)

ड्रग्स तस्करों पर 'आपरेशन ग्लोबल हंट' और 'आपरेशन व्हाइट' का कहर

नीलू रंजन • जागरण

- मुंबई में उच्च गुणवत्ता वाली 349 किलोग्राम कोकेन जब्त
- विदेश में रह रहे कई ड्रग्स तस्करों पर कसा जा रहा शिकंजा

नई दिल्ली : नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का 'आपरेशन ग्लोबल हंट' और 'आपरेशन व्हाइट' ड्रग्स तस्करी के अंतराष्ट्रीय और राष्ट्रीय सिंडिकेट पर कहर साबित हो रहा है। 'आपरेशन ग्लोबल हंट' के तहत अंतरराष्ट्रीय आतंकी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को तुर्किये से वापस लाने के दो दिन बाद ही एनसीबी ने 'आपरेशन व्हाइट' के तहत मुंबई में एक ड्रग्स तस्कर सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 1745 करोड़ रुपये की उच्च गुणवत्ता वाली 349 किलोग्राम कोकेन जब्त की है। विदेश में छिपे ड्रग्स तस्करों को लाने के लिए एनसीबी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर 'आपरेशन ग्लोबल हंट' चला रही है। वहीं देश के भीतर सक्रिय ड्रग्स तस्कर सिंडिकेट को खत्म करने के लिए 'आपरेशन व्हाइट' शुरू किया है।

एनसीबी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, सलीम डोला के साथ ही कई ड्रग्स तस्करों की पहचान की गई है, जो विदेश में रहकर भारत में ड्रग्स की तस्करी करते हैं। उनमें आसिफ इकबाल मेमन, हाजरा इकबाल मेमन, जुनैद इकबाल मेमन, हरमीत सिंह, प्रदीप सिंह, परदेमजीत ढलीवाल, सन्नी गोसाल्विस, सन्नी कालरा, जसविंदर सिंह, तैशान बिशनोई, हली सलीम और संदीप धुनिया शामिल हैं। जसविंदर सिंह व सन्नी कालरा फिलहाल दुबई पुलिस की गिरफ्त में हैं और उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरे देशों में रह रहे ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए एनसीबी इंटरपोल सहित अन्य एजेंसियों के साथ तालमेल के साथ काम कर रही है और उनके बीच रीयल टाइम सूचनाओं का आदान-प्रदान हो रहा है।

दूसरी ओर हर वर्ष औसतन 200 से 300 किलोग्राम कोकेन की बरामदगी को देखते हुए मुंबई में एक साथ 349 किलोग्राम की जब्ती की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके लिए छह महीने तक खुफिया जानकारी जुटाई गई और दो चरणों में छापेमारी कर पूरी खेप बरामद की गई। पहले एक वेयरहाउस के पास खड़ी कार से 136 किलोग्राम और फिर दूसरी जगह एक गोदाम से 213 किलोग्राम कोकेन बरामद की गई।

कोकेन को विदेश से आयातित मशीनों के खोखले हिस्से में छिपाकर लाया गया था। एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि एक-एक किलोग्राम के प्रत्येक पैकेट को नौ परतों वाले अलग-अलग प्रकार की पालीथीन में पैक किया गया था। वेयरहाउस में इन मशीनों से कोकेन निकालने के बाद उसे मुंबई के अलग-अलग हिस्सों में आपूर्ति किया जाना था। कोकेन की बरामदगी के बाद अब उससे जुड़े ड्रग्स सरगनाओं की तलाश की जा रही है।

हम नशीले पदार्थों के कार्टेल को बेरहमी से कुचलने के लिए पूरी तरह संकल्पबद्ध हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों के रिंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकेन जब्त की है, जिसकी कीमत 1745 करोड़ रुपये है। यह बाटम-टु-टाप अप्रोच का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें एजेंसी ने एक छोटी खेप को ट्रेस करते हुए एक विशाल नेटवर्क को पकड़ा। टीम एनसीबी को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई।

- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

प्रेरक उपलब्धि

देख, सुन और बोल नहीं सकती सारकाइडोसिस से पीड़ित छात्रा सारा मोइन, आइएससी (12वीं) में 98.7 प्रतिशत अंक प्राप्त कर किया कालेज टाप

रिपोर्ट कार्ड में गूंजा मूक-बधिर सारा की सफलता का शोर

जागरण संवाददाता, लखनऊ

कहते हैं अगर हौसले बुलंद हों तो शारीरिक अक्षमताएं भी मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकतीं। लखनऊ की बेटी सारा मोइन ने इस कहावत को सच्चाई में बदल दिया है। दृष्टिबाधित और मूकबधिर सारा काउंसिल फार द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (सीआइएससीई) की आइएससी (12वीं) परीक्षा में 98.7 प्रतिशत अंक हासिल कर न केवल अपने कालेज की टापर बनी, बल्कि उसने उन लाखों लोगों के लिए मिसाल पेश की है, जो मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं। सारा ने हाईस्कूल परीक्षा में भी 95 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे।

सारा की सफलता की कहानी जितनी प्रेरक है, उतनी ही भावुक भी। महज छह वर्ष की उम्र में वह 'सारकाइडोसिस' नामक बीमारी की चपेट में आ गई थी। तब वह नर्सरी में थी। इस बीमारी ने धीरे-धीरे देखने, सुनने और बोलने की शक्ति छीन ली। लेकिन उसकी शिक्षिका मां जूली हामिद ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी की हथेली को ही स्लेट बना दिया। वह बेटी की हथेली पर उंगलियों से अक्षर बनाती थीं। सारा उन स्पर्शों को महसूस कर शब्दों और वाक्यों को समझती थी। यह 'स्पर्श-संवाद' ही उसकी शिक्षा का आधार बना। स्कूल के शिक्षकों और स्टाफ ने सारा का भरपूर ध्यान रखा और कभी उसके अंदर हीनभावना नहीं आने दी।

सारा मोइन। फाइल

सारा मोइन का रिपोर्ट कार्ड

भूगोल	100/100
मास मीडिया	100/100
अंग्रेजी	98/100
इतिहास	97/100
मनोविज्ञान	96/100

आर्बिट रीडर ने बनाया आत्मनिर्भर

सारा की इस असाधारण यात्रा में आधुनिक तकनीक 'आर्बिट रीडर' का विशेष योगदान रहा। भारतीय संचार निगम लि. (बीएसएनएल) में कार्यरत पिता मोइन अहमद ने बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए छह वर्ष पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। उसी समय उन्होंने गुजरात से विशेष ब्रेल डिवाइस आर्बिट रीडर मंगवाया था। यह डिवाइस एक पोर्टेबल लैपटाप की तरह काम करता है, जो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ने और लिखने की सुविधा देता है। इस डिवाइस के जरिये सारा पढ़ाई करती रही।

मिलिए लखनऊ की हेलेन केलर से ...

क्राइस्ट चर्च कालेज के प्रधानाचार्य राकेश चत्री और शिक्षक सलमान बताते हैं कि सारा का जज्बा विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका हेलेन केलर की याद दिलाता है। हेलेन भी श्रव्य-दृष्टिबाधित थीं। कालेज में सारा के दोस्त और शिक्षक उसे 'हेलेन केलर' के नाम से बुलाते हैं। उसने नर्सरी से इंटर तक की पढ़ाई इसी कालेज से की है। सारा का सपना आइएएस अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना है। उनके माता-पिता और शिक्षकों को पूरा भरोसा है कि जिस बेटी ने अंधकार और सूनापन को अपनी मेहनत से मात दी है, वह प्रशासनिक सेवा में भी सफलता का कीर्तिमान रचेगी।

3 मई से 5 मई तक तीन दिन बादल छाए रहेंगे। गर्जन वाले बादल बनने, बिजली चमकने, 40 से 50 किमी प्रति घंटे की तेज रफ्तार हवा चलने और हल्की वर्षा होने का भी पूर्वानुमान है। इसके असर से तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी।

www.jagran.com
राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार, 2 मई, 2026

आज का मौसम

शनिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धूप भी खिली रहेगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
1 मई	39.0	25.0
2 मई	37.0	26.0
नोएडा		
1 मई	36.0	20.1
2 मई	36.0	26.0
गुरुग्राम		
1 मई	39.0	25.0
2 मई	39.0	25.0

डिग्री सेल्सियस में

न्यूज गैलरी

बिना पीयूसीसी वाले 15,000 वाहनों को नहीं मिला ईंधन

नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए बगैर पीयूसी (प्रदूषण नियंत्रण) प्रमाणपत्र वाले 15,000 से अधिक वाहनों को पेट्रोल पंपों से 26 से 29 अप्रैल के बीच चार दिनों में बिना ईंधन के वापस भेज दिया गया। सरकार ने 22 अप्रैल को दोहराया था कि वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा, जिस पर अमल करते हुए यह कदम उठाया गया। (राब्यू)

जामिया में प्रदर्शन पर पाकिस्तान की टिप्पणी को किया खारिज

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (जेकेएसए) ने दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुए हालिया विरोध प्रदर्शनों पर पाकिस्तान की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक नासिर खुएहामी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए इसे भारत के आंतरिक मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप करार दिया। चेतावनी दी कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नासिर ने कहा कि पाकिस्तान जामिया की ऐतिहासिक विरासत को गलत तरीके से प्रस्तुत करने की कुचेष्टा कर रहा है। (जासं)

कच्छा बनियान गिरोह ने दंपती को बंधक बना लूटा

नई दिल्ली : कच्छा बनियान गिरोह ने मालवीय नगर थाना क्षेत्र स्थित सर्वोदय एन्क्लेव में शुक्रवार तड़के एक घर में घुसकर लूटपाट की। बदमाश पार्क में लगे पेड़ के सहारे बालकनी में चढ़े। दंपती के जाग जाने पर उन्हें बंधक बनाकर एक कमरे में बंद कर दिया। (जासं)

अनुराग ठाकुर व प्रवेश वर्मा के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2020 में दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुरव प्रवेश वर्मा द्वारा दिए गए कथित नफरती भाषणों के खिलाफ कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता। भाजपा सांसद ठाकुर पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि वर्मा दिल्ली सरकार में मंत्री हैं।

29 अप्रैल को नफरती भाषणों से संबंधित याचिकाओं के एक समूह पर सुनाए गए निर्णय में जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने माकपा के नेताओं वृंदा करात और के.एम. तिवारी द्वारा दायर याचिका पर भी विचार किया, जिन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के जून, 2022 के निर्णय को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने करात और तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने ठाकुर और वर्मा के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के लिए ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में नोट किया कि हाई कोर्ट ने स्वतंत्र रूप से आकलन करते हुए कहा कि भाषणों

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

नफरती भाषण के मामले में दोनों भाजपा नेताओं को सुप्रीम कोर्ट से क्लीनचिट

में कोई संज्ञेय अपराध का गठन नहीं होता है। साथ ही ये बयान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं थे और ना ही उन्होंने हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था को भड़काया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "रिकार्ड पर प्रस्तुत सामग्री में कथित भाषण 26 फरवरी, 2020 की स्थिति रिपोर्ट और निचली अदालतों द्वारा दर्ज किए गए कारण शामिल हैं, पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता।" माकपा नेताओं ने दावा किया कि 27 जनवरी, 2020 को ठाकुर ने रिठाला में एक रैली में कथित रूप से नफरती भाषण दिया। उन्होंने दावा किया कि 28 जनवरी, 2020 को वर्मा ने भड़काऊ भाषण दिए।

नोएडा एयरपोर्ट से 15 जून से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें

जागरण संवाददाता, जेवर

- एयरपोर्ट से पहली उड़ान होगी इंडिगो एयरलाइंस की
- 10 मई से टिकट की बुकिंग शुरू होने की संभावना

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सफर का सपना 15 जून को पूरा होने जा रहा है। दिल्ली सहित एनसीआर व पूरे उत्तर भारत के यात्रियों को नोएडा एयरपोर्ट से यात्री सुविधाओं के अलावा कार्गो की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पहली उड़ान इंडिगो एयरलाइंस की होगी। एयरपोर्ट पर यात्री सेवाएं शुरू होने से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगातार बढ़ रहे दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। 10 मई से टिकट की बुकिंग शुरू होने की संभावना है। पहली उड़ान कहां के लिए होगी और किस समय होगी इसको लेकर एयरलाइन जल्द ही घोषणा करेंगी।

एयरपोर्ट को डीजीसीए (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) ने छह मार्च को एयरोड्रम लाइसेंस और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने नोएडा एयरपोर्ट के सुरक्षा प्रोग्राम को सोमवार को अपनी स्वीकृति दी थी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (यापल) एयरलाइन कंपनियों के साथ जल्द बैठक करते हुए एयरपोर्ट से प्रमुख शहरों के

यात्री सेवाओं के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैयार यात्री टर्मिनल बिल्डिंग। जागरण

लिए टिकट की दरें घोषित करेगी। इसके बाद टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. के नोडल अफसर शैलेंद्र भाटिया का कहना है कि 10 मई के आसपास टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही उन शहरों के नाम भी घोषित हो जाएंगे, जहां के लिए एयरपोर्ट से यात्री सेवा उपलब्ध होगी।

उड़ानों की समय सारणी जल्द होगी घोषित : यापल की तरफ से बताया गया कि व्यावसायिक सेवाओं के शुभारंभ से पहले एयरपोर्ट का सुरक्षा ढांचा और संचालन प्रक्रियाएं नियमों के अनुरूप पूरी कर ली गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस नोएडा एयरपोर्ट से पहली उड़ान संचालित करेगी। उसी दिन आकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी उड़ान भरेंगी। एयरपोर्ट से 50 शहरों के लिए शुरू होने वाली उड़ानों की समय सारणी, गंतव्यों और यात्री सेवाओं के बारे में जल्द वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध होगी।

एमसीडी क्षेत्र में 'स्व-गणना' का आगाज, एलजी व सीएम ने भरी अपनी जानकारी

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: देश की डिजिटल प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में 'जनगणना 2027' के तहत सेल्फ-एन्यूमरेशन (स्व-गणना) प्रक्रिया की एमसीडी क्षेत्र में औपचारिक शुरुआत की गई। अभियान के पहले दिन उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता व परिवहन मंत्री डा. पंकज सिंह ने पोर्टल पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज कर इस नागरिक अभियान की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बताते हुए कहा कि स्व-गणना से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों की गोपनीयता भी सुनिश्चित रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब नागरिक स्वयं अपनी जानकारी देते हैं, तो त्रुटियों की संभावना न्यूनतम हो जाती है। बता दें कि एनडीएमसी व कैंट इलाकों में खुद से गिनती करने का काम पहले ही पूरा हो चुका है, जहां अब गणना करने वालों द्वारा घरों की लिस्ट बनाने व घरों की गिनती करने का काम चल रहा है।

भविष्य की दिल्ली में घर के समीप ही होगा दफ्तर और मनोरंजन

डीडीए ने शुरू की 10 'मेगा प्रोजेक्ट' की तैयारी

इस नई पहल का मकसद दिल्लीवालों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना भी है

संजीव गुप्ता • जागरण

नई दिल्ली: भविष्य में दिल्ली की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदलने वाली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (टीओडी) नीति में बड़े बदलावों को अधिसूचित करने के बाद जमीन पर काम शुरू कर दिया है। इस नई पहल का मकसद दिल्लीवालों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना और एक ही छत के नीचे घर, दफ्तर और मनोरंजन की सुविधाएं देना है। पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा में पहले से ही एक टीओडी प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इसे नए नियमों के साथ विस्तार दिया जा सकता है।

छोटे प्लाट, बड़े सपने : अब 2000 वर्ग मीटर पर भी बनेगा 'मिनी टाउनशिप' : डीडीए ने टीओडी प्रोजेक्ट के लिए 10,000 वर्ग मीटर जमीन की पुरानी शर्त को खत्म कर दिया गया है। अब मात्र 2000 वर्ग मीटर के प्लाट पर भी टीओडी प्रोजेक्ट शुरू हो सकेंगे। इससे दिल्ली के घने इलाकों में भी आधुनिक बिल्डिंग बन पाएंगी। जहां दफ्तर, घर के साथ मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं होंगी।

सिंगल विंडो क्लीयरेंस : 60 दिनों में 'ग्रीन सिग्नल' : अब नक्शा पास कराने या मंजूरी लेने के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। डीडीए उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक हाई-लेवल 'टीओडी कमेटी' बनेगी, जो 60 दिनों के भीतर प्रोजेक्ट को मंजूरी देगी। इसमें जल बोर्ड, एमसीडी और अन्य विभागों के अधिकारी एक साथ बैठेंगे।

नई नीति में मध्यम वर्ग पर खास ध्यान : कुल फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) का 65 प्रतिशत हिस्सा अब आवासीय होगा (पहले यह 50 प्रतिशत था)। ये फ्लैट्स 100 वर्ग मीटर से कम कार्पेट एरिया के होंगे, जिससे इनकी कीमत मध्यम वर्ग के बजट में रहे।

डेवलपर के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का एकमुश्त टीओडी चार्ज तय किया गया है। इसमें पानी, सीवर, लैंड यूज चार्ज और लीज होल्ड से फ्री होल्ड जैसे सभी मुख्य खर्चे शामिल होंगे, जिससे प्रोजेक्ट की लागत और जटिलता कम होगी।

कड़कड़डूमा स्थित डीडीए का टीओडी टावर। सौजन्य : डीडीए

इन 10 प्राइम लोकेशनों पर हो सकती है नजर, शुरू होगा काम

- **द्वारका सेक्टर-21 :** यह एयरपोर्ट लाइन व आने वाले बड़े बस टर्मिनल का केंद्र है।
- **सराय काले खां :** यहां मेट्रो, नमो भारत और बस अड्डा तीनों का संगम है।
- **नेहरू प्लेस :** यह पहले से ही एक बिजनेस हब है।
- **पीरागढ़ी :** यह पश्चिमी दिल्ली का प्रमुख ट्रांजिट प्वाइंट है।
- **आजादपुर :** यहां तीन मेट्रो लाइनों का इंटरचेंज व मंडी के पास जमीन प्राथमिकता में होगी।
- **कश्मीरी गेट के आसपास :** ऐतिहासिक और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में छोटे स्तर के टीओडी प्रोजेक्ट की प्रबल संभावना है।
- **रोहिणी और रिठाला :** यहां डीडीए के पास पहले से ही काफी खाली जमीन उपलब्ध है।
- **मयूर विहार फेज-1 :** नोएडा व दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी पाइंट।
- **आनंद विहार :** यह यूपी और दिल्ली का प्रवेश द्वार है, जहाँ रेलवे और मेट्रो का बड़ा नेटवर्क है।

इस नीति से न केवल दिल्ली में जमीन का सही उपयोग होगा, बल्कि प्रदूषण में कमी आएगी व सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ेगा। यह नीति बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने व लोगों के सपने को पूरा करने में मील का पत्थर है। **-एन सरवन कुमार, उपाध्यक्ष, डीडीए**

राजधानी के गांव में बढ़ेगी विकास की रफ्तार, 48 गांव शहरीकृत घोषित

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- डीडीए ने फरवरी में दिल्ली नगर निगम को भेजा था प्रस्ताव, मिली मंजूरी

राजधानी में एमसीडी ने डीडीए के प्रस्ताव पर 48 गांवों को शहीरकृत घोषित करने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद से इन गांव में अब नियोजित विकास हो सकेगा। सड़क, बिजली, पानी, सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार इस निर्णय के बाद किया जा सकेगा। डीडीए ने फरवरी में यह प्रस्ताव निगम को भेजा था। एमसीडी के अनुसार, जिन 48 गांवों के शहरीकरण की मंजूरी दी गई है उसमें बाहरी उत्तरी, उत्तरी, उत्तर-पूर्वी, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी जिलों में जहां भविष्य में व्यापक विकास योजनाएं लागू की जानी हैं।

एमसीडी की स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा ने कहा कि यह निर्णय केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि जमीन पर दिखने वाले विकास की दिशा में ठोस पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो गांव व्यवहार में शहरी स्वरूप ले चुके हैं, उन्हें औपचारिक रूप से शहरी दर्जा देना आवश्यक था। उन्होंने बताया कि इस मंजूरी के बाद निगम सदन में यह प्रस्ताव पारित किया जाएगा। फिर अधिसूचना के लिए दिल्ली सरकार को भेजा जाएगा। इसके बाद इसके लागू होने से संबंधित क्षेत्रों में सड़क, सीवर, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और कूड़ा प्रबंधन जैसी सुविधाओं को प्रभावी व जवाबदेह तरीके से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गांव शहरीकृत होने के यह होते हैं लाभ

- डीएलआर एक्ट से मुक्ति : शहरीकरण के बाद उस गांव पर 'दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम' (डीएलआर) लागू नहीं रहता। इसका मतलब है कि ग्रामीण अब अपनी जमीन का उपयोग खेती के अलावा अन्य कामों (जैसे मकान बनाना या व्यावसायिक उपयोग) के लिए बिना किसी कानूनी अड़चन के कर सकते हैं।
- लैंड पूलिंग पालिसी : शहरीकृत होने के बाद ही गांव की जमीन 'लैंड पूलिंग पालिसी' के दायरे में आती है। इसमें ग्रामीण अपनी जमीन सरकार को विकास के लिए दे सकते हैं और बदले में उन्हें विकसित जमीन (पार्क, अस्पताल, चौड़ी सड़कों वाली) का हिस्सा मिलता है, जिससे जमीन की कीमत कई गुना बढ़ जाती है।
- बुनियादी ढांचे का विकास : शहरी घोषित होने पर उस क्षेत्र की जिम्मेदारी नगर निगम एमसीडी या डीडीए के पास चली जाती है। इससे गांव में पक्की सड़कें, सीवर सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, पार्क और बेहतर साफ-सफाई की सुविधाएं सुनिश्चित होती हैं।
- नक्शा पास कराने की सुविधा : ग्रामीण अब अपने घर या दुकान बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर नक्शा ले आउट प्लान पास करा सकते हैं, जिससे उनका निर्माण कानूनी रूप से वैध हो जाता है।

कांस्टेबल निकला 50 लाख की लूट का मास्टरमाइंड, सात आरोपित दबोचे

- दिल्ली पुलिस की 5वीं बटालियन में तैनात था आरोपित कांस्टेबल समय सिंह मीणा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपित कांस्टेबल समय सिंह मीणा और बरामद की गई नकदी व मोबाइल। सौ. दिल्ली पुलिस >>

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

राजधानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पुलिसकर्मी ने ही खाकी को दागदार कर दिया। दिल्ली पुलिस की पांचवीं बटालियन में तैनात 2009 बैच के कांस्टेबल समय सिंह मीणा ने गिरोह तैयार किया, जिसने 50 लाख की लूट को अंजाम दिया और पैसे आपस में बांट लिए।

उत्तरी जिला पुलिस ने कांस्टेबल समेत गिरोह के सात आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से लूट की रकम से खरीदे पांच मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की गई है। जांच में पता चला कि आरोपित समय सिंह मीणा पहले भी चांदनी महल, पश्चिम विहार और सराय रोहिल्ला थाना क्षेत्र में लूट व डकैती की तीन वारदात कर चुका है। उत्तरी जिले के उपायुक्त राजा बांठिया के मुताबिक, 31 मार्च को शिकायतकर्ता राणा महेपाल सिंह ने बताया था कि वह साथी मोहन लाल के साथ कीर्ति नगर से परिचित विक्की से 50.37 लाख लेने के बाद एक आटो से चांदनी चौक जा रहे थे। जैसे ही वे रेलवे अंडरपास पर पहुंचे, तभी स्कूटी व बाइक सवार चार बदमाशों ने आटो रोका व थप्पड़ मारते हुए मोहन लाल से पैसों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

एक बार में एक महीने से अधिक की फीस के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे निजी स्कूल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- निदेशालय ने आदेश जारी कर एडवांस वसूली पर लगाई रोक
- आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर होगी सख्त कार्रवाई

राजधानी में निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर जारी मनमानी पर आखिरकार शिक्षा निदेशालय ने सख्ती दिखाई है। निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि अब कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों को एक बार में एक महीने से अधिक की फीस जमा कराने के लिए बाध्य नहीं कर सकेगा। निदेशालय ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें स्कूल की मान्यता रद करने या प्रबंधन अपने हाथ में लेने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है।

निदेशालय को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई निजी स्कूल अभिभावकों को दो महीने या तिमाही आधार पर फीस देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। निदेशालय ने माना कि यह प्रथा न केवल अनुचित है, बल्कि इससे खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। आदेश के तहत स्कूल अभिभावकों को एडवांस फीस देने के लिए बाध्य कर सकेंगे। नए आदेश के तहत यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अभिभावक अपनी सुविधा से एक से अधिक महीनों की फीस एक साथ जमा करना चाहता है, तो स्कूल उसे मना नहीं करेगा, लेकिन इसके लिए किसी तरह का दबाव या शर्त नहीं रखी जा सकती। यह व्यवस्था पहले से लागू निर्देशों के अनुरूप है। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के आधार पर वर्ष 2019 में भी मासिक फीस प्रणाली लागू करने को कहा गया था, लेकिन इसके बावजूद कुछ स्कूल नियमों की अनदेखी कर रहे थे।

स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को सात कार्यदिवस के भीतर अपने नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करें और आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करें, ताकि सभी अभिभावकों को इसकी जानकारी मिल सके।

राजधानी में बनेंगे आधुनिक लेबर चौक और श्रमिक सेवा केंद्र : रेखा गुप्ता

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- सीएम ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कीं कई घोषणाएं, कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ
- सामूहिक विवाह योजना की घोषणा की, प्रत्येक पात्र जोड़े को मिलेगी आर्थिक सहायता

अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस पर मुखर्जी नगर क्षेत्र धीरपुर में श्रमिक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं कीं। आधुनिक लेबर चौक, श्रमिक सेवा केंद्र और सामूहिक विवाह योजना शुरू करने की घोषणा की। साथ ही दिल्ली के पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए पंजीकरण शुल्क 20 रुपये और नवीनीकरण शुल्क पांच रुपये को पूरी तरह माफ करने का एलान किया।

श्रमिक सेवा केंद्रों के जरिये मोबाइल वैन सीधे श्रमिकों तक सेवाएं पहुंचाएंगी। इन केंद्रों पर पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, शौचालय, प्राथमिक उपचार, रोजगार के अवसर, कौशल विकास और शिकायत निवारण जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक पात्र जोड़े को आर्थिक सहायता दी जाएगी। विवाह समारोह के लिए टेंट, भोजन व अन्य का खर्च सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 'रिकाग्निशन आफ प्रायर लर्निंग' (आरपीएल) योजना के तहत कौशल विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धीरपुर में संत निरंकारी मंडल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 1000 निर्माण श्रमिकों को सेफ्टी किट बांटी।

अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस पर धीरपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान महिला श्रमिकों को सेफ्टी किट भेंट करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उनके साथ हैं श्रम मंत्री कपिल मिश्रा सौ. दिल्ली सरकार

खुल रहीं परतें

'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' में 38 करोड़ के घोटाला मामले की जांच में खुल रहीं हैं परतें, नए खाते खोलने के बजाय पुराने खाते में ट्रांसफर हुए पैसे, कई छात्रों के नाम दो या अधिक संस्थानों में दर्ज

नियमों को ताक पर रख कई इंस्टीट्यूट को दिया गया था कोचिंग का ठेका

राकेश कुमार सिंह • जागरण

नई दिल्ली: पूर्ववर्ती आप सरकार की गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने की योजना में 38 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है संबंधित विभाग द्वारा किए फर्जीवाड़े की परतें खुलती जा रही हैं।

2017 में कैबिनेट के निर्णय के बाद 9 जनवरी 2018 को 'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' शुरू की गई थी। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के छात्रों को कोचिंग देने के लिए शुरू में आठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया था।

इसके लिए 16 इंस्टीट्यूट ने आवेदन भरा। इंस्टीट्यूट के लिए तीन साल का पढ़ाने का अनुभव होने का मानदंड तय था, लेकिन जिन आठ इंस्टीट्यूट का चयन किया गया उनमें कई के पास एक साल का भी अनुभव नहीं था। यानी नियमों को ताख पर रखकर कोचिंग का ठेका दे दिया गया था।

प्रतीकात्मक

क्या है मामला

'जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना' के नाम पर केजरीवाल सरकार ने मेधावी छात्र छात्राओं को मुफ्त कोचिंग सुविधा देने की शुरुआत की थी, लेकिन करोड़ों का घोटाला करने के कारण योजना ही बंद हो गई दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) ने दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले नौ आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

सत्यापन किया जा रहा प्रमाण पत्र, हो सकती हैं कई और गिरफ्तारियां

संस्थानों द्वारा एससी-एसटी कल्याण विभाग को प्रस्तुत आय और जाति प्रमाण पत्र का राजस्व अधिकारियों से सत्यापन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना के तहत दिल्ली के 46 बड़े इंस्टीट्यूट से सरकार का विद्यार्थियों को पढ़ाने का समझौता हुआ था, जिनमें अभी केवल चार इंस्टीट्यूट के निदेशक गिरफ्तार हुए हैं। पता चला कि कई इंस्टीट्यूट ने फर्जी आय प्रमाण पत्र बनवाकर एसडीएम की मुहर लगाकर छात्रों को इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का फर्जी दावा पेश किया था।

पहले चरण में लगभग 5,000 छात्र नामांकित हुए थे। कोचिंग फीस और छात्रों के लिए वजीफा, एससी और एसटी कल्याण विभाग द्वारा कोचिंग संस्थानों को भुगतान किया जाना था। थोड़े अंतराल के बाद 2019-20 में इस योजना को कुछ संशोधनों के साथ फिर से शुरू किया गया, जिसमें एसटी, ओबीसी, ईडब्लूएस श्रेणियों को भी शामिल किया। इस बार 38 और संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया। इसमें भी जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। दोनों चरणों में लगभग 22,000 छात्र नामांकित हुए थे।

प्रवेश से संबंधित फर्जी दस्तावेज बनाए गए : जांच में पता चला कि इन संस्थानों ने इस योजना के तहत करीब 38 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। सभी संस्थानों के लिए इस योजना हेतु नया बैंक खाता अनिवार्य था, लेकिन इसका बिल्कुल पालन नहीं किया गया। संबंधित विभाग द्वारा इंस्टीट्यूट के पुराने खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए जो फर्जीवाड़े को दर्शाता है। सरकार ने इसकी कभी जांच नहीं की कि आखिर पैसे किसके खाते में भेजे जा रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया कि सरकारी खजाने से धन प्राप्त करने के लिए संस्थानों द्वारा प्रस्तुत छात्रों की सूची में कई नाम दो या दो से अधिक संस्थानों की सूची में शामिल में थे।

बेटी को पीटने से रोका तो दामाद ने ससुर की चाकू से वार कर हत्या की

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- पहली मंजिल से घसीटकर गली में ले गया, चाकू से किए वार
- पति के साथ मायके आई थी बेटी, आरोपित फरार

सीमापुरी इलाके में दामाद ने अपने ही ससुर की चाकू से कई वार कर हत्या कर दी। ससुर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने दामाद को बेटी को पीटने से रोका था। आरोप है युवक पहली मंजिल से ससुर को घसीटते हुए नीचे लाया और गली में उन पर चाकू से वार किए। मृतक की पहचान रामजतन (50) के रूप में हुई है। सीमापुरी थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। जीटीबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सौंप दिया गया है।

रामजतन परिवार के साथ सीमापुरी में रहते थे। वह वाहन धोने का काम करते थे। बृहस्पतिवार को उनकी बेटी नंदनी पति संदीप के साथ मायके आई हुई थी। रात को किसी बात पर संदीप पत्नी को पीटने लगा। रामजतन ने बेटी को बचाने की कोशिश की। इस पर संदीप भड़क गया और ससुर को थप्पड़ मारा और फिर उन्हें पहली मंजिल से घसीटते हुए नीचे गली में ले गया। इसके बाद उसने चाकू से उन पर कई वार कर किए, जिससे रामजतन गंभीर रूप से घायल हो गए। पकड़े जाने के डर से आरोपित फरार हो गया। लहूलुहान रामजतन को जीटीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीण का कहना है कि सीमापुरी थाना पुलिस ने हत्या केस दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

60 ईडी के मामलों में अभी तक अदालत का फैसला आया है, जिनमें 56 मामले में दोष सिद्धि के बाद सजा सुनाई गई है। इस तरह से ईडी 94 प्रतिशत सजा दर हासिल करने में सफल रही है।

गुजरात में देश का पहला बैरियर मुक्त टोल प्लाजा शुरू

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

- गुजरात में दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे पर अत्याधुनिक टोलिंग सिस्टम का गडकरी ने किया शुभारंभ
- साल के अंत तक देशभर के 1050 टोल प्लाजा होंगे बैरियर मुक्त, सुगम होगा आवागमन
- मल्टी लेन फ्री फ्लो तकनीक बेरोकटोक आवागमन का बनी आधार

नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा पर अब आपको न तो रुकना पड़ेगा और न ही लंबी कतार के झंझट में पड़ना पड़ेगा। फर्राटा भरते हुए आप वहां से निकल सकेंगे। टोल स्वतः कट जाएगा। भारत का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा दिल्ली-मुंबई नेशनल हाईवे (एनएच-48) पर सूरत और भरूच के बीच चौरियासी खंड पर चालू हो गया है। शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शुभारंभ किया। यह देशभर में पूरी तरह से स्वचालित टोल संग्रह की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वैसे भी सरकार का लक्ष्य इस साल के अंत तक देश के 1,050 से अधिक टोल प्लाजाओं को एआइ-आधारित बैरियर-फ्री सिस्टम में बदलना है।

यह प्रणाली मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) तकनीक पर आधारित है और इसे एनएचएआइ द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजना के तहत टोलिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को अत्याधुनिक बनाने के लिए लागू किया गया है।

एनएचएआइ ने शुक्रवार को सूरत के चौरियासी टोल प्लाजा पर भारत की पहली बैरियर मुक्त टोलिंग प्रणाली शुरू की। एएनआइ

प्रेट्र के अनुसार, गडकरी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा- 'यह अत्याधुनिक प्रणाली वाहनों को रोके बिना निर्बाध टोल संग्रह की सुविधा प्रदान करती है। इसमें आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) और फास्टैग जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है।' गडकरी ने कहा कि बैरियर रहित टोलिंग नागरिकों के लिए 'ईज आफ लिविंग' को बढ़ाएगी और देशभर में माल और लाजिस्टिक्स के तेज और अधिक कुशल परिवहन को सक्षम करके 'ईज आफ डूईंग बिजनेस ' को बढ़ावा देगी। भारत में 2026 के अंत तक टोल संग्रह पूरी तरह से बैरियर-फ्री होने की उम्मीद है।

80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गुजर सकेंगे वैरियर फ्री टोल प्लाजा से

1,500 करोड़ रुपये के ईंधन की सालाना वचत होगी वैरियर फ्री टोलिंग से

6,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा वेहतर कार्य-कुशलता से

बैरियर फ्री टोल प्लाजा के फायदे

- टोल पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति, यात्रा का समय काफी कम होगा
- वाहन की ईंधन खपत में बचत होगी, साथ ही वाहन उत्सर्जन में भी कमी आएगी
- टोल संचालन में मानव हस्तक्षेप कम से कम होगा, इससे विवाद भी कम होंगे

यूं काम करता है बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम : आइएएनएस के अनुसार, एनएचएआइ के मुख्य परिचालन अधिकारी एआर चित्रांसी ने कहा कि इस बैरियर लेस टोलिंग को मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग भी कहा जाता है। इसमें वाहन को रोकने की आवश्यकता नहीं है। वाहन गैंट्री के नीचे से गुजरेगा और उसका टोल काटा जाएगा। उन्होंने बताया कि टोल शुल्क स्वचालित रूप से एएनपीआर तकनीक और फास्टैग एकीकरण के संयोजन का इस्तेमाल करके काटा जाता है। हाई रिजोल्यूशन कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं, जबकि आरएफआइडी सेंसर फास्टैग विवरण पढ़ते हैं और इससे बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सीधे शुल्क की वसूली होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसमें सड़क के ऊपर लगे फ्रेम में सेंसर और कैमरे लगे होते हैं। ये चलती हुई गाड़ियों की पहचान कर लेते हैं और ट्रैफिक को रोके बिना अपने आप पैसे काट लेते हैं। यदि किसी वाहन में सक्रिय फास्टैग नहीं है तो सिस्टम इसे नंबर प्लेट के माध्यम से पहचानता है और भुगतान के लिए वाहन मालिक को ई-नोटिस भेजता है।

अब 30 जून तक अपने सहायक के साथ रेलवे की परीक्षा दे सकेंगे दिव्यांग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- रेलवे बोर्ड ने सभी जोन और आरआरबी को भेजा पत्र

रेलवे की नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। रेल मंत्रालय ने भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांगों के लिए होने वाले बड़े बदलावों को फिलहाल 30 जून तक के लिए टाल दिया है। इस कारण 30 जून से पहले होने वाली रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट (सीबीटी-वन) परीक्षा, असिस्टेंट लोको पायलट और जूनियर इंजीनियर परीक्षा में दिव्यांग अपने सहायक के साथ दे सकेंगे।

रेलवे ने भर्ती परीक्षा को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए नए नियम बनाए हैं। इसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपना 'स्क्राइब' (सहायक) लाने के बजाय परीक्षा एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए 'स्क्राइब पूल' से मदद लेनी होगी। यानी रेलवे के पैनल से सहायक चुनना होगा। तकनीक और विशेष साफ्टवेयर का उपयोग करना होगा। नई व्यवस्था में एजेंसी द्वारा सहायक देने का प्रविधान है, जिसकी तैयारी अभी पूरी नहीं है।

भर्ती परीक्षा में फिलहाल पुरानी व्यवस्था जारी।

अभ्यर्थियों को मिलने वाला प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय पहले की तरह जारी रहेगा। देशभर के परीक्षा केंद्रों पर डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर और सरकारी 'स्क्राइब पूल' तैयार करने में समय लग रहा है, जिसके चलते 30 जून तक नया नियम लागू नहीं होगा। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक थंगजाम राकेश कुमार द्वारा 30 अप्रैल को जारी यह आदेश सभी जोनल रेलवे और भर्ती बोर्ड को भेज दिया गया है। सीपीआरओ शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि बोर्ड के निर्देश के क्रम में दिव्यांगों को परीक्षा में पूर्ववत सुविधा मिलती रहेगी।

एक साल में ईडी ने की 81 हजार करोड़ से अधिक की संपत्ति जब्त

संप्रग सरकार के दौरान हर साल औसतन 575 करोड़ रुपये की संपत्ति ही होती थी जब्त

वित्तीय अपराध के कैंसर का देश से सफाया कर रही है ईडी : वित्त राज्यमंत्री

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

अवैध तरीके से बनाई संपत्तियों की जब्ती और पीड़ितों तक उनकी वापसी की दिशा में ईडी को बड़ी सफलता मिल रही है। ईडी अभी तक अवैध तरीके से बनाई गई दो लाख 36 हजार 17 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है, जिनमें अकेले पिछले वित्तीय वर्ष में 81,422 करोड़ की संपत्तियों को जब्त किया गया। इसके साथ ही ईडी को 63,142 करोड़ रुपये की संपत्ति को घोटालेबाजों से जब्त कर पीड़ितों को वापस करने में भी सफलता मिली है। प्रवर्तन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ये आंकड़े देते हुए निदेशक राहुल नवीन ने कहा कि आतंकी फंडिंग और क्रिप्टो फ्राड जैसे मामले एजेंसी की प्राथमिकता में हैं।

प्रवर्तन दिवस के अवसर पर शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में आंकड़े जारी करते केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और ईडी के निदेशक राहुल नवीन। प्रेट्र

काली कमाई से बनाई गई संपत्तियों के पुराने आंकड़ों से तुलना में ईडी की सफलता काफी बड़ी है। ईडी ने इसके पहले 2024-25 के वित्तीय वर्ष में 30,036 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। उसकी तुलना में 2025-26 में 170 प्रतिशत अधिक संपत्तियां जब्त की गईं। उसके पहले 2014 से 2024 तक ईडी हर साल औसतन 11,938 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करती रही थी। वहीं संप्रग सरकार के दौरान 2004 से 2014 तक औसतन हर साल केवल 575 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई थी। अवैध संपत्तियों को जब्त करने में ईडी की सफलता की सराहना करते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोपों को सिरे खारिज कर दिया। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईडी को ताकत देश से वित्तीय अपराध के कैंसर को साफ करने के लिए दी है, विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए नहीं।

संपत्ति जब्त करने के साथ ही ईडी को पीड़ितों को इन्हें वापस दिलाने में भी बड़ी सफलता मिल रही है। घोटाले में गवाएं गए 63,142 करोड़ की संपत्ति वापस पाने वालों में उदयपुर के 200 घरों के खरीददार भी शामिल हैं। इसके साथ ही पर्ल्स ग्रुप के आवासीय योजनाओं में निवेश करने वालों को 15,581 करोड़ रुपये वापस किये गए। ईडी निदेशक के अनुसार अभी तक ईडी के 60 मामलों में अदालत का फैसला आया है, जिनमें 56 मामले में दोष सिद्धि के बाद सजा सुनाई गई है। इस तरह से ईडी 94 प्रतिशत सजा दर हासिल करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि 2400 मामलों में अदालत में सुनवाई चल रही है और जल्द ही अदालत का फैसला आने की उम्मीद है।

धर्मार्थ ट्रस्ट की जांच किए बगैर टैक्स छूट नहीं दे सकता आइटीएटी

विनीत त्रिपाठी, जागरण • नई दिल्ली

- आइटीएटी के आदेश को रद करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, फिर से जांच का दिया निर्देश
- आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ राजस्व विभाग ने दायर की थी अपील

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम निर्णय में कहा कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आइटीएटी) किसी धर्मार्थ ट्रस्ट की गतिविधियों की उचित जांच किए बिना उसे सीधे कर छूट का लाभ नहीं दे सकता। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता व न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ ने कहा कि आइटीएटी ने एक कानूनी गलती की है। न्यायाधिकरण ने मामले को ठीक से जांचने के लिए वापस भेजने के बजाय सीधे रजिस्ट्रेशन दे दिया। पीठ ने कहा कि यह नजरिया पहली नजर में गलत है।

रजिस्ट्रेशन के समय कमिश्नर को ट्रस्ट की असलियत की जांच करनी चाहिए, न कि यह देखना चाहिए कि ट्रस्ट की कमाई चैरिटेबल या धार्मिक कामों पर खर्च हो रही है या नहीं। साथ ही पीठ ने निर्देश दिया कि यह प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी की जाए।

अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए सुकून एसपी फाउंडेशन नामक धर्मार्थ ट्रस्ट को पंजीकरण और अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश देने संबंधी आइटीएटी के आदेश को रद कर दिया। ट्रस्ट ने आयकर अधिनियम की धारा 12ए(एक)(एसी)(तीन) के तहत पंजीकरण और धारा 80जी के तहत अनुमोदन के लिए आवेदन किया था।

किसी धर्मार्थ ट्रस्ट को अपनी आय पर आयकर से छूट प्राप्त करने के लिए धारा 12ए/12एबी के तहत पंजीकरण आवश्यक है।

आइटीएटी ने ट्रस्ट की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि आयुक्त का आदेश अस्पष्ट था और ट्रस्ट की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद थी। इसके बाद आइटीएटी ने पंजीकरण और अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश दिया। निर्देश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आयकर कमिश्नर (छूट) ने इस आधार पर आवेदन खारिज कर दिया कि ट्रस्ट लाभार्थियों की जानकारी और ट्रस्ट की गतिविधियों की असलियत साबित करने को सहायक दस्तावेज नहीं दे सका था।

एनसीईआरटी युद्धस्तर पर कक्षा नौ की पुस्तकों की कर रही छपाई

नई दिल्ली, प्रेट्र : एनसीईआरटी ने शुक्रवार को कहा कि वह कक्षा नौ की नई पाठ्यपुस्तकों की छपाई युद्धस्तर पर कर रहा है और आपूर्ति को सामान्य किया जा रहा है। उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 पर आधारित कक्षा नौ की पाठ्यपुस्तकों का एक नया सेट जारी किया है। उसने दो सप्ताह पहले ही अपनी वेबसाइट पर कक्षा नौ की नई पाठ्यपुस्तकों के डिजिटल संस्करण मुफ्त में उपलब्ध करा दिए हैं।

बयान में कहा गया है, इन पुस्तकों की छपाई युद्धस्तर पर की जा रही है और इन्हें पूरे देश में वितरित किया जा रहा है। पाठ्यपुस्तकों की बहुत बड़ी संख्या की आवश्यकता के कारण, आपूर्ति और मांग में अस्थायी अंतर है। एनसीईआरटी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और इस कमी को दूर करने के लिए काम कर रहा है। पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति को सामान्य किया जा रहा है। नई किताबों के उपलब्ध नहीं होने से जुड़ी शिकायतों पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार मंत्रालय व एनसीईआरटी के अधिकारियों के साथ उपलब्धता, वितरण और छपाई आदि को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही निर्देश दिया कि प्रत्येक छात्र तक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए।

विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने नेपाल के राजदूत से की विदाई मुलाकात

- दोनों द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की

विदेश सचिव विक्रम मिसरी शुक्रवार को नई दिल्ली में नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा से विदाई भेंट की। एएनआइ >>

नई दिल्ली, एएनआइ : विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारत से जा रहे नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा से विदाई मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने दो देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की।

विदेश मंत्रालय के एक्स पर किए एक पोस्ट के अनुसार, बैठक में विदेश सचिव ने नेपाल के साथ बहुआयामी संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को फिर से पुष्ट किया। उन्होंने शर्मा द्वारा भारत-नेपाल संबंधों को आगे बढ़ाने में किए गए योगदान की भी सराहना की। पोस्ट में कहा गया, 'विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने नेपाल के राजदूत डा. शंकर प्रसाद शर्मा का विदाई काल के लिए स्वागत किया।

विदेश सचिव ने नेपाल के साथ बहुआयामी संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट किया और इस प्रयास में डा. शर्मा के योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

शंकर प्रसाद शर्मा ने भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में कार्य करने से पहले नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग में बतौर उपाध्यक्ष भी काम किया। एक अनुभवी अर्थशास्त्री और राजनयिक शर्मा ने 2009 से 2014 तक अमेरिका में नेपाल के राजदूत के रूप में भी कार्य किया है।

स्वदेशी महेंद्रगिरि युद्धपोत शक्तिशाली हथियार प्रणाली के साथ नौसेना में शामिल

- नीलगिरि-क्लास का छठा खुफिया युद्धपोत एमडीएसएल मुंबई में सौंपा गया
- ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल,सोनार और स्टेल्थ तकनीक से है लैस

नई दिल्ली, प्रेट्र : स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरि को भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। नीलगिरि-क्लास (प्रोजेक्ट 17ए) का यह छठा खुफिया युद्धपोत 30 अप्रैल को मझगांव डाक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल), मुंबई में सौंपा गया। यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, अत्याधुनिक सोनार और स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जो दुश्मन के रडार को चकमा दे सकता है। अधिकारियों के अनुसार, यह डिलीवरी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में एक 'महत्वपूर्ण मील का पत्थर' है।

रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, 'प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट बहुउपयोगी मिशन प्लेटफार्म है, जिन्हें समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अत्याधुनिक फ्रिगेट नौसेना के डिजाइन, स्टेल्थ, अग्निशक्ति, स्वचालन और जीवित रहने की क्षमता में गुणात्मक छलांग को दर्शाता है और युद्धपोत निर्माण में आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।' अधिकारियों ने कहा कि महेंद्रगिरि (यार्ड 12654) इस श्रेणी का चौथा जहाज है जो एमडीएसएल में निर्मित किया गया है। पी17ए फ्रिगेट स्वदेशी जहाज 'पीढ़ीगत छलांग' को दर्शाते हैं। पी17ए जहाजों को पी17 (शिवालिक-क्लास) की तुलना में एक उन्नत हथियार और सेंसर सूट से लैस किया गया है। ये जहाज संयुक्त डीजल या गैस (सीओडीओजी) प्रोपल्शन प्लांट से कांफिगर किए गए हैं, जिसमें एक डीजल इंजन और एक गैस टरबाइन शामिल है जो प्रत्येक शाफ्ट पर कंट्रोल करने योग्य पिच प्रोपेलर (सीपीपी) को संचालित करता है और एक अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम (आइपीएमएस) है।

स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को गुरुवार को मुंबई में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। प्रेट्र

महेंद्रगिरि छठा पी17ए जहाज है जिसे नौसेना को 17 महीनों से कम समय में सौंपा गया। 75 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री के साथ प्रोजेक्ट में एमडीएसएल में 200 से अधिक एमएसएमई शामिल हैं।

चमोली की नीती घाटी में पहली बार बजी मोबाइल की घंटी

विनय बहुगुणा • जागरण

- चीन सीमा से लगे नीती, क्यूंगलूनग और बमल्स गांव को मिली सुविधा

श्रीनगर(गढ़वाल): चीन सीमा से लगे जनपद चमोली के सबसे दुर्गम क्षेत्र नीती घाटी में पहली बार मोबाइल की घंटी बजने के साथ फोर-जी इंटरनेट सेवा भी शुरू हो गई है। चमोली के नीती, क्यूंगलूनग और बमल्स गांव में बीएसएनएल के तीन मोबाइल टावर का 27 अप्रैल से विधिवत संचालन शुरू हो गया है। इससे स्थानीय लोगों को संचार सुविधा मिलने के साथ सामरिक सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी।

भारत सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत उत्तराखंड के चीन व नेपाल सीमा से लगे 91 गांवों में ढांचागत विकास, संचार संपर्क और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। पहले चरण में चीन सीमा से लगे 51 गांवों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें जनपद चमोली की नीती घाटी भी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य देश की द्वितीय रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के साथ ही उनके जीवन स्तर को सुधारकर पलायन रोकना है। योजना के तहत भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने नीती घाटी के नीती, क्यूंगलूनग और बमल्स गांव में मोबाइल टावर स्थापित कर संचालन शुरू कर दिया है। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम की चुनौतियों के बीच बीएसएनएल ने एक वर्ष से भी कम समय में इस क्षेत्र को संचार सेवा से जोड़ने में सफलता पाई है। यही नहीं, यहां गांवों में रहने वाले स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, आपदा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। बीएसएनएल ने वी-सेट भी लगाया है, जिससे पूरे क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क साइट्स आन-एयर हो गई हैं। भारत संचार निगम के उप महाप्रबंधक जय सिंह चौहान ने बताया कि क्षेत्र में मोबाइल सेवा के साथ फोर-जी इंटरनेट सेवा शुरू होने से यहां तैनात सेना के साथ स्थानीय लोगों और पर्यटकों को लाभ मिलेगा। अब, नीती घाटी से देश के किसी भी कोने में आडियो व वीडियो काल की जा सकेगी।

संजीदा पहल

बीआइएस ने तय किए मानक, बैसाखी से लेकर ब्रेल साइन तक होंगे बेहतर, भारतीय उत्पाद नए मानकों से अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप ही बनेंगे

अशक्त लोगों के लिए चलना-फिरना होगा और आसान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

भारत मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने सहायक उपकरणों में बदलाव के जरिये लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें आसान करने का प्रयास किया है। इसके लिए नए मानक तय किए गए हैं, जो खास तौर पर दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और ऐसे लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिन्हें चलने-फिरने या देखने में परेशानी होती है। इन उपकरणों में बैसाखी, चलने की छड़ी, मल्टी-लेग स्टिक, व्हीलचेयर के लिए पोर्टेबल रैंप, टैक्टाइल मैप और ब्रेल साइनेज शामिल हैं। इन्हें ज्यादा सुरक्षित, टिकाऊ एवं उपयोग में आसान बनाकर जरूरतमंद लोगों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य है।

दरअसल, देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और कई लोग उम्र या बीमारी के कारण सहायक उपकरणों पर निर्भर हैं। ऐसे में सुरक्षित एवं भरोसेमंद उत्पाद उनकी जीवन गुणवत्ता सुधार सकते हैं। बाजार में मिलने वाले ऐसे उपकरणों की गुणवत्ता एक समान नहीं होती है। कई लोग सस्ती छड़ी या बैसाखी खरीद लेते हैं, जो जल्दी खराब हो जाती हैं या शरीर के अनुरूप नहीं होते। इससे संतुलन बिगड़ने और गिरने का खतरा बना रहता है। नए मानकों के लागू होने के बाद इन उपकरणों की मजबूती, डिजाइन और संतुलन बेहतर होगा। इससे उपयोग करने वालों को अधिक भरोसा मिलेगा। नए मानकों से बड़ा लाभ यह होगा कि भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय स्तर के अनुरूप बनेंगे। इससे देश के निर्माता बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद तैयार कर सकेंगे और उन्हें वैश्विक बाजार में भी जगह मिलेगी। साथ ही, शोध और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा।

छह उपकरणों के मानक जारी : बीआइएस ने छह उपकरणों के मानक जारी किए हैं। इनमें कोहनी वाली बैसाखी, सामान्य चलने की छड़ी के अतिरिक्त तीन या उससे अधिक पैरों वाली छड़ी के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इनमें सुरक्षा, आराम, पकड़, वजन और टिकाऊ बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। निर्माता को यह भी बताना होगा कि उत्पाद का सही उपयोग कैसे किया जाए। व्हीलचेयर उपयोग करने वालों के लिए पोर्टेबल रैंप का मानक तय किया गया है। इससे सीढ़ियों, इमारतों और सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच आसान होगी। यह रैंप न केवल दिव्यांगजनों बल्कि बच्चों की गाड़ी या सामान ले जाने वालों के लिए भी उपयोगी होंगे। इससे आवाजाही में बड़ी सहूलियत मिलेगी।

अशक्तों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने को उठाए कदम।

टैक्टाइल गाइड मैप के नए नियम बताए गए हैं

दृष्टिबाधित लोगों के लिए भी अहम कदम उठाए गए हैं। टैक्टाइल गाइड मैप के नए नियम बताए गए हैं, ताकि वे इमारतों, पार्कों और परिवहन केंद्रों को आसानी से समझ सकें। इसी तरह ब्रेल साइनेज के तय मानक से लिखावट का आकार, दूरी और सामग्री एक जैसी होगी। इसका फायदा ब्रेल पढ़ने वाले लोगों को मिलेगा। सभी मानक बड़े राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा हैं। इनका संबंध उन जरूरी सहायक उत्पादों की सूची से है, जिसे देश में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि दिव्यांगजन और बुजुर्ग बिना किसी बाधा के अपनी जिंदगी जी सकें। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे मानकों की जरूरत समय के साथ बढ़ी है।

कह कर रहेंगे माधव जोशी

215 सीटें मिली थीं तृणमूल कांग्रेस को 2021 के बंगाल विस चुनाव में। वहीं भाजपा ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी।

बंगाल में आज 15 बूथों पर पुनर्मतदान

चुनाव आयोग का फैसला, मगराहाट पश्चिम के 11 और डायमंड हार्बर के चार बूथ शामिल

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

बंगाल के मगराहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 15 मतदान केंद्रों पर दो मई को दोबारा मतदान होगा। चुनाव आयोग ने इन मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद इन मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। इनमें मगराहाट पश्चिम हाट के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के चार मतदान केंद्र शामिल हैं। इसके साथ ही आयोग ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होने के संकेत दिए हैं। यहां कई मतदान केंद्रों पर ईवीएम में टेप लगाए जाने की शिकायतें मिली थीं। माना जा रहा है कि देर रात तक इस पर भी फैसला हो सकता है।

चुनाव आयोग ने यह फैसला बंगाल में दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर 29 अप्रैल को हुए चुनाव के दौरान चार विधानसभा सीटों के करीब 77 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद किया है। इनमें फाल्टा के सबसे अधिक 32, डायमंड हार्बर के 29, मगराहाट के 13 व बजबज विधानसभा के तीन मतदान केंद्रों से जुडी शिकायतें शामिल थीं। आयोग ने इन सभी शिकायतों की जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने मगराहाट और डायमंड हार्बर के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए हैं। वहीं फाल्टा की जांच रिपोर्ट न मिलने से वहां दोबारा मतदान कराने को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। आयोग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, बंगाल के जिन मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान होना है, वह दो मई को हो जाएगा। इस दौरान मतदाता सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान कर सकेंगे। चुनाव आयोग के पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बंगाल में भी बाकी चारों राज्यों के साथ चार मई को मतगणना होगी। आयोग इसे लेकर बंगाल सहित सभी राज्यों में तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटा है।

बांकुड़ा में शुक्रवार को मीडिया को जानकारी देते बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल। एएनआइ

ममता के चार घंटे तक स्ट्रांग रूम पर रूकने पर आयोग को भेजी गई रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- कोलकाता पुलिस ने सात स्ट्रांग रूम केंद्रों के 200 मीटर दायरे में लागू की धारा 163

कोलकाता में मतगणना से पहले स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासत तेज हो गई है। दक्षिण कोलकाता के शेखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम में गुरुवार रात हुए घटनाक्रम पर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) ने चुनाव आयोग को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी है, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की वहां चार घंटे मौजूदगी और वहां की गतिविधियों का पूरा ब्योरा शामिल है।

भवानीपुर विधानसभा सीट के ईवीएम इसी स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखे गए हैं। नियमों के तहत प्रत्याशी या उनके अधिकृत एजेंट को निरीक्षण का अधिकार है और इसी आधार पर ममता बनर्जी वहां पहुंचीं। करीब चार घंटे तक उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। बाहर आने के बाद ममता ने पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि वोट लूटने की कोशिश हुई तो वह जान देकर भी लड़ेंगी। उन्होंने ईवीएम और पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए। भाजपा प्रत्याशी सुवेंदु अधिकारी के चुनाव एजेंट भी वहां मौजूद रहकर निगरानी करते रहे।

प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती: घटनाक्रम के बाद प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। कोलकाता पुलिस ने शहर के सात स्ट्रांग रूम केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है। इसके तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन, रैली या जुलूस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

पुलिस का कहना है कि यह कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और ईवीएम व बैलेट पेपर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। वहीं, चुनाव आयोग अब डीईओ की रिपोर्ट के आधार पर यह तय करेगा कि शेखावत मेमोरियल में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं।

जनादेश के बाद शांति की तैयारी, बंगाल में गणना बाद हिंसा रोकने को आयोग सख्त

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता

- बहुस्तरीय सुरक्षा, 700 कंपनियों की तैनाती और 24 घंटे निगरानी से सुरक्षित माहौल का भरोसा
- आयोग ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर 1800 345 0008 और ई-मेल wbfreeandfairpolls@gmail.com

बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद अब निर्वाचन आयोग का पूरा ध्यान मतगणना और उसके बाद की शांति सुनिश्चित करने पर है। 'शांतिपूर्ण जनादेश' के संकल्प के साथ, भारत निर्वाचन आयोग ने बंगाल में कानून का शासन बनाए रखने के लिए अब तक की सबसे सख्त घेराबंदी तैयार की है।

चुनाव के बाद होने वाली संभावित हिंसा को जड़ से खत्म करने के लिए आयोग ने राज्य भर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 700 कंपनियां तैनात रखने का निर्णय लिया है। यह बल न केवल मतगणना केंद्रों पर तैनात रहेगा, बल्कि राज्य के सुदूर और संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त कर अराजक तत्वों पर नकेल कसेगा।

त्रिस्तरीय घेरा और डिजिटल अभेद्य दुर्ग : मतगणना केंद्रों की सुरक्षा को 'किले' में तब्दील कर दिया गया है। यहां त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जहां केवल क्यूआर कोड आधारित पहचान पत्र वाले अधिकृत कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। डिजिटल एक्सेस कंट्रोल के जरिए अवांछित प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है।

चौबीस घंटे सीधी निगरानी : आयोग ने एक 24×7 कमांड हब स्थापित किया है, जो सीधे दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से जुड़ा है। किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में यह हब तत्काल रिस्पांस टीम को सक्रिय करेगा। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रशासनिक और पुलिस मशीनरी अभी भी आयोग के कड़े नियंत्रण में है।

कड़ी चेतावनी और नागरिक भागीदारी : आयोग ने कड़ा संदेश दिया है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही, नागरिकों की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर 1800 345 0008 और ईमेल wbfreeandfairpolls@gmail.com जारी किया गया है,जहां सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। बंगाल अब एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में अपने नए जनादेश का स्वागत करने को तैयार है।

कोलकाता के भवानीपुर स्थित शेखावत मेमोरियल स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम के पास गुरुवार रात हुई गहमागहमी के बाद शुक्रवार को पहरा देते सुरक्षाकर्मी। प्रेट्र

विजय के पार्टी कार्यालय को आग के हवाले कर भागे आरोपित

विजय। फाइल

तिरुचिरापल्ली, प्रेट्र : तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में विजय की पार्टी टीवीके के चुनावी कार्यालय को अज्ञात लोगों ने आग के हवाले कर दिया। यह घटना शुक्रवार तड़के हुई। पुलिस के अनुसार, आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और केवल कार्यालय के प्रवेश द्वार पर लगी छप्परनुमा छत जलकर क्षतिग्रस्त हुई। यह कार्यालय श्रीरंगम विधानसभा क्षेत्र के लिए पार्टी का कैंपेन सेंटर था। घटना ऐसे समय में हुई है जब 23 अप्रैल को मतदान हो चुका है और चार मई को मतगणना होनी है, जिससे मामले को लेकर संवेदनशीलता बढ़ गई है।

ईवीएम नहीं, चुनाव आयोग और एसआइआर की आड़ में की जा रही वोट चोरी: उमर

राज्य ब्यूरो, जागरण • श्रीनगर

- जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा की ममता की अपील का किया समर्थन
- कहा कि मतदाता सूचियों से मतदाताओं को हटाकर चुनाव में धांधली करने की कोशिश की गई है, सावधान रहना होगा

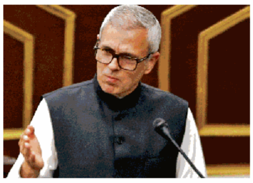
उमर अब्दुल्ला। फाइल

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को बंगाल में मतगणना से पहले ईवीएम की सुरक्षा करने की ममता बनर्जी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि आज वोट चोरी ईवीएम के जरिए नहीं बल्कि चुनाव आयोग के जरिए और एसआइआर की आड़ में की जा रही है। उन्होंने बंगाल के चुनाव ने एक नई चुनौती पेश की है और अगर एसआइआर चुनाव परिणाम को प्रभावित करता है तो यह हम सभी के लिए खतरनाक होगा। उमर बोले, उन्होंने मतदाता सूचियों से मतदाताओं को हटाकर चुनाव में धांधली करने की कोशिश की है और हमें इससे सावधान रहना होगा।

दक्षिण कश्मीर के पांपोर में पत्रकारों के साथ बातचीत में गुरुवार रात कोलकाता के भवानीपुर में एक स्ट्रांग रूम के बाहर हुए हाई वोल्टेज ड्रामा से जुड़े सवाल पर उमर ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि मैं चुनाव से पहले धांधली को स्वीकार नहीं करता और मतदान के बाद ईवीएम की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जब बैलेट बाक्स होते थे, तब भी हम ऐसा ही करते थे, हम अपने लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर रखते थे। इसलिए, लोगों को स्ट्रांग रूम के बाहर रखना ममता बनर्जी का अधिकार था, और उन्होंने ऐसा किया। इसमें कुछ गलत नहीं है।

उन्होंने बंगाल के चुनाव संबंधी एक्जिट पोल पर कहा कि अब तक कौन सा एक्जिट पोल सही रहा है? पांच साल पहले जब बंगाल में चुनाव हुए थे, तो सभी एक्जिट पोल ने भाजपा की जीत और उसके बंगाल में सत्तासीन होने के दावे किए थे। लेकिन नतीजा क्या था? हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, नतीजे सोमवार को आएंगे। उमर ने चुटकी लेते हुए कहा कि एक एजेंसी ने अपना एक्जिट पोल सार्वजनिक करने से मना कर दिया है, क्योंकि शायद उसे नतीजे पसंद नहीं आए हैं।

मतगणना में केंद्रीय कर्मियों की तैनाती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची तृणमूल

- आयोग के निर्देश के खिलाफ तृणमूल की याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कर दिया था खारिज

नई दिल्ली, प्रेट्र : बंगाल विधानसभा चुनाव में डाले गए मतों की गिनती के लिए केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शनिवार को सुनवाई करने वाला है। याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जोयमाल्या बागची की पीठ सुनवाई करेगी।

इससे पहले गुरुवार को आयोग के निर्देश के खिलाफ तृणमूल की याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार और पीएसयू के कर्मचारियों को मतगणना पर्यवेक्षक और सहायक नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले में कुछ भी गैरकानूनी नहीं है।

हाई कोर्ट में तृणमूल ने बंगाल के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 30 अप्रैल को जारी एक पत्र को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कम-से-कम एक मतगणना पर्यवेक्षक या सहायक केंद्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी होना चाहिए। तृणमूल के वकील ने तर्क दिया था कि यह पत्र अधिकार क्षेत्र से बाहर जारी किया गया था और मात्र आशंका पर आधारित था। दूसरी तरफ चुनाव आयोग के वकील का कहना था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 आयोग को कार्य सौंपने की अनुमति देता है और यह निर्देश वैध है।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

भाजपा और तृणमूल ने काउंटिंग एजेंटों व नेताओं की बुलाई बैठक

राज्य ब्यूरो, जागरण • कोलकाता: मतगणना को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चा रही हैं। एक तरफ भाजपा तो दूसरी ओर तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी शनिवार को सभी काउंटिंग एजेंटों की बैठक बुलाई। भाजपा ने तो गुरुवार को ही बंगाल में तैनात अन्य राज्यों के प्रभारी नेताओं को कोलकाता पहुंचने का निर्देश दे दिया था। शनिवार को बंगाल चुनाव के प्रभारी व अन्य केंद्रीय नेता इस बैठक में मैजूद रहेंगे। वहीं शुक्रवार को अभिषेक ने भी पार्टी नेताओं व काउंटिंग एजेंटों की वर्चुअल बैठक बुलाई है।

यह बैठक सीटों के एजेंटों को ध्यान में रखकर आयोजित की जा रही है। इसमें एजेंटों को मतगणना के दौरान पालन किए जाने वाले नियम, प्रक्रियाएं और सतर्कता के बिंदुओं पर विस्तार से निर्देश दिए जाएंगे। तृणमूल पहले भी संगठनात्मक मजबूती के लिए वर्चुअल बैठकों का सहारा लेती रही है। वोटर लिस्ट संशोधन से लेकर प्रचार अभियान तक, विभिन्न चरणों में ऐसी बैठकें हुई हैं।

भ्रष्टाचार में रेवाड़ी की निवर्तमान चेयरपर्सन पूनम भाजपा से निष्कासित

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी

- 13 अन्य लोग छह साल के लिए किए गए निष्कासित
- पूनम यादव के पति बलजीत यादव भी पार्टी से निकाले गए

निकाय चुनाव के बीच भाजपा ने बागी होकर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी निवर्तमान चेयरपर्सन पूनम यादव और उनके पति बलजीत यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही बागी होकर धारूहेड़ा में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कंवर सिंह यादव को भी छह साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

भाजपा के अनुसार, नगर निकाय चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के चलते 15 लोगों को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी ने यह कार्रवाई उन लोगों पर की है, जो भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने इस बार रेवाड़ी नगर परिषद में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की समर्थित विनीता पीपल को चेयरपर्सन की टिकट दी है, जबकि 2020 के निकाय चुनाव में राव समर्थित ही पूनम यादव को टिकट देकर चुनाव जिताया गया था, लेकिन पूनम यादव के कार्यकाल के दौरान हुए भ्रष्टाचार के चलते इस बार पार्टी के भीतर ही नहीं बल्कि आम लोगों में भी काफी विरोध था।

कंवर सिंह

कंवर सिंह

100 करोड़ रुपये के पार पहुंचा छत्तीसगढ़ में भारतमाला मुआवजा घोटाला

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • रायपुर

- **11** जिलों में फैली जांच, तत्कालीन कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और कारोबारी ईडी के रडार पर

भारतमाला परियोजना से संबंधित मुआवजा घोटाले का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में अब तक घोटाले की राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक पहुंच चुकी है, जबकि प्रारंभिक अनुमान 35 से 40 करोड़ रुपये का था। जांच का दायरा प्रदेश के 11 से अधिक जिलों तक फैल चुका है। जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि जमीन अधिग्रहण की गोपनीय जानकारी पहले ही कारोबारियों और दलालों को उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद सस्ते दामों पर जमीन खरीदकर राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेरफेर कर मुआवजा कई गुना बढ़ाया गया। इस मामले में जिलों के तत्कालीन कलेक्टर और राजस्व अधिकारी जांच के घेरे में हैं। स्वीकृति के बदले मोटा कमीशन लेने के आरोप भी हैं।

गुरुवार को ईडी ने रायपुर, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा समेत 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिलासपुर में सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के यहां से 17 किलो सोना, तीन करोड़ के हीरे के आभूषण और नकदी मिलने की चर्चा है। अंबिकापुर के कांग्रेसी नेता के करीबी से 50 लाख से अधिक की रकम मिलने की भी जानकारी है। ईओडब्ल्यू पहले ही इस मामले में 10 आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है और चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है।

धमतरी के एक कारोबारी द्वारा किसानों के नाम पर जमीन खरीदकर करीब 100 करोड़ रुपये का मुआवजा दिलाने का मामला भी गरमाया हुआ है। संदिग्धों के मोबाइल फोन खंगाले जा रहे हैं। इन डिजिटल साक्ष्यों से आने वाले दिनों में नौकरशाही और राजनीति के कई बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। वहीं रायपुर, धमतरी, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, दुर्ग और राजनांदगांव में ईडी की जांच जारी है।

भारतमाला परियोजना की एक सड़क। फाइल

अपराधियों की तलाश में रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना असंवैधानिक : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

- कहा, स्वजन को ढाल बनाना या थाने बुलाना अंग्रेजों के जमाने का तरीका
- आज किसी व्यक्ति का पता लगाने के लिए उच्च तकनीकी साधन मौजूद

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी फरार अपराधी को पकड़ने के लिए उसके निर्दोष रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना अनुचित ही नहीं, असंवैधानिक भी है। अपराधियों की तलाश के लिए स्वजन को ढाल बनाना या उन्हें थाने बुलाकर मानसिक दबाव डालना अंग्रेजों के जमाने का पुराना तरीका है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे के हिसाब से उचित नहीं है। कोर्ट ने पुलिस को भविष्य में याची के घर दबिश देने या उन्हें किसी भी तरह से परेशान करने से रोक दिया है।

कानपुर निवासी सेवानिवृत्त कैप्टन मंगल सिंह ने अदालत से सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उनके बेटे संदीप तोमर को पंजाब में हत्या मामले में दोषी करार दिया गया था। बेटा सजा सुनाए जाने के बाद से फरार चल रहा था। पंजाब पुलिस की सूचना पर स्थानीय कानपुर पुलिस ने संदीप की तलाश में उसके वृद्ध माता-पिता के घर पर न केवल छापेमारी की, बल्कि उन्हें बार-बार पुलिस चौकी और थाने बुलाकर प्रताड़ित भी किया। याची का तर्क था कि उन्होंने अपने बेटे की अनैतिक गतिविधियों के कारण उसे बहुत पहले ही अखबारों में विज्ञापन देकर बेदखल कर दिया था और अब उनका उससे कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर के उस व्यक्तिगत हलफनामे की आलोचना की, जिसमें कहा गया था कि याची ने अपने बेटे को बेदखल करने का कोई 'आधिकारिक प्रमाण पत्र' पेश नहीं दिया है।

गंगोत्री हाईवे को लेकर एनजीटी ने दिखाई सख्त, स्थायी समाधान पर दिया जोर

अंकुर अग्रवाल • जागरण

- बीआरओ को एक साल की डेडलाइन, ट्रीटमेंट प्लान की समीक्षा

देहरादून : चारधाम यात्रा की लाइफलाइन गंगोत्री हाईवे (एनएच-34) पर बार-बार हो रहे भूस्खलन और सुस्त मरम्मत कार्यों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने सख्त तेवर दिखाए हैं। ट्रिब्यूनल ने चेतावनी दी है कि अब 'कागजी दावे' नहीं, बल्कि जमीन पर नतीजे चाहिए, वह भी तय समयसीमा में। अब गंगोत्री हाईवे पर 'मरम्मत' नहीं, बल्कि 'स्थायी समाधान' चाहिए और समय पर होने चाहिए। एनजीटी ने गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे पुनर्स्थापन एवं संरक्षण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। एनजीटी ने उत्तराखंड में आने वाले एनएच-34 के हिस्से वाले मामले में सुनवाई की।

एनजीटी की प्रधान पीठ के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद ने सुनवाई के दौरान सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) से सीधे सवाल किए और उसकी प्रगति रिपोर्ट को परखा। बीआरओ ने हलफनामे में दावा किया कि बरेठी, नालूपानी, पोखुदेवता-मतली, जसकोट व गोजमर जैसे सबसे संवेदनशील भूस्खलन जोन अब उसके सीधे नियंत्रण में हैं और यहां काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। बीआरओ ने बताया कि 113.12 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें ढलान स्थिरीकरण, भूस्खलन उपचार व पर्यावरणीय पुनर्स्थापन का व्यापक खाका है। टेंडर प्रक्रिया जारी है और एजेंसी ने यह वादा किया है कि ठेका मिलते ही एक साल के भीतर पूरा काम खत्म कर दिया जाएगा। एनएच-34 पर उत्तरकाशी में बरेठी और नालूपानी जैसे क्षेत्र लंबे समय से 'भूस्खलन हाटस्पाट' बने हुए हैं। वर्षाकाल में सड़क बार-बार बंद होती है, जिससे यात्री घंटों फंसे रहते हैं। बीआरओ ने बताया कि इस बार डीपीआर में सिर्फ कंक्रीट समाधान नहीं, बल्कि जियो-जूट, लेमन ग्रास, वेटिवर जैसी जैव-इंजीनियरिंग तकनीकों को शामिल किया गया है, ताकि ढलानों को प्राकृतिक तरीके से मजबूत किया जा सके।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फाइल

मस्जिद में फंदे से लटका मिला मदरसा छात्र का शव

जासं, सुलतानपुर : मस्जिद में मदरसे के एक छात्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

जिले के तातोमुरैनी गांव निवासी नौशाद का पुत्र 14 वर्षीय रेहान मस्जिद के बगल में संचालित मदरसे में कक्षा छह का छात्र था। वह शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद घर गया था और दोपहर बाद वापस मदरसे लौट आया था। उसके घर से मदरसे की दूरी लगभग 500 मीटर बताई जा रही है। कुछ देर बाद उसका शव मस्जिद के भीतर छत के पंखे से रस्सी के सहारे लटका मिला। कोतवाल अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा। फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है।

खाता फ्रीज करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 50 हजार रुपये का हर्जाना

विधि संवाददाता, जागरण • लखनऊ

- हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी- बैंक ट्रस्टी है न कि जांच एजेंसी
- बैंकों की मनमानी कार्रवाई से प्रभावित होता है कारोबार

इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने बैंक खातों को मनमाने ढंग से फ्रीज करने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बैंक एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, न कि निगाह रखने वाली जांच एजेंसी के रूप में। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने एक खाते को बिना किसी उचित कारण के फ्रीज करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है।

खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में बैंक खाता किसी साइबर अपराध के कारण, जैसा कि इन दिनों प्रचलित है, फ्रीज नहीं किया गया है, बल्कि इस कारण फ्रीज किया गया है कि संबंधित बैंक स्वयं एक जांच एजेंसी में परिवर्तित हो गया है। बैंक यह तय नहीं कर सकता कि पैसा कहां से आया, जब तक कि पुलिस, ईडी या सीबीआइ जैसी संस्थाओं से कोई औपचारिक आदेश न मिले। न्यायालय ने कहा कि इन दिनों बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वर्तमान मामले में बैंक ने खाते को बिना किसी उचित कारण के फ्रीज किया। इस प्रकार की मनमानी कार्रवाई का प्रत्यक्ष प्रभाव में खाताधारक के दैनिक व्यावसायिक कार्य बाधित होते हैं, जिससे उसकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा तथा आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। याची फर्म की ओर से दलील दी गई कि फार्म मछली पालन की मशीनरी का व्यवसाय करती है। उसके बैंक खाते में 16 जनवरी 2026 को 23 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से जमा हुए थे, लेकिन बैंक ने इस आधार पर खाता फ्रीज कर दिया कि खाता खोलते समय याची फर्म ने अपनी वार्षिक आय सिर्फ 5.76 लाख रुपये बताई थी तो इससे अधिक की राशि उसके खाते में कैसे जमा हो गई। वहीं, बैंक की दलील थी कि यह एक संदिग्ध लेन-देन था और मनी लाड्रिंग एक्ट के प्रविधानों के तहत उसने कार्रवाई की है।

प्रतीकात्मक

342 एलपीजी वितरण केंद्रों पर तेल कंपनियों ने जुर्माना लगाया है और 73 के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। वहीं, अब तक 43,200 से अधिक पीएनजी कनेक्शन वालों ने अपने एलपीजी सिलिंडर छोड़ दिए हैं।

88 विधायकों ने रखा सरकार का 'मान', विश्वास प्रस्ताव पास, विपक्ष रहा गैरहाजिर

आप के सात राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब में विधायकों में फूट को विराम

विपक्ष की गैरहाजिरी पर बोले पंजाब के मुख्यमंत्री मान- अगर वे भी मौजूद होते तो दो-चार वोटें और मिल जाते

इनजीत सिंह मणकू • जागरण

चंडीगढ़ : आम आप के सात राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने के बाद पंजाब में आप सरकार के विधायकों में फूट की अटकलों को शुक्रवार को विराम लग गया। सरकार की ओर से मजदूर दिवस पर बुलाए गए विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव पर आप के 88 विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इसके बाद यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया।

सीएम की ओर से पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस व भाजपा के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। विपक्ष के तौर पर सिर्फ निर्दलीय विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह ही मौजूद थे, लेकिन वोटिंग के वक्त वह भी सदन से बाहर चले गए। 117 सीटों वाली

पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भगवंत मान सदन से बाहर आकर विक्ट्री साइन बनाते हुए। संजय घिल्डियाल

विधानसभा में आप के 94 विधायक हैं। पार्टी के छह विधायक विधानसभा में मौजूद नहीं थे। इनमें से मनजिंदर सिंह लालपुरा और दविंदर सिंह लाडी ढोस विदेश गए हुए हैं, जबकि एडीसी जसविंदर सिंह उपचाराधीन हैं। कुंवर विजय प्रताप सिंह पार्टी से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। विधानसभा ने पंजाब प्रिज़न्स एंड करेक्शनल सर्विसेज बिल-2026' और सोसाइटीज

विधानसभा में पेश विश्वास प्रस्ताव का मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित अन्य विधायक हाथ उठाकर सर्वसम्मति से समर्थन करते हुए। सौ. लोसंवि

रजिस्ट्रेशन (पंजाब संशोधन) विधेयक 2026 को भी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने सदन में विश्वास प्रस्ताव रखते हुए स्पष्ट किया कि राज्यसभा सदस्यों के प्रकरण से जोड़कर पिछले कुछ दिनों से सरकार को लेकर तरह-तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इन अटकलों का मकसद सिर्फ जनता और विधायकों के बीच भ्रम पैदा करना है। ऐसे में सरकार ने सदन के पटल पर विश्वास प्रस्ताव लाकर स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट करने का निर्णय लिया है, ताकि लोकतांत्रिक तरीके से बहुमत साबित किया जा सके।

उन्होंने कहा कि मेरा विश्वास तो इतना है कि यदि विपक्षी विधायक भी वोटिंग करने के लिए मौजूद होते तो हमें दो-चार अधिक ही वोट मिल जाते।

उन्होंने कहा कि वह इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद पांच मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के साथ होने वाली मुलाकात के दौरान उन्हें यह प्रस्ताव सौंपेंगे और मांग करेंगे कि दल-बदल कानून में संशोधन हो ताकि लोगों के फतवे की लूट न हो सके। उन्होंने कहा कि पंजाब देश का पहला राज्य बन जाएगा, जो इस कानून में बदलाव की मांग करेगा।

49.8 लाख एलपीजी सिलिंडर एक दिन में वितरित, 98 प्रतिशत आनलाइन बुकिंग

पश्चिम एशिया संकट

- सरकार ने कहा- देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य, घबराकर खरीदारी न करें
- अब तक 43,200 पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपने एलपीजी सिलिंडर लौटाए

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। फाइल

नई दिल्ली, आइएएनएस : सरकार का कहना है कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को 49.8 लाख एलपीजी सिलिंडर वितरित किए गए, जबकि 41.6 लाख सिलिंडरों के लिए नई बुकिंग की गई। पश्चिम एशिया संकट के चलते भले ही सप्लाई चेन में बाधा आई है मगर किसी वितरण केंद्र पर गैस की कमी नहीं है। आनलाइन घरेलू एलपीजी सिलिंडर बुकिंग 98 प्रतिशत तक बढ़ गई है। वितरक स्तर पर किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आथेंटिकेशन कोड बेस्ड डिलीवरी लगभग 93 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में छापेमारी जारी है। गुरुवार को देशभर में 2,300 से अधिक छापे मारे गए। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने 342 एलपीजी वितरण केंद्रों पर जुर्माना लगाया है और 73 के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 43,200 से अधिक पीएनजी कनेक्शन धारकों ने अपने एलपीजी सिलिंडर सरेंडर किए हैं। मंत्रालय पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की है कि वह पैनिक में आकर ईंधन की खरीद न करें। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल पर्याप्त हैं।

एएनआइ के अनुसार, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने कतर और बहरीन के लिए फ्लाइटें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। साथ ही 30 अप्रैल से यूएई, ओमान और सऊदी अरब के लिए अतिरिक्त उड़ानों की शुरुआत की गई है। उड़ानें प्रमुख भारतीय महानगरों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों से शुरू की गई हैं जिनमें दिल्ली, अमृतसर, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोझीकोड, कन्नूर, लखनऊ, मंगलुरु, मुंबई, तिरुचिरापल्ली, तिरुअनंतपुरम और वाराणसी शामिल हैं। एअर इंडिया एक्सप्रेस अल ऐन, अबू धाबी, दुबई, रस अल खैमाह, शारजाह, जेद्दाह, रियाद और मस्कट के लिए उड़ानें जारी रखेगा।

पश्चिम एशिया में फंसे नाविकों को जल्द वापस लाने की मांग

फारवर्ड सीमेन यूनियन आफ इंडिया (एफएसयूआइ) ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह पश्चिम एशिया क्षेत्र में फंसे भारतीय नाविकों को वापस लाने के प्रयासों को तेज करे। यह क्षेत्र इस समय अमेरिका-इजरायल सेनाओं और ईरान के बीच चल रही जंग का एक बड़ा केंद्र है। इसी बीच, हफ्तों की कठिनाइयों को झेलने के बाद लौटने वालों का एक नया जत्था मुंबई पहुंच गया है।

दिल्ली की सीएम पर अभद्र टिप्पणी करने वाला कांग्रेस नेता गिरफ्तार

जासं, जयपुर : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी करने के मामले में दर्ज एक मामले में अजमेर पुलिस ने एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। अजमेर में भाजपा की जिला इकाई के मीडिया संयोजक विक्रम सिंह की रिपोर्ट के आधार पर प्रारंभिक जांच के बाद कांग्रेस की आईटी सेल के शहर प्रभारी पीयूष सुराणा को गिरफ्तार किया गया है। गुरुवार को इंटरनेट मीडिया पर पीयूष की दिल्ली की सीएम के बारे में की गई पोस्ट प्रसारित होने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था।

गुरुवार शाम जब पुलिस सुराणा से थाने में पूछताछ कर रही थी। उसी दौरान भाजपा की कुछ महिला कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। दो महिला कार्यकर्ताओं ने सुराणा के चेहरे और कपड़ों पर काला रंग फेंक दिया। विवाद बढ़ा तो पुलिसकर्मियों ने भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं को समझाया। पुलिस की पूछताछ में सुराणा ने बताया कि उन्होंने गुरुवार सुबह विवादित टिप्पणी की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया था।

हिमंत के बयान से चिढ़ा बांग्लादेश, जताया विरोध

- असम के सीएम ने घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने को लेकर दिया था बयान
- कहा था-हम तब असम से उन घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं, जब वे खुद से नहीं जाते

ढाका, प्रेट्र: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के बयान से चिढ़े बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त पवन बाधे को बुलाकर अपना औपचारिक विरोध दर्ज कराया है।

यूएनबी न्यूज सर्विस ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि दक्षिण एशिया की महानिदेशक इशरत जहां ने बांग्लादेश के रुख से भारतीय राजनयिक को गुरुवार को अवगत कराया। हिमंत ने पिछले सप्ताह इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि अमस में 20 विदेशी नागरिकों को पकड़ा गया और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा, 'लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम तब असम से उन घुसपैठियों को बाहर निकालते हैं, जब वे खुद से नहीं जाते। ऐसे में हम लगातार इस कहावत को याद करते हैं। जैसे ये 20 अवैध बांग्लादेशी, जिन्हें कल रात धक्का देकर वापस भेज दिया गया।'

हिमंत बिस्वा सरमा

इशरत ने भारतीय राजनयिक से कहा कि इस तरह की टिप्पणियां दोनों देशों के बीच मित्रता के संबंधों की भावना को कमजोर करती हैं। उन्होंने इन टिप्पणियों को बांग्लादेश-भारत संबंधों के लिए अपमानजनक बताया और ढाका की नाखुशी को व्यक्त किया।

बता दें कि अगस्त, 2024 में गठित मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान भारत और बांग्लादेश के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। इस वर्ष फरवरी में संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जीत के बाद तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

बांग्लादेशी सांसद के बयान पर निशिकांत ने टीएमसी को घेरा

नई दिल्ली, एएनआइ: भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे पर बांग्लादेश के एक सांसद के बयान को लेकर तृणमूल कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि टीएमसी के मददगार धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। निशिकांत ने एक्स पर एक पोस्ट में बांग्लादेश के सांसद अख्तर हुसैन का एक वीडियो साझा किया है। उनके अनुसार, हुसैन ने कहा है कि अगर बंगाल की सत्ता में भाजपा आती है तो वह घुसपैठ को रोक देगी और बांग्लदेशी मुसलमानों को राज्य से बाहर कर देगी। तृणमूल कांग्रेस के मददगार धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में मतदान हुआ और चार मई को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार के दौरान घुसपैठ का मुद्दा गरमाया रहा। दूसरे चरण के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में भाजपा सरकार बनने की संभावना जताई गई है।

निशिकांत दुबे

एलपीजी की किल्लत की वजह से श्रमिक लौट रहे है गांव, आम गृहिणियां भी प्रभावित

प्रथम पृष्ठ से आगे

पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एलपीजी की किल्लत साफ दिख रही है। इससे न सिर्फ आम गृहिणी बल्कि उद्योग जगत भी प्रभावित हो रहा है। पिछले दिनों उद्योग चैंबर सीआइआइ की तरफ से यह मुद्दा सरकार के समक्ष उठाया गया था कि एलपीजी किल्लत की वजह से श्रमिक गांव लौट रहे हैं। मार्च 2026 में एलपीजी खपत 13 प्रतिशत घटी है, जबकि घरेलू सिलिंडर की बिक्री 8.1 प्रतिशत और कमर्शियल की 48 प्रतिशत घटी है। आयात प्रभावित होते देख सरकार ने रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल्स से एलपीजी उत्पादन की ओर मोड़ने का निर्देश दिया था, जिससे घरेलू उत्पादन 25-30 प्रतिशत बढ़कर मार्च में 14 लाख टन हो गया।

होर्मुज जलमार्ग बाधित होने से ईंधन पर बढ़ा दबाव : भारत अपनी जरूरत का 60 प्रतिशत एलपीजी आयात करता है, जिनमें से 90 प्रतिशत गैस होर्मुज मार्ग से आती है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण होर्मुज जल मार्ग बाधित होने से वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें करीब 50 प्रतिशत बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड 100-120 डालर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। इससे घरेलू बाजार पर दबाव बढ़ा है और कंपनियों को कीमतें संशोधित करनी पड़ रही हैं। सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी दी जाती है। पिछले वित्त वर्ष में 30 हजार करोड़ रुपये की एलपीजी सब्सिडी तेल कंपनियों को दी गई थी।

घरेलू एलपीजी को कमर्शियल सेक्टर में जाने से रोकना चुनौती : शुक्रवार की बढ़ोतरी के बाद कमर्शियल सिलिंडर और सब्सिडी वाले घरेलू सिलिंडर की कीमतों में करीब 2000 रुपये का अंतर हो गया है। इससे सब्सिडी वाले घरेलू सिलिंडरों की ब्लैक मार्केटिंग और कमर्शियल सेक्टर में डायवर्जन की आशंका गहरा गई है। केंद्र सरकार अब इसकी रोकथाम के लिए सक्रिय हो गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को देर शाम आइओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग और डायवर्जन रोकने के तत्काल कदमों पर चर्चा हुई।

एलपीजी का विकल्प नहीं बन सकती पीएनजी

चंडीगढ़ के शेफ हरपाल सिंह सोखी का कहना है कि होटल-रेस्तरां के लिए पीएनजी को एलपीजी का विकल्प कहा जा रहा है, लेकिन यह बहुत ज्यादा कामयाब नहीं है। कई इंडियन और चाइनीज डिश होती हैं, जिन्हें हाई फ्लेम पर ही तैयार किया जा सकता है, जबकि पीएनजी पाइपलाइन में इतना हाई प्रेशर नहीं होता है।

भाषा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं : फडणवीस

- महाराष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों को सीखनी चाहिए मराठी: सीएम
- कहा-महाराष्ट्र, एक सुधारवादी राज्य है, देश को दिशा भी प्रदान करता है

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के निवासियों को मराठी सीखने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन भाषा के नाम पर हिंसा अस्वीकार्य है। फडणवीस महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर हुतात्मा चौक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। इस अवसर पर मुंबई की मेयर रितु तावड़े भी उपस्थित थीं।

उन्होंने कहा, ''भाषा की बात करें तो, अपनी भाषा पर गर्व होना जरूरी है। मराठी भाषा पर गर्व होना चाहिए। महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी सीखने का प्रयास करना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं सीखी है, तो हम उन्हें सिखाएंगे।'' उनका यह बयान राज्य सरकार के उस निर्देश के बीच आया है, जिसमें आटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी को अनिवार्य करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र देश का विकास केंद्र और शक्ति का स्रोत है। महाराष्ट्र, भक्ति आंदोलन का साक्षी रहा एक सुधारवादी राज्य है, देश को दिशा भी प्रदान करता है।

देवेंद्र फडणवीस। फाइल

राज स्पष्ट करें अपना रुख : सरनाइक

धाराशिव, प्रेट्र : महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वे राज्य में रहने वाले हिंदी भाषी लोगों को मराठी सिखाना चाहते हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कुछ जगहों पर हिंदी भाषी लोगों को मराठी सिखाने के लिए कक्षाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हिंदी भाषी लोगों को मराठी क्यों सिखाई जानी चाहिए।

पायलट संघ की मांग- फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन लागू करें

बेंगलुरु, एएनआइ : एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एएलपीए) ने शुक्रवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को पत्र लिखकर अदालत द्वारा अनिवार्य उड़ान ड्यूटी समय सीमा के कार्यान्वयन में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। पिछले दिनों दो पायलटों की मौत के बाद पायलट संघ ने डीजीसीए को यह पत्र लिखा है। उल्लेखनीय है कि पिछले दो दिनों में एअर इंडिया और अकासा एयर के दो पायलटों को दिल का दौरा पड़ा। दोनों ड्यूटी पर नहीं थे। एअर इंडिया के पायलट की बाली में विश्राम के दौरान, जबकि अकासा एयर के पायलट की मृत्यु प्रशिक्षण के दौरान हुई।

अपने पत्र में पायलट संघ ने कहा कि इस सप्ताह हुई पायलटों की मौत के मद्देनजर उड़ान सुरक्षा और चालक दल के कल्याण के बारे में चिंताएं हैं। ये मुद्दे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) के निरंतर स्थगन के कारण उत्पन्न हुए हैं, जबकि इस विषय पर पहले भी कई बार आपत्ति जताई जा चुकी है।

उत्तर भारत को मई में भी मिलेगी गर्मी से राहत

- इस माह सामान्य से ज्यादा होगी वर्षा, नियंत्रण में रहेगा तापमान
- अंडमान-निकोबार में 14-16 मई के बीच पहुंच सकता है मानसून

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

मई महीने में देश का मौसम राहत और चुनौती दोनों एक साथ लेकर आ रहा है। किसी क्षेत्र में अधिक गर्मी तो कहीं अधिक वर्षा हो सकती है। उत्तर-पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे रह सकता है, जिससे भीषण गर्मी से काफी हद तक राहत मिलेगी। पूर्वी भारत में वर्षा का स्वरूप असमान रह सकता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा और कुछ में कमी की स्थिति बन सकती है। अलनीनो का असर मानसूनी वर्षा पर पड़ेगा, जिसके चलते सामान्य से कम वर्षा की आशंका पहले ही जताई जा चुकी है।

मानसून की शुरुआत के संकेत भी साफ हैं। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 14 से 16 मई के बीच पहुंच सकता है। यह सामान्य तिथि के आसपास है, जो मानसून के समय पर आगे बढ़ने की संभावना को मजबूत करता है। मौसम विभाग के महानिदेशक डा. मृत्युंजय महापात्रा ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर मई के तापमान, वर्षा और मानसून की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मई में पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रह सकती है।

प्रतीकात्मक

उत्तर-पश्चिम भारत और हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में शुरुआती पखवाड़े में सामान्य से अधिक वर्षा हो सकती है। इससे जम्मू-कश्मीर से लेकर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान पर नियंत्रण रहेगा एवं लू का असर सीमित हो सकता है। हालांकि महीने के अंतिम सप्ताह में तापमान बढ़ने के संकेत हैं, जो अस्थायी रूप से गर्मी को तेज कर सकते हैं।

पूर्वानुमान में कहा गया है कि अलग-अलग इलाकों के तापमान में भी असमानता होगी। उत्तर एवं उत्तर-पश्चिम राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य या उससे कम रह सकता है, जबकि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रह सकता है।

सामान्य से अधिक रहेगी लू के दिनों की संख्या

मौसम विभाग का मानना है कि हिमालय के तराई वाले इलाकों, पूर्व के तटीय राज्यों, गुजरात और महाराष्ट्र में लू के दिनों की संख्या सामान्य से ज्यादा रह सकती है। गुजरात, विशेषकर सौराष्ट्र क्षेत्र में तीन से चार दिन तीव्र लू की संभावना जताई गई है। मौसम के इस मिश्रित असर के पीछे समुद्री कारकों की बड़ी भूमिका है। प्रशांत महासागर में अभी न्यूट्रल स्थिति है, जो धीरे-धीरे अलनीनो की ओर बढ़ रही है।

मुक्तसर में गुटका साहिब के फटे अंग मिले, नए बेअदबी कानून में पहला मामला दर्ज

संवाद सूत्र, जागरण, मलोट (मुक्तसर) : पंजाब में मुक्तसर जिले के मलोट में गुरुवार शाम श्री गुटका साहिब के फटे हुए अंग गली में बिखरे मिले। इसके बाद संगत ने इन अंगों को नजदीकी गुरुद्वारा साहिब में संभालकर रख दिया और पुलिस को सूचित किया। डीएसपी हरजीत सिंह ने बताया कि बेअदबी के खिलाफ जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत पंजाब में पहला मामला मलोट में दर्ज किया गया है। हालांकि, यह अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है। मौके पर मौजूद सिख नेताओं ने श्री दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब के उपप्रबंधक सुखदेव सिंह को मांगपत्र दिया। सुखदेव सिंह ने कहा कि 10 दिन का पुलिस को अल्टीमेटम दिया है। यदि इस दौरान कोई कार्रवाई न हुई तो संगत आगामी रणनीति तय करेगी। बता दें, अप्रैल 2026 में पंजाब सरकार द्वारा लागू कानून के तहत धार्मिक बेअदबी के दोषियों को उम्रकैद तक की सजा और 5 लाख से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

राजनीति

एमवीए के गठन के बाद से शुरू हुआ सीटों और सम्मान के समझौते का सिलसिला, 2019 में जब एमवीए अस्तित्व में आई, तब से ही कांग्रेस की स्थिति गठबंधन में रही रक्षात्मक

महाराष्ट्र में बार-बार 'गठबंधन धर्म' की भेंट चढ़ती कांग्रेस

ओमप्रकाश तिवारी • जागरण

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में 'गठबंधन धर्म' निभाने की कवायद कांग्रेस के लिए आत्मघाती साबित होती दिख रही है। महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के गठन के बाद से शुरू हुआ सीटों और सम्मान के समझौते का सिलसिला अब प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष का कारण बनने लगा है। ताजा घटनाक्रमों ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) के सामने कांग्रेस आलाकमान पूरी तरह नतमस्तक हो चुका है।

2019 में जब महाविकास आघाड़ी अस्तित्व में आई, तब से ही कांग्रेस की स्थिति गठबंधन में रक्षात्मक रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में सबसे अधिक स्ट्राइक रेट होने के बावजूद विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को सांगली और मुंबई जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर

प्रतीकात्मक

अपने सहयोगियों के सामने झुकना पड़ा। हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश इकाई ने गठबंधन की एकता के नाम पर उन सीटों से भी समझौता कर लिया, जहां कांग्रेस का पारंपरिक आधार मजबूत था।

पिछले कुछ महीनों के राजनीतिक घटनाक्रम कांग्रेस के लिए और भी अधिक निराशाजनक रहे हैं। राज्यसभा चुनाव हो या विधान परिषद की सीटें, हर बार शिवसेना (यूबीटी) और शरद पवार की पार्टी ने अपनी रणनीतिक चालों से कांग्रेस को पीछे धकेलने का ही काम किया है।

पिछले दिनों हुए रास चुनाव में शरद पवार को पुनः राज्यसभा भेजने के लिए कांग्रेस को समझौता करना पड़ा, तो अब विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस शिवसेना (यूबीटी) के मुखिया उद्धव ठाकरे को समर्थन करने के लिए तैयार थी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने नामांकन भरने के एक दिन पहले गठबंधन सहयोगियों से सलाह किए बिना ही खुद के बजाय अपनी पार्टी के एक अन्य नेता को विधान परिषद का टिकट घोषित कर दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने तुरंत इस चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार देने की भी घोषणा कर दी। लेकिन दिल्ली में बैठे अपने आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस को फिर अपने कदम पीछे खींचकर शिवसेना (यूबीटी) उम्मीदवार को समर्थन करना पड़ा है। इससे पहले बारामती विधानसभा उपचुनाव में भी सहयोगियों के दबाव और स्थानीय समीकरणों के चलते कांग्रेस को वह स्थान नहीं मिल सका, जिसकी पार्टी उम्मीद कर रही थी। वहां कांग्रेस उम्मीदवार को पर्चा भरकर भी अपना नामांकन वापस लेना पड़ा था। इस प्रकार हर बार 'बड़े भाई' की भूमिका निभाने वाली कांग्रेस महज एक सहायक दल की तरह सीटों के लिए गुहार लगाती नजर आ रही है।

स्थानीय नेताओं का मानना है कि गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में पार्टी अपना जनाधार खो रही है। सांगली लोकसभा सीट का उदाहरण देते हुए एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवार होने के बाद भी सीट सहयोगियों को दे दी गई, जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। सत्ता की राजनीति और भाजपा को रोकने की कवायद में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भले ही इसे 'बलिदान' करार दे रहा हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है।

गुजरात की तरह मप्र में भी आदिवासी वर्ग को यूसीसी से मिल सकती है छूट

- सरकार ने पुलिस मुख्यालय को गुजरात और उत्तराखंड में यूसीसी के प्रविधानों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने को कहा

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया • भोपाल

मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह ही समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में आदिवासी वर्ग को छूट देने की तैयारी है। ऐसा करने की वजह यह है कि उनकी मूल सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। यूसीसी से बाहर होने पर विवाह, विवाह- विच्छेद, विरासत और संपत्ति से जुड़े पारंपरिक आदिवासी रीति-रिवाज पर यूसीसी के प्रविधान लागू नहीं होंगे।

प्रदेश में यूसीसी लागू करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति इसी सप्ताह बनाई है। समिति अब जनसुनवाई कर यूसीसी के बारे में लोगों की राय लेगी। गुजरात में भी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने में देसाई की बड़ी भूमिका रही है। हालांकि, यूसीसी लागू करने के पहले सरकार गुजरात और उत्तराखंड माडल का अध्ययन भी कराने जा रही है। पुलिस मुख्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यालय द्वारा दोनों राज्यों में लागू प्रविधानों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

सरकार इस मामले में हर प्रविधान का विधिक पहलू भी देख रही है। यही कारण है कि समिति में विधि के जानकार, शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मिलित किया गया है। जुलाई में विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार यह विधेयक ला सकती है। इसी कारण समिति को 60 दिन के भीतर अपना प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया है।

2026 जुलाई तक एयर इंडिया ने अपनी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में कटौती करने का फैसला किया है। एयर इंडिया हर दिन लगभग 100 उड़ानें रद करेगी।

इंडियन स्टेट वाले बयान पर राहुल के खिलाफ एफआइआर की मांग खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा– परिस्थितियों और तर्कों के मद्देनजर याचिका में मेरिट की कमी

कहा, संदेह आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

'इंडियन स्टेट' से लड़ाई वाले बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एकलपीठ ने राहुल के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने गत 8 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर ली थी। शुक्रवार को फैसले में कहा, परिस्थितियों और तर्कों के मद्देनजर याचिका में मेरिट की कमी है।

कोर्ट ने कहा, यह स्थापित कानूनी सिद्धांत है कि संदेह आपराधिक अभियोजन का आधार नहीं बन सकता। याची के लिए यह अनिवार्य था कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्य प्रस्तुत करता जो अपमानजनक भाषण को अपराध बना देते। पहले चरण के न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय ने याची सिमरन के खिलाफ निष्कर्ष दर्ज किए हैं। संबंधित न्यायालय ने अपने अधिकार का प्रयोग कानून के अनुसार किया है। संभल निवासी सिमरन गुप्ता ने 23 जनवरी, 2025 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(4) के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संभल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल गांधी का बयान भारतीय राज्य की संप्रभुता, अखंडता और एकता के लिए खतरा है। यह समाज में अस्थिरता और विद्रोह की भावना पैदा करेगा। 10 फरवरी, 2025 को सिविल जज (वरिष्ठ श्रेणी)/विशेष जज, एमपी/एमएलए कोर्ट ने यह शिकायत खारिज कर दी।

इसके बाद सात नवंबर, 2025 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चंदौसी ने भी याचिका खारिज कर दी तो सिमरन ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल का कहना था कि ट्रायल कोर्ट और पुनरीक्षण अदालत ने कानून को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा। कोर्ट ने कहा, इस न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई परिस्थितियां और महत्वपूर्ण विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं जिनसे ये संकेत मिले कि भाषण के परिणामस्वरूप विध्वंसक गतिविधियां भड़कीं, अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा मिला। भाषण जनवरी 2025 में दिया गया था और एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उसके परिणामस्वरूप भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के अंतर्गत आने वाली कोई भी गड़बड़ी हुई है।

राहुल गांधी। फाइल

राहुल गांधी की आवाज के नमूने के मिलान पर आज आएगा फैसला

जासं, सुलतानपुर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में शनिवार को सुनवाई होगी। परिवादी भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से राहुल गांधी की आवाज के नमूने का विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मिलान कराने के लिए दी गई अर्जी पर एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा निर्णय सुनाएंगे। आरोप है कि राहुल गांधी ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

राहुल ने कहा था–हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से

15 जनवरी 2025 को दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा था, 'कांग्रेस की लड़ाई अब केवल राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रह गई है। अगर आप यह सोचते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस जैसे किसी संगठन से लड़ रहे हैं तो आप स्थिति नहीं समझ रहे हैं। भाजपा और आरएसएस ने देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हमारी लड़ाई भाजपा, आरएसएस और खुद 'इंडियन स्टेट' से है।'

वायस काल पर सुनाई दे रही थीं चीखें

जबलपुर क्रूज हादसा

गौतम कुमार मिश्रा • जागरण

- समायापुरी के रहने वाले एक ही परिवार की तीन पीढ़ियों के तीन सदस्य की क्रूज हादसे में डूबने से हुई मौत

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी बांध में बृहस्पतिवार शाम हुए दिल दहला देने वाले क्रूज हादसे में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनमें दिल्ली के मायापुरी के खजान बस्ती में रहने वाले मसीह परिवार की तीन पीढ़ी से ताल्लुक रखने वाले तीन लोग शामिल हैं। जिन लोगों की जानें गई हैं, उनमें मधुर मसीह, इनकी बेटी मैरिना व मैरिना का चार साल का बेटा त्रिशान शामिल है। हादसा जिस क्रूज से जुड़ा है, उस पर मसीह परिवार के छह सदस्य थे।

मंगलवार को परिवार के जो सदस्य जबलपुर के लिए निकले थे, उनमें जूलियस मसीह, इनकी पत्नी मधुर मसीह, दमाद प्रदीप, इनकी पत्नी मैरिना मसीह, प्रदीप की बेटी सिया व बेटा त्रिशान थे। पूरा परिवार प्रदीप के बड़े भाई के जबलपुर में बने नए मकान के गृह प्रवेश में शामिल होने दिल्ली से निकला। बृहस्पतिवार को गृह प्रवेश समारोह पूरा होने के बाद शाम के समय सभी डैम घूमने निकले।

जब ये डैम में नौकायन कर रहे थे, तभी मैरिना ने अपनी छोटी बहन सिम्पी को वीडियो काल किया, दोनों में बात होने लगी। मैरिना वहां के नजारे सिम्पी को वीडियो काल पर दिखा रही थी। इसी दौरान नेटवर्क की समस्या आई। कुछ देर बाद सिम्पी ने अपने मोबाइल से मैरिना के मोबाइल पर वायस काल किया, काल जैसे ही मैरिना ने रिसीव किया, अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैरिना कह रही थीं कि हमें बचा लो। काफी शोरगुल हो रहा था, धीरे-धीरे शोरगुल थम गया। बाद में सिम्पी व इनके स्वजन ने कई बार फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा।

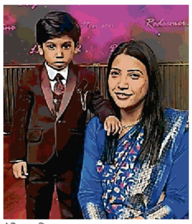
मैरिना व त्रिशान। स्वजन

मधुर।

सिम्पी। जागरण

चार वर्षीय बेटे को सीने से चिपकाए रही मां, सबकी आंखें हुई नम

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: मध्य प्रदेश में जबलपुर के बरगी बांध से शुक्रवार सुबह विचलित करने वाली एक तस्वीर सामने आई। मां मैरिना मसीह अपने अपने चार वर्षीय बेटे त्रिशान को सीने से चिपकाए हुए मिलीं। दोनों की डूबने से मौत हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर राहत व बचाव कार्य में जुटे जवानों और मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। दिल्ली निवासी मसीह परिवार के छह सदस्य बरगी बांध की सैर करने आए थे।

मैरिना व त्रिशान एक ही लाइफ जैकेट पहने थे। मरीना की मां मधुर मसीह (66) की भी मौत हो गई। हादसे में परिवार के तीन अन्य सदस्य प्रदीप कुमार (मैरिना के पति), बेटी सिया व ससुर जूलियस सुरक्षित बच गए। सिया ने मीडिया से चर्चा में बताया कि जब तेज हवा चलने लगी तो भी लाइफ जैकेट किसी ने नहीं दी थी। पापा और एक अंकल ने कांच तोड़कर निकाली। तभी क्रूज एक तरफ झुका और खिड़की टूट गई। मैं और पापा उसी रास्ते बाहर निकल गए। भाई (त्रिशान) को जैकेट पहना रहे थे तब तक तेज लहर आने लगी तो मम्मी (मैरिना) ने भाई को लाइफ जैकेट में जकड़ लिया।

रघुवंशी हत्याकांड में सोनम के कथित प्रेमी का जमानत आवेदन निरस्त

- शिलांग न्यायालय से अब सुपारी किलर विशाल, आनंद और आकाश ने भी मांगी जमानत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : इंदौर-टू-शिलांग हनीमून मर्डर में कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या में सोनम के कथित प्रेमी राज कुशवाह की जमानत अर्जी निरस्त हो गई। सोनम रघुवंशी की जमानत को आधार बनाकर राज ने अपना आवेदन शिलांग सत्र न्यायालय में लगाया था। अब सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने भी अपनी-अपनी जमानत के लिए आवेदन लगाया है।

इंदौर निवासी 30 वर्षीय राजा रघुवंशी की हत्या मई 2025 में शिलांग में पत्नी सोनम के साथ हनीमून दौरे के दौरान कर दी गई थी। शिलांग पुलिस ने राजफाश किया था कि सोनम ने अपने घरेलू नौकर और कथित प्रेमी राज कुशवाह के साथ साजिश की और इंदौर के सुपारी किलर विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी से राजा की हत्या करा दी। पिछले दिनों शिलांग सत्र न्यायालय ने गिरफ्तारी के समय के रिकार्ड में उचित धाराओं को न दर्शाने जैसी प्रक्रिया में पुलिस की खामियों का लाभ देते हुए सोनम को सशर्त जमानत दे दी थी। इसके आधार पर राज कुशवाह के वकील फुयोसा योबिन ने भी सत्र न्यायालय से जमानत मांगी, जिसे शुक्रवार को निरस्त कर दिया। योबिन के अनुसार कोर्ट ने तकनीकी आधार पर जमानत आवेदन निरस्त किया है।

मकान खाली कर चला गया राज का परिवार

आरोपित राज कुशवाह का परिवार इंदौर में लक्ष्मणपुरा कालोनी में रहता था। राज की गिरफ्तारी के बाद उसकी मां बहनों को लेकर उत्तर प्रदेश में गांव में चली गई है। वकील योबिन के अनुसार, परिवार का कोई सदस्य राज से मिलने नहीं आता है। कोर्ट के दस्तावेज साइन करवाने के लिए वकील ही शिलांग जेल में मिलने जाते हैं।

बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट से परेशान महिला ने फंदे से लटककर दी जान

जागरण संवाददाता, बिजनौर

- सुसाइड नोट में किसी युवक के परेशान करने की बात लिखी
- पुलिस को ब्लैकमेलिंग का अंदेशा, तीन टीमें कर रहीं जांच

बिजनौर में डिजिटल अरेस्ट से परेशान होकर महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। स्वजन द्वारा उपलब्ध कराए मोबाइल नंबरों की जांच में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं। स्वजन डिजिटल अरेस्ट किए जाने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस ब्लैकमेलिंग का अंदेशा जता रही है। उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले के एसपी अभिषेक झा ने कहा कि अभी तक की जांच में डिजिटल अरेस्ट का तथ्य सामने नहीं आया है। पुलिस की तीन टीमों ने जांच शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के गांव फरीदपुर भोगी निवासी रणवीर सिंह की पत्नी 28 वर्षीय मोनिका ने गत सोमवार सुबह फंदे पर लटककर जान दे दी थी। स्वजन ने उसी दिन अंतिम संस्कार कर दिया था।

उनके भतीजे संयोग का आरोप है कि अंतिम संस्कार के दौरान भी मोनिका के मोबाइल फोन पर वर्दी पहने एक युवक ने काल की थी।

आरोप है कि फोन करने वाला युवकि पैसों की मांग कर रहा था। दो दिन बाद स्वजन को मोनिका के कमरे में रखी एक डायरी में सुसाइड नोट मिला। इसमें उसने एक युवक द्वारा परेशान किए जाने की बात दो बार लिखी है। मामला चर्चा में आने के बाद पुलिस भी जागी और गांव पहुंचकर स्वजन से जानकारी ली। साथ ही पति की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया।

पति द्वारा उपलब्ध कराए मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है और सीडीआर निकाली जा रही है। मोनिका के पति ने डिजिटल अरेस्ट किए जाने से परेशान होकर जान देने की बात कही है। हालांकि, तहरीर में सिर्फ फोन कर परेशान करने का जिक्र है।

बता दें, मोनिका की शादी 2015 में हुई थी। उसकी नौ और चार साल की दो बेटियां हैं। रणवीर एक फैक्ट्री में श्रमिक है, जबकि मोनिका गृहणी थी।

स्वजन ने यह भी जानकारी दी कि मृतक मोनिका का किसी बैंक में अकाउंट नहीं है।

मोनिका का फाइल फोटो। सौ स्वजन

तरबूज तोड़ने के विवाद में मासूम की हत्या, आंख भी निकाली

जागरण संवाददाता, आगरा

- गांव से एक किलोमीटर दूर चकमार्ग के किनारे मिला शव
- चार घंटे तक नहीं उठने दिया, जाम लगाकर किया प्रदर्शन

तरबूज तोड़ने के विवाद में मासूम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। किशोर का शव गांव से एक किलोमीटर दूर चकमार्ग के किनारे पड़ा मिला। उसकी दायीं आंख भी निकाल ली गई। पास से ही तरबूज काटने का चाकू भी बरामद हुआ है।

किशोर का शव देखकर ग्रामीणों में आक्रोश भड़क गया। चकमार्ग पर जाम लगाकर चार घंटे तक शव नहीं उठने दिया। स्वजन आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद ही शव उठाने देने की मांग पर अड़े थे।

गांव रंधीरपुरा के आसपास मेरठ के मुस्लिम परिवार तरबूज और खरबूज की खेती करते हैं। गांव निवासी नरेश कुशवाह का 14 वर्षीय पुत्र छोटू शुक्रवार दोपहर 12 बजे इन खेतों से तरबूज लाने की बात कहकर घर से निकला था। शाम तक जब वह वापस नहीं आया तो स्वजन ने तलाश शुरू की।

गांव से एक किलोमीटर दूर सोनीखेड़ा बांध के पास चकमार्ग पर शुक्रवार शाम पांच बजे छोटू का शव खून से लथपथ हालत में बहन भोला ने देखा। बहन की चीख सुनकर ग्रामीण और स्वजन भी पहुंच गए। किशोर के सिर, चेहरे, कान पर धारदार हथियार के निशान थे। पास में ही तरबूज काटने का चाकू भी पड़ा मिला। उसकी दायीं आंख भी गायब थी। स्वजन का आरोप है कि तरबूज के विवाद में उनके पुत्र की हत्या की गई है। विलाप करते स्वजन चकमार्ग पर ही बैठ गए।

ग्रामीणों ने वाहनों को रोककर जाम लगा दिया। सूचना पर एसीपी प्रीता दुबे के अलावा 10 थानों का पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों ने बताया कि नरेश मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। छोटू चार बहन व तीन भाइयों में सबसे छोटा था।

वंदे भारत एक्सप्रेस के नाश्ते में निकली मक्खी, हंगामा

जागरण संवाददाता, आगरा : आगरा-वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में शुक्रवार सुबह नाश्ते में मक्खी निकली। घटना से नाराज यात्रियों ने हंगामा किया। मुंबई के बाल रोग विशेषज्ञ डा. कपिल पाटिल की पत्नी सहित कुछ महिला यात्रियों ने फूड प्वाइजनिंग की शिकायत की। प्रयागराज स्टेशन पर यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो गया। आइआरसीटीसी ने यात्री की शिकायत पर तत्काल सेवा प्रदाता फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार सुबह छह बजे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। इटावा के बाद यात्रियों को नाश्ता का वितरण किया गया। इसमें फ्रेंच फ्राइज-कटलेट, ब्रेड-मक्खन और इडली-सांभर शामिल थी। सी-13 कोच की सीट नंबर 52 में राघव मित्तल व डा. कपिल पाटिल परिवार के साथ सफर कर रहे थे। यात्रियों ने फ्रेंच फ्राइज-कटलेट का पैकेट खोला तो उसमें मक्खी निकली।

छत्तीसगढ़ में यीशु के चमत्कार के नाम पर इलाज के दौरान मौत, दोषी को उम्रकैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर

- परिवार पर मतांतरण का दबाव बनाते हुए कर रही थी चमत्कारी तेल और गर्म पानी से इलाज

यीशु के नाम पर चमत्कारी इलाज के दौरान 18 वर्षीय युवती के मौत की जिम्मेदार छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले की ईश्वरी साहू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोषी महिला पूरे परिवार को मतांतरित करने के प्रयास में भी जुटी थी। रायपुर के पंडरी क्षेत्र की रहने वाली सुनीता सोनवानी की मानसिक रोग से पीड़ित बेटी की 22 मई 2025 को मौत के बाद पोस्टमार्टम में स्पष्ट हुआ था कि तेल और गर्म पानी से इलाज के दौरान उसे गंभीर चोटें आई थीं।

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने गरियाबंद जिले के राजिम क्षेत्र की 41 वर्षीया ईश्वरी को सजा सुनाते हुए कहा है कि दोषी ने यीशु मसीह के नाम पर चमत्कार का भ्रम फैलाकर न केवल एक मासूम की जिंदगी छीनी, बल्कि उसके परिवार को धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया। विशेष लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने अदालत में 21 गवाह पेश किए, जिनमें मृतका की मां, स्वजन, डाक्टर और अन्य प्रत्यक्षदर्शी शामिल थे। डाक्टर ने कोर्ट में इसे हिंसक (हत्यात्मक) प्रकृति की मृत्यु बताया जिसमें मृतका के फेफड़े में खून जमा था और छाती पर गंभीर अंदरूनी चोटें थीं।

दाहिनी ओर की तीन पसलियां टूटी हुई थीं। इसके कारण सांस रुकने से मौत हुई। बचाव पक्ष ठोस तर्क प्रस्तुत नहीं कर सका।

ईश्वरीसाहू

रायपुर के पंडरी निवासी युवती का मई 2025 की अंदरूनी चोटों के कारण रुक गई थी सांस

इलाज की तलाश में फंसा परिवार

मृतका की मां सुनीता सोनवानी ने बेटी का इजाल निजी अस्पताल और महासमुंद मेडिकल कालेज में करा रही थी। इसी दौरान एक नजदीकी से भाटापारा निवासी ईश्वरी द्वारा प्रभु की शक्ति से इलाज की जानकारी मिली और वह जाल में फंस गई। दोषी महिला बुरी आत्मा निकालने के नाम पर चमत्कारी तेल और गर्म पानी डालकर युवती के शरीर को पैरों से मसलती थी। इलाज के दौरान किशोरी की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती गई। दोषी हर बार चमत्कार का दावा करती थी। साथ ही चेताया कि अगर इलाज के बारे में किसी को बताया गया, तो यीशु मसीह नाराज हो जाएंगे। इस डर और उम्मीद से वह चुप रहे। ईश्वरी ने पीड़ित मां-बेटी पर दबाव बनाया कि ठीक होने के पहले उन्हें धर्म परिवर्तन करना होगा।

आगरा अवैध मतांतरण गिरोह से जुड़े चार और आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, आगरा

- आरोपितों में एक निकाहनामा तैयार करता था, दूसरा करता था ब्रेनवाश
- पुलिस ने तीन दिल्ली और एक आरोपित को राजस्थान से किया गिरफ्तार

दो बहनों का अवैध मतांतरण कराने के चर्चित मामले में पुलिस ने मतांतरण गिरोह के चार और सक्रिय सदस्यों को दिल्ली और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपित उम्रकैद के सजायाफ्ता मौलाना कलीम सिद्दीकी गिरोह से जुड़े थे और कलीम के जेल जाने के बाद गिरोह की कमान संभाले वाले अब्दुल रहमान कुरैशी के साथ सक्रिय थे। गिरोह में इनकी अलग-अलग जिम्मेदारी थी। एक निकाहनामा तैयार करता था तो दूसरा ब्रेनवाश करता था। तीसरा सदस्य युवतियों के रुकने आदि की व्यवस्था करता था।

बीते वर्ष शहर से गायब दो बेटियों को पुलिस ने कोलकाता के मुस्लिम बहुल तपसिया क्षेत्र से बरामद किया था। बेटियों का अवैध मतांतरण कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने सरगना दिल्ली के अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल सिंह सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में सभी जेल में हैं। पुलिस टीमें गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई थीं। पुलिस ने दिल्ली निवासी तलजीम उर रहमान, परवेज अख्तर, जतिन कपूर उर्फ जाशिम कपूर और राजस्थान निवासी हसन मोहम्मद को गिरफ्तार किया। हाल ही में बयान दर्ज कराने आई राजस्थान की पीड़ित छात्रा से पुलिस को अहम जानकारी मिली थी।

कोर्ट ने नहीं दिया रिमांड

राजस्थान और दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लाई पुलिस ने चारों आरोपितों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया। राष्ट्रीय सुरक्षा, मतांतरण और विदेशी कनेक्शन से मामला जुड़ा होने के कारण पुलिस ने 14 दिन का रिमांड मांगा। न्यायालय ने रिमांड अर्जी खारिज करते हुए सभी को जेल भेज दिया।

ससुराल शादी में आया दामाद सास को बाइक पर बैठाकर फरार

जासं, मथुरा : आठ बच्चों की मां को दामाद एक बार फिर भगा ले गया। दामाद भी पांच बच्चों का पिता है। शादी समारोह में दोनों को लोगों ने आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। इसके बाद दामाद सास को बाइक पर बैठाकर ले गया। पूर्व में भी दामाद सास को ले जा चुका है। इस मामले में कार्रवाई को थाने में प्रार्थना पत्र दिया है। आगरा के दो सगे भाइयों की शादी 12 वर्ष पूर्व फरह के एक गांव की दो सगी बहनों के साथ हुई थी। शादी के तीन वर्ष बाद बड़े दामाद को 53 वर्षीय सास से प्यार हो गया। शादी के तीन वर्ष बाद दोनों भाग गए। स्वजन ने दोनों को दिल्ली स्थित एक कंपनी से पकड़ा था। उसके बाद सब ठीक चल रहा था। गुरुवार को बड़ा दामाद ससुराल में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था। आरोप है दोपहर एक बजे दामाद, सास को घर के पीछे खेत में मेहंदी तोड़ने के बहाने ले गया। वहां महिला के पति ने दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया।

झारखंड

परीक्षा में दृष्टि और सृष्टि ने हासिल किए 97 .6 प्रतिशत अंक, दोनों की शक्ल और आदतें भी काफी मिलती-जुलती

जुड़वा बहनें आइसीएसई 10वीं बोर्ड में बनीं टापर

जागरण संवाददाता, हजारीबाग

- दोनों बहनों ने न केवल एक साथ पढ़ाई की, बल्कि एक-दूसरे की ताकत बनकर अपने को आगे बढ़ाया

झारखंड के हजारीबाग की रहने वाली जुड़वां बहनों दृष्टि और सृष्टि ने आइसीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.6 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले की टापर बनी हैं। दोनों बहनें हजारीबाग के कार्मेल स्कूल में पढ़ती हैं। खास बात यह है कि दोनों की शक्ल और आदतें भी काफी मिलती-जुलती हैं। अब दोनों के नंबर भी एक समान आये हैं।

दृष्टि और सृष्टि हजारीबाग के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डा. मोहन लाल और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. रश्मि प्रसाद की पुत्रियां हैं। घर में शुरू से ही पढ़ाई और अनुशासन का माहौल रहा, जिसका असर दोनों की पढ़ाई पर साफ दिखा। दोनों बहनों ने न केवल एक साथ पढ़ाई की, बल्कि एक-दूसरे की ताकत बनकर आगे बढ़ीं। दोनों बहनों ने बताया कि उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि वे दोनों एक साथ टापर बनेंगी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई के दौरान वे एक-दूसरे को प्रोत्साहित करती थीं। किसी भी विषय में कठिनाई आने पर दोनों साथ बैठकर उसे समझती थीं और तब तक प्रयास करती थीं, जब तक विषय पूरी तरह स्पष्ट न हो जाए।

दोनों प्रबंधन का विशेष ध्यान रखती थीं। स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने भी हर कदम पर उनका सहयोग किया और जरूरत पड़ने पर फोन के माध्यम से भी उनकी समस्याओं का समाधान किया। भविष्य को लेकर दृष्टि और सृष्टि का लक्ष्य भी स्पष्ट है। वे अपने माता-पिता से प्रेरित होकर डाक्टर बनना चाहती हैं।

एक समारोह के दौरान अपने माता-पिता के साथ दृष्टि (बीच में बाएं) और सृष्टि (बीच में दाएं)। फाइल फोटो >>

पटना में बदल गया नीतीश कुमार का पता

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना

- मुख्यमंत्री आवास, 01, अणे मार्ग से 07 सर्कुलर रोड स्थित आवास में आ गए
- पुत्र निशांत कुमार एवं अन्य स्वजन भी हैं उनके साथ

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का पता बदल गया है। करीब 20 वर्षों तक उनके पद का नाम मुख्यमंत्री और आवास का पता 01, अणे मार्ग रहा। 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से वह विधिवत विदा हो गए। शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा पर नए आवास में पूजा-अर्चना हुई। उनका सामान भी आ गया है। साथ में पुत्र निशांत कुमार एवं अन्य स्वजन हैं।

अब किसी शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 01, अणे मार्ग में चले जाएंगे। 07, सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार एक बार पहले भी रह चुके हैं। मई, 2014 में मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद वह इसी आवास में रहने आए थे।

फरवरी, 2015 में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वह फिर एक अणे मार्ग में रहने चले गए। तब से गुरुवार तक वह इसी आवास में रहे। 01, अणे मार्ग राज्य के मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित आवास है। आवास परिसर में एक मिनी सचिवालय भी है, जिसमें मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में तैनात अधिकारी बैठते हैं।

नीतीश के नए आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मी। प्रेट्र

बिहार का नाम बदलकर श्रमिक प्रदेश कर दे भाजपा : तेजस्वी

राज्य ब्यूरो, जागरण • पटना : राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार विगत 21 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन में नगण्य, परंतु श्रम की आपूर्ति में अव्वल है। भाजपाइयों, विशेषकर नए-नवेले व बड़बोले मुख्यमंत्री को चाहिए कि श्रमिक दिवस का नाम बदल कर बिहार समर्पित दिवस और बिहार का नाम बदल कर श्रमिक प्रदेश कर दें।

44 मोरों की मौत की पुष्टि हुई है कर्नाटक के तुमकुर जिले में एच5एन1 बर्ड फ्लू वायरस से। 16 अप्रैल से एक सप्ताह के भीतर लगातार मोरों की मौत के मामले सामने आए थे। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 10 किलोमीटर का कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।

न्यूज गैलरी

केरलम के मंदिरों में हाथियों का कहर, दो लोगों की मौत

कोच्चि : केरलम में शुक्रवार को मंदिरों से जुड़ी दो अलग-अलग घटनाओं में बेकाबू हुए हाथियों ने अफरा-तफरी मचा दी, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर और एक महावत की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। पहली घटना अंगमालि में हुई, जहां मंदिर में लाया गया हाथी अचानक उग्र हो गया। उसने परिसर के बाहर खड़े वाहनों को पलट दिया और भारी नुकसान पहुंचाया। इस दौरान हाथी ने उस ट्रक चालक को कुचल दिया, जिससे उसे लाया गया था, जबकि मुख्य महावत गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने उसे बेहोश कर काबू में किया। दूसरी घटना इरिंजालाकुडा में हुई, जहां उत्सव के लिए लाया गया हाथी पहले से ही बेकाबू था और उसे बांधकर रखा गया था। महावत खाना देने पहुंचे, तो हमला कर दिया। (प्रेट्र)

अटारी सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी अब छह बजे से होगी

अमृतसर : भारत-पाकिस्तान की अटारी सीमा पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी का समय बदल दिया गया है। अब रिट्रीट सेरेमनी की रस्म रोज शाम छह से साढ़े छह बजे तक होगी। इससे पहले इसका समय साढ़े पांच से छह बजे तक था। बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि यहां रिट्रीट सेरेमनी देखने देश के विभिन्न हिस्सों से दर्शक पहुंचते हैं। गर्मी के मौसम के कारण समय में बदलाव किया गया है। (जासं)

बेंगलुरु में आभूषण दुकान से 70 किलो चांदी लेकर फरार

बेंगलुरु : बेंगलुरु में चोरों ने एक आभूषण दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 70 किलो चांदी के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बदमाशों ने पीछे से दुकान में घुसकर दीवार में छेद किया और ताले तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। सुबह दुकान खुलने पर चोरी का पता चला। पुलिस के अनुसार चोरी गए सामान की कीमत करोड़ों रुपये में बताई जा रही है। हैरानी की बात यह है कि दुकान के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। आरोपित पास की दुकान का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। (प्रेट्र)

मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में तुइवई नदी पर बना पुल ढहा

चुराचांदपुर : चुराचांदपुर जिले में तुइवई नदी पर बना एक अहम बेली ब्रिज अचानक ढह गया। यह घटना तब हुई जब दो सीमेंट से लदे ट्रक पुल से गुजर रहे थे। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। यह पुल इलाके के लिए जरूरी आपूर्ति मार्ग माना जाता है। इससे असम के सिलचर और मिजोरम से आवश्यक सामान की आवाजाही होती है। घटना के बाद प्रशासन ने युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है, ताकि जल्द से जल्द यातायात बहाल किया जा सके। (प्रेट्र)

मंगला देवी मंदिर के पास बिजली गिरने से 11 घायल

इडुक्की : केरलम के इडुक्की में मंगला देवी मंदिर के पास शुक्रवार को बिजली गिरने से 11 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, सभी श्रद्धालु पूजा कर लौट रहे थे, तभी पहाड़ी से नीचे उतरते समय यह हादसा हुआ। गौरतलब है कि चित्रा पूर्णिमा के दौरान हर साल खुलने वाले इस मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। (प्रेट्र)

ब्रिटिश इतिहासकार की पुस्तक में दावा, हिंदू शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी भोजशाला

धार्मिक स्वरूप ▸ हाई कोर्ट में सुनवाई के बीच सामने आई 1902 में प्रकाशित अर्नेस्ट बर्न्स की पुस्तक- धार एंड मांडू

मस्जिद वाले स्थल पर राजा भोज का विद्यालय होने का स्पष्ट उल्लेख, स्थानीय परंपराओं से मेल का भी किया जिक्र

प्रेमविजय पाटिल • नईदुनिया

धार : ऐतिहासिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप निर्धारित करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में नियमित सुनवाई जारी है। इस बीच, ब्रिटिशकालीन एक महत्वपूर्ण पुस्तक से नए तथ्य सामने आए हैं।

अर्नेस्ट बर्न्स।

ब्रिटिश इतिहासकार अर्नेस्ट बर्न्स द्वारा लिखित पुस्तक- 'धार एंड मांडू' में दर्ज विवरण से स्पष्ट होता है कि भोजशाला मूल रूप से हिंदू संरचना एवं शिक्षा का केंद्र रही, जिसे बाद में मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया।

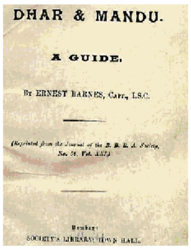

ब्रिटिश इतिहासकार अर्नेस्ट बर्न्स की किताब का मुख्य पृष्ठ। सौजन्य इतिहासकार

तत्कालीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती इस पुस्तक के पृष्ठ 12 पर 'राजा भोज का विद्यालय' शीर्षक से लिखे लेख में उल्लेख है कि मौलाना कमाल-उद्दीन के मकबरे के पास स्थित यह स्थान स्थानीय हिंदू समाज में 'राजा भोज का विद्यालय' के रूप में जाना जाता था। यह तथ्य इस स्थल के शैक्षणिक महत्व को स्पष्ट करता है और परमार कालीन परंपरा से इसका संबंध जोड़ता है। 1902 में प्रकाशित इस पुस्तक में यह भी उल्लेख है कि वर्तमान में यह संरचना मस्जिद के रूप में दिखाई देती है, लेकिन इसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री पुराने हिंदू भवनों से ली गई प्रतीत होती है। इससे संकेत है कि मस्जिद बनाए जाने से पहले यहां भव्य हिंदू मंदिर या शिक्षा केंद्र था। इसके मेहराब और गुम्बद की सजावट को अन्य समकालीन इमारतों की तुलना में अधिक अलंकृत बताया गया है, जो इसकी प्राचीनता और विशेषता को दर्शाता है। उल्लेख है कि इस स्थल की ऐतिहासिकता को सर्पबंध स्तंभ शिलालेख और अधिक मजबूत करते हैं। 11वीं-12वीं सदी के नागरी लिपि में अंकित संस्कृत शिलालेखों में वर्णमाला, संज्ञा और क्रिया के विभक्ति रूप अंकित हैं। सर्प के आकार में बने इन शिलालेखों में कुल 53 अक्षर और कई व्याकरणिक रूप दर्ज हैं। विशेषज्ञ इसे वर्णमाला आधारित शिलालेख मानते हैं, जो यह स्पष्ट करता है कि यहां व्यवस्थित शिक्षा दी जाती थी। इतिहासकारों के अनुसार, राजा भोज के समय धार विद्या और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। ऐसे में इस स्थान का 'राजा भोज का विद्यालय' के रूप में उल्लेख इस बात को और बल देता है कि यहां पहले शिक्षा और धार्मिक गतिविधियां संचालित होती थीं, जिन्हें बाद में परिवर्तित कर मस्जिद का स्वरूप दिया गया। मंदिर पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल के अनुसार, ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में यह पुस्तक स्पष्ट करती है कि भोजशाला पहले हिंदू संरचना और शिक्षा का केंद्र था, बाद में इसे तोड़कर मस्जिद का रूप दिया गया। यह साक्ष्य हमारे पक्ष को और मजबूत करता है। इस पुस्तक का प्रकाश बंबई, सोसाइटी पुस्तकालय ने किया था।

पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत

▸ सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच में सहयोग करेंगे और बुलाने पर थाने में पेश होंगे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा पर आरोपों के मामले में आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर खेड़ा को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग देंगे और जब जरूरत होगी या बुलाया जाएगा तब पुलिस थाने में पेश होंगे। यह भी कहा है कि खेड़ा जांच और ट्रायल के दौरान सुबूतों से छेड़छाड़ या उन्हें प्रभावित नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट की पूर्व अनुमति बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे। कोर्ट ने आदेश में टिप्पणी की कि यह मामला राजनीतिक रंजिश से उपजा हुआ लगता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार एक अनमोल मौलिक अधिकार है और इसे छीनने का कोई भी कदम ऊंचे मानदंडों पर सही ठहराया जाना चाहिए, खासकर तब जब आसपास के हालात राजनीतिक रंग होने का संकेत देते हों। कोर्ट ने कहा कि हमारी राय में इस मामले में जो आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं, वे पहली नजर में राजनीति से प्रेरित और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित लगते हैं। ये ऐसी स्थिति नहीं दर्शाते जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो। कोर्ट ने कहा कि आरोपों की सच्चाई की जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है।

पवन खेड़ा। फाइल

असम के मुख्यमंत्री की पत्नी पर तीन पासपोर्ट के आरोपों का मामला

> मामले में सामने आए आरोप-प्रत्यारोप प्रथमदृष्टया राजनीति से प्रेरित और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रभावित लगते हैं, न कि ऐसी स्थिति को उजागर करते हैं जिसके लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो।
> -सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी

कांग्रेस ने खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जीत बताया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश और वरिष्ठ वकील सांसद अभिषेक सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संदेश देता है कि व्यक्तिगत आजादी सबसे ऊपर है और गिरफ्तारी "आखिरी उपाय" होना चाहिए न की कोई सामान्य कदम।

फ्रेट कारिडोर धमाके में एक और आरोपित मानसा से गिरफ्तार

▸ मारे गए आतंकी जगरूप का शव मोर्चरी में पड़ा, परिवार ने नहीं किया दावा

जागरण टीम, पटियाला

पटियाला जिले के शंभू के पास गांव बठौणियां से गुजर रहे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कारिडोर पर पिछले दिनों धमाका करने के मामले में एक और आरोपित मनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। मानसा के गांव जलवेड़ा निवासी मनप्रीत प्राइवेट अस्पताल में काम करता था और यहीं से उसे पकड़ा गया। सूत्रों के अनुसार उसे पटियाला पुलिस को सौंप दिया गया है, लेकिन पटियाला पुलिस गिरफ्तारी से इन्कार कर रही है। चार आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। उधर, ट्रैक पर विस्फोटक लगाते समय मारे गए आतंकी जगरूप का शव 72 घंटे से राजपुरा सिविल अस्पताल की मोर्चरी में लावारिस पड़ा है। 28 अप्रैल को क्षत-विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था, लेकिन अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य शव पर दावा करने नहीं पहुंचा है। अस्पताल के दस्तावेज में भी शव अज्ञात के रूप में ही दर्ज है, जबकि यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि यह शव जगरूप का ही है। अस्पताल के एसएमओ डा. शरणजीत सिंह ने बताया कि नियमों के मुताबिक किसी भी लावारिस या अज्ञात शव को अधिकतम 72 घंटे तक ही मोर्चरी में रखा जाता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवार ने दावा नहीं किया तो कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर जीआरपी की देखरेख में शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा।

गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 मई तक नहीं लगेगा कोई टोल टैक्स, 15 मई से देना होगा टोल

▸ 594 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर बनाए गए हैं 21 छोटे-बड़े टोल प्लाजा

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाले 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले वाहनों से 14 मई तक टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपीडा (उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी) ने एक्सप्रेसवे का निर्माण करने वाली कंपनी आइआरबी और अदाणी इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 दिनों तक टोल नहीं वसूलने के लिए कहा है। इससे कंपनियों को होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। 15 मई से कंपनियां वाहनों से वसूली कर सकेंगी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 अप्रैल को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया, जिसके बाद से वाहनों का आवागमन शुरू है। इसका निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) टोल माडल पर किया गया है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज से होकर गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 36,230 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। 120 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से डिजाइन किए गए इस एक्सप्रेसवे पर मेरठ व प्रयागराज में दो मुख्य टोल प्लाजा और 19 रैंप टोल प्लाजा हैं।

कार व जीप से वसूले जाएंगे करीब 1800 रुपये : यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी एचपी शाही ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर सफर के लिए टोल का आधार मूल्य 2.55 रुपये प्रति किमी तय है, पर स्ट्रक्चर में खर्च राशि के आधार पर कार व जीप चालकों को मेरठ से प्रयागराज तक के सफर के लिए करीब 1800 रुपये देने पड़ेंगे।

पुणे में सेल्फी के चक्कर में डूबकर तीन दोस्तों की मौत

पुणे, प्रेट्र: पुणे के मावल तहसील में शुक्रवार को दोस्तों के एक समूह का पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बुरे सपने में तब्दील हो गया। सेल्फी लेने के चक्कर में उनमें तीन लोग बांध के पानी डूब गए। यह घटना जाधववाड़ी बांध पर दोपहर करीब तीन बजे घटी। पुलिस ने मृतकों की पहचान अजय गरुडे, संतोष एडके और अनिकेत पवार के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि पुणे के भोसारी से छह दोस्तों का समूह पिकनिक मनाने वहां पहुंचा था। उनके दोस्तों से मिली जानकारी के अनुसार, समूह के चार सदस्य घुटनों तक गहरे पानी में खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक, जो किनारे पर खड़ा था, फिसलकर गहरे पानी में गिर गया।

तुर्किये में 'हमजा' नाम से रह रहा था सलीम डोला

नई दिल्ली, प्रेट्र : तुर्किये से हाल ही में भारत लाए गए अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला तुर्किये में 'हमजा' नाम से बुल्गारियाई पासपोर्ट पर रह रहा था। अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मुंबई की एक स्थानीय अदालत ने 59 वर्षीय डोला को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में 8 मई तक भेज दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि डोला तुर्किये में 'हमजा' नाम से बुल्गारियाई पासपोर्ट पर रह रहा था। यह पता लगाया जा रहा है कि उसका बुल्गारियाई पासपोर्ट वैध था या नकली। जांच एजेंसी ने बताया कि डोला का नाम दाऊद इब्राहीम से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर के रूप में उभरा है और उसे जून, 2023 में दक्षिण मुंबई से जब्त की गई मेफेड्रोन ड्रग की वाणिज्यिक मात्रा का प्रमुख आपूर्तिकर्ता माना गया है।

महाराष्ट्र के रेस्त्रां में बताना होगा पनीर परोस रहे या उसका विकल्प

मुंबई, प्रेट्र : महाराष्ट्र में रेस्त्रां और खाने-पीने की दुकानों को अब यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि उनके द्वारा परोसा जाने वाला "पनीर" दूध से बना असली पनीर है या उसका विकल्प खाद्य तेल व चीज एनालाग से बना है। महाराष्ट्र सरकार ने ग्राहकों को इसकी स्पष्ट सूचना देने का निर्देश जारी किया है।

अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के खाद्य और औषधि प्रशासन के गुरुवार से प्रभावी 20 मार्च के आदेश में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सस्ते गैर-डेयरी विकल्पों के उपयोग से गुमराह होने से रोकने के लिए जारी किया गया था। आदेश के अनुसार, रेस्त्रां, होटल, कैटरर्स और फास्ट-फूड आउटलेट समेत सभी खाद्य व्यवसायों को अपने मेन्यू, बिल और डिस्प्ले बोर्ड पर विकल्पों के उपयोग को स्पष्ट रूप से बताना होगा। निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को भी ऐसे उत्पादों को सही तरीके से लेबल करने के लिए निर्देशित किया गया है। खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पनीर ऐसा उत्पाद है जो पूरी तरह से दूध से बनाया जाता है, जबकि एक चीज एनालाग खाद्य तेल, स्टार्च और इमल्सिफायर का उपयोग करके तैयार होता है। ऐसे विकल्पों को असुरक्षित नहीं माना जाता।

खाद्य और औषधि प्रशासन। फाइल

आप छोड़ भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य गुप्ता की फैक्ट्री पर दंडात्मक कार्रवाई पर रोक

▸ याचिका में कंपनी ने आरोप लगाया है कि पीपीसीबी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई

राज्य ब्यूरो, जागरण • चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी (आप) छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्य और ट्राइडेंट ग्रुप के संस्थापक व उद्योगपति राजिंदर गुप्ता की कंपनी ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) द्वारा की गई छापेमारी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में शुक्रवार को याचिका दायर की है। इसमें कंपनी ने आरोप लगाया है कि पीपीसीबी की कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की गई है।

दूसरी ओर, पीपीसीबी ने अदालत को स्पष्ट किया कि यह केवल नियमित निरीक्षण था और किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित नहीं है। अदालत ने पीपीसीबी के बयान को रिकार्ड में लेते हुए कंपनी के खिलाफ किसी भी कठोर कार्रवाई पर रोक लगा दी। कंपनी ने अदालत को बताया कि 1990 में स्थापित उनके उद्योग में लगभग 15 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं और सभी पर्यावरणीय मानकों का पालन किया जा रहा है। राजिंदर गुप्ता, जो अब सक्रिय प्रबंधन से अलग हैं और चेयरमैन एमेरिटस की भूमिका में हैं, ने 24 अप्रैल को आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। उनके भाजपा में शामिल होने के बाद कंपनी के प्रबंधन और कर्मचारियों को कथित धमकियों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने 25 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव को सुरक्षा की मांग संबंधी पत्र भी भेजा था। याचिका में आरोप लगाया गया कि गुरुवार को पीपीसीबी की 30 सदस्यीय टीम ने फैक्ट्री परिसर में पहुंचकर छापामार कार्रवाई की।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट। फाइल

यात्रा

हिमालय की गोद में आस्था के साथ रोमांच, जहां मिलती है आत्मिक शांति

उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित मजुवा टाप की करें यात्रा, यहां हर तरफ है सुकून

घनश्याम जोशी • जागरण

बागेश्वर: अगर आप मैदानी क्षेत्रों के माहौल से कुछ पल सुकून पाने की तलाश में हैं, तो उत्तराखंड में बागेश्वर जिले का मजुवा टाप आ जाइए। यहां हिमालय की विराटता, आस्था की गहराई व प्राकृतिक सुंदरता के संग रोमांच का एहसास भी है। पिंडारी ग्लेशियर मार्ग पर स्थित यह स्थल शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की शांति में ले जाता है। यहां सूर्योदय की किरणें व सूर्यास्त के रंग जीवन को नए अर्थ देते हैं।

कपकोट तहसील के कर्मी गांव के समीप स्थित मजुवा टाप से हिमालय की विस्तृत और मनोहारी पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। साफ मौसम में बर्फ से ढकी चोटियां किसी सजीव चित्रकला का आभास कराती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ यह स्थल धार्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां स्थित संकटहर महादेव मंदिर क्षेत्रवासियों की गहरी आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि नानतिन बाबा ने यहां तपस्या कर मंदिर की स्थापना की थी। प्रत्येक वर्ष श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रोमांच प्रेमियों के लिए यह क्षेत्र विशेष महत्व रखता है, क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर जाने वाला ट्रैक मार्ग यहीं से होकर गुजरता है। पिंडारी ग्लेशियर की यात्रा शुरू हो गई है, जोकि 15 जून तक चलेगी।

बागेश्वर के कर्मी गांव के पास मजुवा टाप का मनमोहक दृश्य • जागरण

ध्यान-योग के लिए हैं पांच गुफाएं

संकटहर महादेव मंदिर और गुफा • जागरण

मजुवा टाप क्षेत्र में पांच गुफाएं हैं, जहां पर्यटक ध्यान और योग साधना कर सकते हैं। प्राकृतिक शांति और एकांत के कारण यह स्थान साधकों के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से यह स्थल भविष्य में बड़ी पहचान बना सकता है। कर्मी गांव में पर्यटकों के ठहरने के लिए होमस्टे की सुविधा है।

> प्रशासन और पर्यटन विभाग समन्वित प्रयास करें तो मजुवा टाप न केवल कपकोट, बल्कि पूरे देश के लिए नई पहचान बन सकता है। प्राकृतिक सौंदर्य, आध्यात्मिक शांति और साहसिक रोमांच का अनूठा संगम समेटे यह स्थल आज भी अपने सुनहरे भविष्य की प्रतीक्षा कर रहा है।
> **खीम सिंह बिष्ट,** स्थानीय नागरिक

> मजुवा टाप को पर्यटन मानचित्र से जोड़ने के प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पूर्व में प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। यह अत्यंत रमणीक स्थल है, जहां धार्मिक और साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं।
> **पीके गौतम,** जिला पर्यटन अधिकारी, बागेश्वर

ऐसे पहुंचें मजुवा टाप : काठगोदाम और हल्द्वानी तक रेल व बस सेवा से आप पहुंच सकते हैं। यहां से अल्मोड़ा होते हुए 162 किलोमीटर दूर बागेश्वर तक बस, टैक्सी से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद टैक्सी से कपकोट। वहां से कर्मी गांव के पास मजुवा टाप स्थित है। हल्द्वानी से गरुड़ तक हेली सेवा भी शुरू हो चुकी है। बागेश्वर से कर्मी गांव की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है।

कुमाऊंनी व्यंजनों का चखें स्वाद

यहां पर होम स्टे की सुविधाएं हैं, जहां आपको घर जैसा महसूस होगा। ठहरने के साथ ही आप दाल-सब्जी, रोटी के अतिरिक्त कुमाऊंनी व्यंजनों में मडुवे की रोटी, तिमुल की सब्जी आदि का स्वाद चख सकते हैं।

बागेश्वर में बागनाथ के भी कर सकते हैं दर्शन

अगर आपके पास समय है तो आप बागेश्वर मुख्यालय में बागनाथ मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। यह सरयू और गोमती नदियों के पवित्र संगम पर स्थित भगवान शिव के व्याघ्रेश्वर स्वरूप को समर्पित धाम है। इसका वर्तमान स्वरूप कुमाऊं नरेश लक्ष्मी चंद द्वारा 15वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहां विशाल मेला लगता है। परिसर में भैरव, दत्तात्रेय, गंगा माई, हनुमान, दुर्गा, कालिका सहित अनेक मंदिर स्थित हैं।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे का 'मिसिंग लिंक' शुरू हुआ, यात्रा में आधे घंटे कम लगेंगे

- खंडाला व लोनावला के बीच 'अडोशी सुरंग' से 'खंडाला एक्जिट' तक का हिस्सा था खतरनाक
- अब चुनौतीपूर्ण घुमावों और ट्रैफिक जाम से यात्रियों को हमेशा के लिए मिल जाएगी मुक्ति
- ब्रिज 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के झोंके को भी झेलने में सक्षम

मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के 'मिसिंग लिंक' परियोजना का शुक्रवार को उद्घाटन किया गया। प्रेट्र »

राज्य ब्यूरो, जागरण • मुंबई

महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे के विकास में शुक्रवार को एक नया अध्याय जुड़ गया। बहुप्रतीक्षित मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे के 'मिसिंग लिंक' परियोजना का उद्घाटन होने से राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण महानगरों मुंबई और पुणे के बीच की दूरी न केवल कम हुई है, बल्कि यात्रा के समय में भी लगभग 30 मिनट की कमी आएगी। मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे देश का पहला एक्सप्रेस वे भी है। इसका निर्माण 1995 में पहली बार बनी शिवसेना-भाजपा सरकार में तब के राज्य के सार्वजनिक निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने कराया था। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह परियोजना इंजीनियरिंग का एक आधुनिक चमत्कार है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की आर्थिक जीवन रेखा को दी गई एक नई गति है। खंडाला घाट के चुनौतीपूर्ण घुमावों और ट्रैफिक जाम से अब यात्रियों को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। परियोजना के निर्माण में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा गया है। आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और आपातकालीन निकास द्वारों से युक्त यह खंड अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस है। अब तक मुंबई-पुणे एक्सप्रेस-वे पर खंडाला और लोनावला के बीच 'अडोशी सुरंग' से 'खंडाला एक्जिट' तक का हिस्सा काफी संकरा और खतरनाक था। मानसून के दौरान भूस्खलन और भारी ट्रैफिक के कारण यहां घंटों जाम लगा रहता था।

650 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना : इसे बनाने के लिए खंडाला-लोनावला की टाइगर वैली के ऊपर लगभग 650 मीटर लंबा केबल स्टे ब्रिज बनाया गया है। इसके खंभों की ऊंचाई 182 से 184 मीटर है। ये ब्रिज न केवल बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना है, बल्कि यात्रियों को विहंगम दृश्य भी प्रदान करते हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद ये ब्रिज 252 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा के झोंके को भी झेलने में सक्षम हैं। यह मार्ग खंडाला घाट के पुराने और खतरनाक घुमावदार रास्तों को पूरी तरह बाईपास कर देता है। मुंबई और पुणे के बीच यातायात के भारी दबाव को देखते हुए इसे आठ-लेन के रूप में बनाया गया है। खास बात यह भी है कि इस मिसिंग लिंक का उपयोग करने वाले यात्रियों को कोई अतिरिक्त टोल भी नहीं देना पड़ेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शनिवार, 02 मई, 2026

दैनिक जागरण

कर्म ही मनुष्य के उत्थान या पतन का कारण बनते हैं

जानलेवा लापरवाही

जबलपुर में बरगी बांध में एक क्रूज के डूबने से नौ पर्यटकों की मौत को केवल हादसे की संज्ञा देना सच से मुंह मोड़ना होगा, क्योंकि यदि पर्याप्त सतर्कता बरती गई होती तो जनहानि से बचा जा सकता था। यह क्रूज इसलिए डूबा, क्योंकि तेज आंधी से वह असंतुलित हो गया, लेकिन किसी के लिए भी समझना कठिन है कि खराब मौसम की सूचना के बाद भी क्रूज का संचालन क्यों किया गया? इससे भी गंभीर प्रश्न यह है कि क्रूज की सुरक्षा के न्यूनतम उपाय भी क्यों नहीं किए गए? क्रूज में लाइफ जैकेट थीं, लेकिन उन्हें पर्यटकों को पहनने के लिए निर्देशित ही नहीं किया गया। हादसे में किसी तरह बचे और बचाए गए लोगों की मानें तो लाइफ जैकेट तब दी गईं, जब क्रूज डूबने लगा। स्पष्ट है अफरातफरी के माहौल में लोगों को या तो उन्हें पहनने का अवसर नहीं मिला होगा या फिर वे उन्हें सही तरह पहन नहीं सके होंगे। क्रूज डूबने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे बचाव दल को लाइफ जैकेट एक बंडल में बंधे मिले। आखिर यह जानलेवा लापरवाही नहीं तो और क्या है? चूंकि बरगी बांध में डूबा क्रूज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की ओर से संचालित किया जा रहा था, इसलिए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। केवल घटना पर शोक जताने या फिर मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने की घोषणा मात्र से कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जानी चाहिए।

मध्य प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि जबलपुर हादसे के लिए जिम्मेदार लोग बचने न पाएं। इसके साथ ही उसे सभी पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय करने चाहिए। इसकी अनदेखी न की जाए कि अतीत में भी राज्य के अन्य पर्यटन स्थलों में हादसे हो चुके हैं और उनमें लोगों की जान गई है। कम से कम तीन हादसे तो पिछले साल ही हो चुके हैं। पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की सुरक्षा के मामले में केवल मध्य प्रदेश सरकार को ही नहीं, अन्य राज्य सरकारों को भी चेतना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थलों में सुरक्षा की कमी के चलते रह-रहकर दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। कुछ ही दिनों पहले मथुरा में यमुना में स्टीमर के पलटने से 15 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। इसी माह के प्रारंभ में हिमाचल के कुल्लू में पर्यटकों से भरी ट्रैवलर नाले में गिरने से चार लोगों की जान गई थी। खराब सड़कों और खतरनाक ढंग से ड्राइविंग के चलते तो प्रायः ही वाहन खाई में गिरते रहते हैं। वास्तव में अपने देश में कहीं पर कभी भी हादसा होने की आशंका बनी ही रहती है। ऐसा आम तौर पर सुरक्षा उपायों की अनदेखी और सतर्कता के अभाव के चलते होता है। यह कहने में हर्ज नहीं कि भारत में हर स्तर पर सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर लापरवाही बरतने का शर्मनाक सिलसिला कायम है।

जान लेती कुप्रवृत्ति

उल्लास के पलों में दिखावे के लिए कानून को ताक पर रखकर हथियारों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति व खुशी प्रकट करने के अमर्यादित आचरण पर अंकुश नहीं लग रहा। उल्लास से तो खुशियां बढ़नी चाहिए, पर हर्ष फायरिंग जैसी घटना से कई बार मातम पसरता है। खतरे को न्योत कर खुशी पाने की कुप्रवृत्ति किसी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती। ताजा मामला उत्तर प्रदेश में मेरठ का है, जहां दुल्हन के स्वागत पर फायरिंग में पड़ोसी की मौत गोली लगने से हो गई। जिनकी मौत हुई, परिवार उनकी ही कमाई पर आश्रित था। एक चूक से पूरा परिवार असमय संकटों से घिर गया। जिस द्वार तक खुशियों की डोली पहुंची थी, वहीं इस कृत्य ने पड़ोस से अर्थी उठवा दी। हर्ष फायरिंग कानूनी अपराध है और इसके लिए सजा का प्रविधान भी है, लेकिन इस पर निषेध के लिए सामाजिक स्तर पर पहल अधिक आवश्यक है। केवल कानून के भरोसे नियंत्रण नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट तक ऐसे मामलों पर चिंता प्रकट कर चुका है। यह कुप्रवृत्ति माहौल को असुरक्षित बनाती है। हम सचेत रहेंगे, तो कोई खुशहाल अवसर विपदा में नहीं बदल सकेगा। झूठी शान तभी जान नहीं लेगी, जब लोगों में कानून का भय होगा। आवश्यक है कि ऐसे मामलों में त्वरित निस्तारण कर सख्त सजा दिलाई जाए ताकि समाज को कठोर संदेश जाए।

> हर्ष फायरिंग की कुप्रवृत्ति माहौल को असुरक्षित बनाती है। मानसिकता बदलेगी तो कोई खुशहाल अवसर विपदा में नहीं बदल सकेगा

आजीविका का संकट बढ़ाएगी बढ़ती गर्मी

आदित्य सिन्हा

गर्मी से रोजगार पर संकट का समाधान आवश्यक है, क्योंकि तेज गर्मी से श्रमिकों के साथ देश की उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है

अवधेश राजपूत

एक हालिया आकलन के अनुसार दुनिया के सौ सबसे गर्म शहरों में से 98 भारत में हैं। भीषण गर्मी अपने साथ तमाम मुश्किलें लाती है। ये मुश्किलें उस तबके के लिए और विकराल बन जाती हैं, जिन्हें आजीविका के लिए खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है। स्वाभाविक है कि उनके समक्ष आजीविका का संकट पैदा होता है, क्योंकि उनके लिए किए जाने वाले उपाय पर्याप्त नहीं होते। इससे न केवल श्रमिकों, बल्कि देश की उत्पादकता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई शोध भी इसी ओर संकेत करते हैं। इस समस्या का समाधान तलाशने की दिशा में इनके निष्कर्षों पर विचार किया जाना चाहिए। इसमें पहला पैमाना शारीरिक पहलुओं से जुड़ा है।

श्री रामचंद्र संस्थान की विद्या वेणुगोपाल, पीके लता और रेखा षणमुगम का 2026 से संबंधित एक अध्ययन 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुआ है। इसमें तमिलनाडु के 11 जिलों के उन 1,560 श्रमिकों की गतिविधियों पर दो वर्ष तक नजर रखी गई, जिन्हें कामकाज के लिए बाहर निकलना पड़ता था। अध्ययन में सामने आया कि गर्मियों के दौरान औसत तापमान 29.9 डिग्री सेल्सियस था, जो 27.5 डिग्री सेल्सियस की अधिकतम बर्दाश्त योग्य सीमा से भी ऊपर था। अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तापमान की इस सीमा से ऊपर निरंतर भारी काम करना असुरक्षित माना जाता है। पर्यवेक्षण समीक्षा के अधीन 88 प्रतिशत श्रमिकों को इस उच्च तापीय परिस्थितियों में काम करना पड़ा। इनमें से 61 प्रतिशत की उत्पादकता में गिरावट दर्ज की गई। भीषण गर्मी के संपर्क में आने वाले श्रमिकों की उत्पादकता में गिरावट की आशंका भी डेढ़ गुना अधिक थी। इनमें 15 प्रतिशत कर्मियों के समक्ष रोजगार छिनने का संकट भी मंडराया, जबकि सर्दियों में उनका प्रतिशत 9.3 ही रहा। दूसरा पहलू वृहद आर्थिक स्तर से जुड़ा है। जर्नल आफ पालिटिकल इकोनमी में सोमनाथन और उनकी टीम का 'उत्पादकता और श्रम आपूर्ति पर तापमान के प्रभाव' शीर्षक से एक शोध प्रकाशित हुआ था। इसमें सूरत के बुनकरों, एनसीआर और हैदराबाद की गारमेंट-सिलाई लाइनों और भिलाई मिल में स्टील शिफ्टों की परिस्थितियों का विश्लेषण किया गया। इसका निष्कर्ष यह था कि तापमान में प्रति डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर वार्षिक फैक्ट्री उत्पादन में लगभग दो प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि यह डाटा 2012 तक का ही है, पर इसके निष्कर्षों का निहितार्थ यह है कि गर्मियों का असर पूंजी या कच्चे माल से अधिक श्रम उत्पादकता पर कहीं गहरा पड़ता है। कामकाजी स्थल के भीतर एयर कंडीशनर उत्पादकता में गिरावट को तो थाम सकता है, पर उपस्थिति को नहीं।

गर्मी का तीसरा पहलू मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा है। इंडिया डेवलपमेंट रिव्यू में 2024 और 2025 के दौरान सामने आया कि दीमापुर में रेहड़ी लगाने वाली 60 प्रतिशत महिलाओं की सब्जियां गर्मियों में एक ही दिन में खराब हो जाती थीं, जबकि सामान्य दिनों में वे दो-तीन चलती थीं। दिल्ली में 11 से 19 जून, 2024 की हीटवेव में 192 बेघर लोगों की मौत हो गई थी। द लैंसेट काउंटडाउन आन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत ने 2024 में भीषण गर्मी के चलते 247 अरब कामकाजी घंटों का नुकसान झेला, जो 1990 के दशक के औसत की तुलना में 124 प्रतिशत अधिक रहा। कृषि क्षेत्र को इसका दो तिहाई और कंस्ट्रक्शन उद्योग को 20 प्रतिशत नुकसान उठाना पड़ा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भीषण गर्मियों के चलते 2030 तक उत्पादकता पर होने वाला आघात आठ करोड़ पूर्णकालिक नौकरियों के बराबर होगा। इसकी सर्वाधिक तपिश कृषि और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों को झेलनी पड़ेगी। भारत में कामकाजी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं क्षेत्रों में है, जहां सीधे गर्मी के संपर्क में ही काम करना पड़ता है। भारत में श्रमबल का करीब 90 प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है और दस प्रतिशत से कम घरों में ही एसी की सुविधा उपलब्ध है।

बढ़ती गर्मियों के चलते रोजगार पर संकट की समस्या का समग्रता में समाधान आवश्यक हो गया है। हमारे यहां कई स्थानों पर दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक काम पर पूरी तरह विराम लगाने का प्रविधान है, जिसे बदला जाना चाहिए। इसके बजाय ऐसी व्यवस्था तय की जाए, जिससे कार्यस्थल पर परिस्थितियों के अनुरूप काम को रोका या आरंभ किया जा सके। मौसमी परिस्थितियों के अनुरूप ही काम का पालियों के समय निर्धारण की लचीली व्यवस्था अस्तित्व में आए। सिंगापुर और यूएई में इसी प्रकार का तंत्र प्रभावी है। दूसरा एक उपाय यह हो सकता है कि पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित व्यवस्था के जरिये असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को भी सुरक्षा आवरण प्रदान किया जाए। गुजरात में सक्रिय संस्था स्व-रोजगार महिला संघ (सेवा) की प्रायोगिक परियोजना इस दिशा में उपयोगी हो सकती है। उद्योग जगत के लिए भी किसी अनिश्चित देनदारी की तुलना में एक छोटा और पूर्व-निर्धारित प्रीमियम चुकाना कहीं अधिक आसान और व्यावहारिक होगा। तीसरा उपाय 'कूल रूफ' यानी ठंडी छतों को आवास और औद्योगिक संहिताओं के एक अनिवार्य हिस्से के रूप में शामिल करने से जुड़ा है। अहमदाबाद की पहल ने मात्र 50 रुपये प्रति वर्ग फुट की लागत पर तापमान को पांच डिग्री सेल्सियस तक कम किया है। पीएम आवास योजना इस लागत का बोझ उठा सकती है। कारोबारी सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सीएसआर का भी इसमें सहयोग लिया जा सकता है। केंद्रीय बजट में गर्मियों के लिए तैयारी से जुड़े उपायों को भी चिह्नित कर उन्हें प्राथमिकता दी जाए, जैसे जेंडर बजट और सतत विकास लक्ष्यों के विषय में किया जाने लगा है। गर्मियां जिस तरह श्रमिकों के हितों पर आघात करती जा रही हैं, उससे उनकी सुरक्षा के हरसंभव उपाय करने ही होंगे।

(लेखक लोक-नीति विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

ओपेक के हाथ से फिसलता तेल बाजार

राशिद सिद्दीकी

यूएई का ओपेक से अलग होना उत्पादन कोटे पर मतभेदों का नहीं, ऊर्जा संप्रभुता की बदलती परिभाषा का संकेत है

ओपेक यानी तेल निर्यातक देशों के संगठन का उदय तेल उत्पादक देशों की उस आकांक्षा से हुआ था, जिसके केंद्र में अपने संसाधनों, उत्पादन और आय पर अधिक नियंत्रण हासिल करने की इच्छा थी। 1960 में जब ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने बगदाद में इस संगठन की स्थापना की, तो उनका उद्देश्य केवल तेल की कीमतों को प्रभावित करना नहीं था। इसके साथ वे उस वैश्विक व्यवस्था को भी बदलना चाहते थे, जिसमें तेल उत्पादक देशों के पास संसाधन तो थे, लेकिन कीमत, उत्पादन और आय पर प्रभाव विदेशी कंपनियों एवं उपभोक्ता देशों का था। इस पृष्ठभूमि में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ओपेक और ओपेक प्लस से अलग होने को केवल उत्पादन कोटे पर मतभेद या क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के रूप में देखना अधूरा होगा। यह ऊर्जा संप्रभुता की बदलती परिभाषा का संकेत है। 1960 में तेल उत्पादक देशों के लिए मंच बनाना जरूरी था, पर आज यूएई जैसे देशों को अपना हित स्वतंत्र निर्णय लेने में है। ओपेक ने तेल उत्पादक देशों को सामूहिक शक्ति दी थी। यूएई अब वही नियंत्रण सामूहिक उत्पादन सीमाओं के बजाय अपनी क्षमता, अवसंरचना और दीर्घकालिक राष्ट्रीय रणनीति के आधार पर हासिल करना चाहता है।

ओपेक की ऐतिहासिक भूमिका निर्विवाद है। उसने तेल उत्पादक देशों को अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों और बड़े उपभोक्ता देशों के सामने सामूहिक शक्ति दी। 1970 के दशक में तेल केवल व्यापारिक वस्तु नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति का केंद्रीय तत्व बन गया। सऊदी अरब ने अपने भंडार और उत्पादन क्षमता के कारण इस व्यवस्था में विशेष स्थान बनाया, पर आज तेल बाजार पहले जैसा नहीं है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है। रूस, कनाडा, ब्राजील, गुयाना और अन्य गैर-ओपेक तेल उत्पादक देश वैश्विक आपूर्ति को प्रभावित कर रहे हैं। 2016 में ओपेक प्लस का विस्तार इसी बदली वास्तविकता की स्वीकृति था।

ओपेक अप्रासंगिक तो नहीं हुआ, लेकिन तेल बाजार अब उसकी मूल संरचना से आगे निकल चुका है। यूएई की रणनीति भी इसी से जुड़ी है। वह केवल तेल निर्यातक देश बनकर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह ऊर्जा, लाजिस्टिक्स, वित्त, तकनीक और वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। तेल उत्पादन सीमा से बंधे रहना उसकी व्यापक राष्ट्रीय रणनीति से मेल नहीं खाता। उसके लिए यह केवल तेल उत्पादन का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़ा प्रश्न है। दुनिया में तेल की मांग अभी समाप्त नहीं हुई है, पर वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे विद्युतीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु नीतियों की ओर बढ़ रही है। ऐसे में कम लागत पर तेल निकालने वाले देशों के सामने बड़ा प्रश्न है कि क्या वे कीमतों को ऊंचा बनाए रखने के लिए उत्पादन सीमित रखें या अपने संसाधनों को समय रहते आय में बदलकर भविष्य की तैयारी करें? यूएई का झुकाव दूसरे विकल्प की ओर दिखाई देता है। ईरान-अमेरिका तनाव और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास की अस्थिरता ने इस सोच को और प्रासंगिक बना दिया है। पाइपलाइन अवसंरचना के कारण यूएई के पास सीमित ही सही, लेकिन ऐसा विकल्प है, जो संकट के समय खरीदारों को अतिरिक्त भरोसा देता है। इसका महत्व एशिया के लिए विशेष है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अब केवल तेल उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसकी दिशा प्रभावित करने वाले बड़े आयातक हैं। उनकी मांग, रिफाइनिंग क्षमता और दीर्घकालिक अनुबंध तेल उत्पादक देशों की रणनीति को प्रभावित करते हैं। यदि यूएई अधिक लचीला और भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता बनता है, तो एशियाई देशों की आपूर्ति सुरक्षा मजबूत हो सकती है और ऊर्जा कीमतों से जुड़ा आर्थिक दबाव कुछ कम हो सकता है।

ओपेक के एक आयोजन में यूएई की भागीदारी। एएफपी

अमेरिका ऐसी व्यवस्था को सकारात्मक मान सकता है, जिसमें तेल बाजार पर कुछ सीमित उत्पादकों का प्रभाव कम हो। रूस के लिए यह बदलाव मिश्रित है। सऊदी अरब के लिए यूएई का निर्णय चुनौती है, लेकिन इसे क्षेत्रीय टकराव का नाम देना सही नहीं होगा। सऊदी अरब अपने तेल भंडार और उत्पादन क्षमता के कारण हमेशा महत्वपूर्ण बना रहेगा। यूएई का कदम इस तरफ इशारा करता है कि खाड़ी की ऊर्जा राजनीति अब अधिक विविध हो रही है। अब खाड़ी देश अपनी-अपनी ऊर्जा प्राथमिकताओं के अनुसार अलग रास्ते अपना सकते हैं।

चूंकि कई देश अब भी ओपेक को उपयोगी मानते हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर सदस्य देशों के बाहर निकलने की संभावना कम है। फिर भी यूएई का कदम दिखाता है कि ओपेक पहले की तरह सभी सदस्यों को एक समान उत्पादन नीति में बांधकर नहीं रख पाएगा। ईरान के संदर्भ में भी संतुलन जरूरी है। उसके पास बड़े ऊर्जा संसाधन हैं, पर प्रतिबंधों और निवेश की कमी ने उसकी क्षमता सीमित कर दी है। ओपेक कमजोर होगा तो ईरान और खाड़ी देशों के बीच संवाद का एक मंच कमजोर पड़ सकता है। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि भविष्य में क्या कोई बदलाव ओआइसी और अरब लीग जैसे संगठनों में भी होंगे?

(दुबई में रह रहे लेखक इस्लामी मामलों और पश्चिम एशिया के विशेषज्ञ हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मनुष्य जीवन

मनुष्य का जन्म केवल जीवन जीने का नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और सत्य का बोध करने का सुनहरा अवसर है। इस जीवन में मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान को समझ सकता है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानकर अपने अस्तित्व को सार्थक बना सकता है। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। आत्मा जन्म-मरण के चक्र में बार-बार शरीर धारण करता रहता है। इस आवागमन से मुक्ति ही मोक्ष है, और यही मुक्ति पाने का सर्वोत्तम अवसर मानव जन्म में मिलता है। यदि हम इस अनमोल अवसर को व्यर्थ गंवा दें, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? हीरे समान इस जीवन को यदि हम कौड़ी के भाव गंवा दें, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। जब हम सत्य की ओर कदम नहीं बढ़ाते और अपने जीवन की मंजिल को नहीं पहचानते, तब हम स्वयं अपने दुर्भाग्य के कारण बनते हैं। अक्सर लोग सुख-दुख और भाग्य का आकलन सांसारिक मानकों से करते हैं-धन, संपत्ति या प्रतिष्ठा के आधार पर, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। दुर्भाग्य उस व्यक्ति का है, जो इस दुर्लभ मानव जन्म को पाकर भी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझता और केवल सांसारिक मोह-माया में उलझा रहता है। संत कबीर साधारण जीवन जीते थे, फिर भी उनसे अधिक भाग्यशाली कौन हो सकता है? उन्होंने उस आध्यात्मिक संपदा को प्राप्त किया, जिसके सामने सांसारिक वैभव तुच्छ प्रतीत होता है।

मानव जीवन हमें इसलिए मिला है कि हम अपने जीवन को संवार सकें, आत्मिक उन्नति कर सकें और परम सत्य की प्राप्ति कर सकें। हर व्यक्ति के भीतर यह संभावना निहित है कि वह अपने जीवन का कल्याण कर सके। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम अपने भीतर उस भावना, उस जागरूकता और उस साधना को विकसित करें, जो हमें इस परम लक्ष्य तक पहुंचा सके।

मुकेश ऋषि

भोजन की बर्बादी से पैदा होती समस्याएं

रंजना मिश्रा

जब हम खाना फेंकते हैं, तो उसे उगाने में इस्तेमाल हुए पानी, मिट्टी, उर्वरक और ईंधन को भी बर्बाद करते हैं

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) की हालिया 'फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट' के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 78.2 मिलियन टन (यानी 7.82 करोड़ टन) भोजन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है। प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो हर भारतीय सालाना औसतन 55 किलो खाना बर्बाद कर रहा है। यह बर्बादी सिर्फ थाली में बचाए गए जूठन तक सीमित नहीं है। हमारे यहां शादियों, सामाजिक समारोहों और बड़े आयोजनों में जिस तरह से भोजन का दिखावा होता है, वह इस समस्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।

हालांकि भारत में भोजन की बर्बादी का ठीकरा सिर्फ उपभोक्ताओं के सिर नहीं फोड़ा जा सकता। इस बर्बादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे खेतों से लेकर मंडियों और अंततः उपभोक्ताओं तक पहुंचने की लंबी प्रक्रिया में ही नष्ट हो जाता है। आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की कमियां, कोल्ड स्टोरेज का अभाव, वैज्ञानिक भंडारण की कमी और लचर परिवहन व्यवस्था के कारण हर साल लाखों टन ताजे फल, सब्जियां और अनाज सड़ जाते हैं। यह न केवल किसान की मेहनत और पूंजी की बर्बादी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा आघात है। इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। अनुमान है कि भारत में हर साल डेढ़ लाख करोड़ रुपये से अधिक का कृषि उत्पाद उचित रखरखाव के अभाव में बर्बाद हो जाता है। जब हम खाना फेंकते हैं, तो हम सिर्फ उस भोजन को नहीं फेंक रहे होते, बल्कि उसे उगाने में इस्तेमाल हुए हजारों लीटर पानी, उपजाऊ मिट्टी, महंगे उर्वरक और परिवहन में जले ईंधन को भी हमेशा के लिए बर्बाद कर रहे होते हैं। इसके अलावा, लैंडफिल या कचरा ढलाव घरों में सड़ता हुआ यह भोजन भारी मात्रा में मीथेन गैस पैदा करता है। मीथेन कार्बन डाइआक्साइड से कई गुना अधिक खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है, जो ग्लोबल वार्मिंग को तेजी से बढ़ा रही है। यूएनईपी की रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में लगभग 8 से 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी इसी बर्बाद हुए भोजन की है।

इस महासंकट से निपटने के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की तत्काल आवश्यकता है। सरकार को जहां एक ओर कृषि अवसंरचना, कोल्ड चेन नेटवर्क और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को मजबूत करने के लिए भारी निवेश करना होगा, वहीं दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता की एक बड़ी लहर की जरूरत है। हमें विवाह और समारोहों में अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए सामाजिक नैतिकता के नियम तय करने होंगे। 'फूड बैंक' की अवधारणा को और अधिक विस्तार देने की जरूरत है, ताकि बचा हुआ सुरक्षित भोजन कचरे में जाने के बजाय तुरंत जरूरतमंदों, अनाथालयों या रैन बसेरों तक पहुंचाया जा सके।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

मेलबाक्स

भय और असुरक्षा का माहौल

संपादकीय 'साइबर ठगों के साथी' पढ़ा। आज डिजिटल युग में तकनीक ने जहां जीवन को सरल बनाया है, वहीं साइबर अपराधों ने आम नागरिकों की मेहनत की कमाई पर सबसे बड़ा खतरा खड़ा कर दिया है। सरकार, बैंक और विभिन्न एजेंसियों द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाने तथा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के बावजूद साइबर ठग नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को झांसे में ले रहे हैं। दुखद स्थिति यह है कि कई मामलों में लोग एक ही फोन काल, लिंक या फर्जी संदेश के माध्यम से अपनी जीवनभर की जमा पूंजी कुछ ही मिनटों में गंवा देते हैं। यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और मानसिक शांति पर भी गहरा आघात है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई घटनाओं में बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत की बातें सामने आती हैं। जिन संस्थाओं और कर्मचारियों पर जनता अपनी गाढ़ी कमाई की सुरक्षा का भरोसा करती है, यदि वहीं लोग अपराधियों के साथ मिल जाएं तो स्थिति और भयावह हो जाती है। रक्षक का भक्षक बन जाना किसी भी व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। कुछ कर्मचारी लालच में आकर ग्राहकों की गोपनीय जानकारी अपराधियों तक पहुंचाने, फर्जी खातों को सक्रिय करने या संदिग्ध लेनदेन को नजरअंदाज करने जैसे कार्यों में शामिल पाए गए हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। आज आवश्यकता केवल जागरूकता अभियान चलाने की नहीं, बल्कि कठोर और त्वरित कार्रवाई की भी है। साइबर अपराधियों के साथ-साथ उनके सहयोगियों पर भी सख्त कानून लागू होने चाहिए। बैंकों की जवाबदेही तय होनी चाहिए तथा कर्मचारियों की नियमित निगरानी और प्रशिक्षण आवश्यक है। साथ ही आम नागरिकों को भी अनजान लिंक, काल और ओटीपी साझा करने से बचना होगा। साइबर अपराध अब केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक विश्वास से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है। यदि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो डिजिटल सुविधा का लाभ उठाने के बजाय लोग भय और असुरक्षा के माहौल में जीने को मजबूर हो जाएंगे।

सुशील कुमार बत्तरा, मेरठ

इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक नैरेटिव

इंटरनेट मीडिया पर इन दिनों एक भ्रामक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को रोककर विपक्ष ने करदाताओं पर अहसान किया है, क्योंकि इससे दोनों सदनों में सांसदों की एवं राज्य विधानमंडलों में विधायकों की संख्या बढ़ती और इससे सरकारी खर्च दोगुना हो जाता। कहा जा रहा है इससे जनता को कोई फायदा नहीं होता, केवल राजनीतिक दलों को होता। यह तर्क न केवल सतही है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक भी है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि लोकतंत्र केवल लागत का सवाल नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व और भागीदारी का प्रश्न है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में समाज के हर वर्ग को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना लोकतंत्र का आत्मा है। यदि महिलाओं, जो आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं, को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो यह लोकतंत्र की अधूरी तस्वीर होगी। यह कहना कि सांसदों की संख्या बढ़ने से केवल खर्च बढ़ेगा और जनता को कोई लाभ नहीं होगा, एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। वास्तव में, अधिक प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि अलग-अलग क्षेत्रों और वर्गों की समस्याएं अधिक प्रभावी ढंग से संसद में उठेंगी। महिला सांसदों की बढ़ती संख्या से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और संतुलित नीतियां बन सकती हैं। भारत का संविधान सहभागिता, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों पर आधारित है, न कि केवल लागत-लाभ विश्लेषण पर। यह भी विचारणीय है कि यह नैरेटिव अचानक क्यों उभरा। इसे एक नादान अभियान समझने की भूल न करें।

pramodkgoelpnb2014@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

7 अरब डालर तक पहुंच सकता है विश्व में डबिंग का कारोबार वर्ष 2033 तक, जो वर्तमान में लगभग चार अरब डालर है, ग्लोबल ग्रोथ इंसाइट की फिल्म डबिंग मार्केट रिपोर्ट के अनुसार। भारत में भी पोस्ट-प्रोडक्शन और डबिंग सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है।

आजकल

डा. विकास सिंह
मैनेजमेंट गुरु तथा वित्तीय एवं समग्र विकास के विशेषज्ञ

दीर्घकालिक विकास में बाधक 'मुफ्त' की नीति

देश के अधिकांश राज्यों में चुनावों के दौरान तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अनेक चीजें मुफ्त प्रदान करने का वादा करते हैं। पिछले एक दशक से इस प्रवृत्ति में व्यापक वृद्धि हुई है। चिंताजनक यह कि इसका दुष्प्रभाव राज्यों की अर्थव्यवस्था पर दिखने भी लगा है। हालांकि मतदाता भी अब यह समझने लगे हैं कि दीर्घकालिक विकास के लिए यह प्रवृत्ति बहुत घातक साबित हो सकती है। फिर भी जिस प्रकार से मुफ्त की चीजें सामान्य होती जा रही हैं, उससे वे अब उन्हें अधिकार के रूप में समझने लगे हैं। ऐसे में इस बारे में सरकार और मतदाता- दोनों को ही नए सिरे से विचार करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के ढांचे को विकसित करने से अधिक आबादी को होगा लाभ। फाइल

भारत के नागरिकों को अब पता चल रहा है कि राजनीति में 'मुफ्त' एक बहुत ही महंगा शब्द बनता जा रहा है। भारतीय राजनीति का सबसे लुभावना शब्द आज 'विकास' या 'सुधार' नहीं है, वह है मुफ्त। मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, मुफ्त पानी, मुफ्त नकद हस्तांतरण। मुफ्त ऋण माफी। यह सही है कि इसमें राजनेताओं को तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है, लेकिन इसमें छिपे अंकगणित की आवाज को कोई नहीं सुन पाता है।

यह बहुत ही चिंताजनक है कि भारत के राज्य आज को जीतने के लिए कल को खर्च कर रहे हैं। परंतु अर्थशास्त्री इसे भलीभांति जानते हैं कि मुफ्त का कोई अस्तित्व नहीं- यह केवल टाली हुई कर वसूली है। लेकिन अधिकांश नागरिक इसे नहीं जानते हैं। वास्तव में 'मुफ्त' की नीति भविष्य की कमाई पर एक प्रकार से स्थायी दावा की तरह है, जो साल दर साल ब्याज भुगतान, कहीं और कटौती, या चुपचाप बढ़ते कर्ज से चुकाया जाता है। स्कूलों, स्वास्थ्य व्यवस्था, लाजिस्टिक्स और शहरी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दौड़ के बजाय, कई सरकारें उपहार और संकीर्ण रियायतों की होड़ में हैं।

आज का लाभ, कल की हानि : यह समझना होगा कि राज्य जब 10 हजार करोड़ रुपये की माफी की घोषणा करता है, तो वह अमूर्त लगती है। इसमें से पांच-छह करोड़ रुपये तक नागरिकों में बंटता है, लेकिन प्रति व्यक्ति बोझ तुच्छ प्रतीत होता है। हालांकि सार्वजनिक वित्त घरेलू खाते की तरह नहीं चलता। सरकारें नुकसान 'समाहित' नहीं करतीं, उन्हें आगे बढ़ाती हैं। उधार से वित्तपोषित माफी राजनीतिक कार्यकाल से कहीं लंबे समय तक ब्याज की धारा बन जाती है। बिना समय सीमा वाली सब्सिडी संरचनात्मक खर्च बन जाती है। सुधार का उलटफेर भविष्य के करदाताओं पर दायित्व थोपता है, जिन्होंने कभी सहमति नहीं दी। राज्य बजटों की संरचना पर गौर करें तो पिछले दशक में राजस्व व्यय- वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान और सब्सिडी आदित ने पूंजीगत व्यय को धीरे-धीरे किनारे कर दिया है। यहां तक कि बेहतर प्रबंधित राज्यों में भी आधे से ज्यादा बजट प्रतिबद्ध दायित्वों पर खर्च होता है। जहां पापुलिस्ट खर्च सबसे आक्रामक है, वहां ब्याज भुगतान अकेले राजस्व का पांचवां हिस्सा निगल लेते हैं। यह उदारता नहीं, पूर्वाग्रह है। विडंबना यह कि वोटर शायद ही देख पाते हैं उस अस्पताल को जो नहीं बना, उस कक्षा को जो नहीं सुधरी, उस जल प्रणाली को आगे नहीं बढ़ सकी, क्योंकि कल के वादे उन्हें अधिक आकर्षित करते हैं।

बुनियादी ढांचा परियोजना : कई मामलों में गलत आवंटन केवल वितरण तक सीमित नहीं है। इसे कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भी देखा जा सकता है, जहां प्रतीकात्मकता सामाजिक प्रतिफल से कहीं ऊपर है। हमारे देश में बन रहा हाई-स्पीड रेल इसका उदाहरण है। हालांकि यह अच्छी बात है कि हमारे देश में भी इस प्रकार की रेल लाइन बन रही है जो तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों और वस्तुओं को ले जाने में सक्षम होगी, परंतु ऐसी रेल लाइन अपेक्षाकृत धनी यात्रियों के हित में होगी, जबकि उसका पूंजीगत खर्च और कर्ज सेवा पूरे कर आधार पर सामाजिकृत होगा- राज्य और देश के हर नागरिक पर। इसमें ऐसे लोग भी होंगे तो अपने पूरे जीवनकाल में कभी उस रेल की यात्रा ही न कर पाएं।

वैसे यह बुनियादी ढांचे के खिलाफ तर्क नहीं। एक ऐसे देश में जहां शहरी परिवहन अपर्याप्त फंडिंग का शिकार है, जहां रेल और बसें रोज करोड़ों लोगों की सेवा करती हैं, और जहां बुनियादी लाजिस्टिक्स छोटे उत्पादकों के लिए लागत बढ़ाती रहती है, केवल कुछ चुनिंदा लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना या उन्हें प्राथमिकता देना सही नहीं है। जबकि धनी देश सार्वभौमिक आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के बाद इस तरह की परियोजनाएं बनाते हैं, जिससे सबको मजबूती मिल सके।

ताकतवरों को माफी, गरीबों के लिए कठोरता : राजनीतिक रूप से सबसे प्रभावी मुफ्तखोरी वह नहीं जो सबसे गरीबों के लिए है, बल्कि वह है जो संगठित वर्गों के लिए है। किसान ऋण माफी को संकटग्रस्त खेतिहरों के लिए राहत के रूप में पेश किया जाता है। व्यवहार में कई अध्ययन दिखाते हैं कि हाशिए के किसान जो अक्सर औपचारिक ऋण से बाहर होते हैं, वे अपेक्षाकृत इससे कम लाभान्वित होते हैं। इसके सबसे बड़े लाभार्थी जमींदार हैं, जिनके पास बैंकों तक बेहतर पहुंच होने के साथ राजनीतिक रसूख कायम है।

अल्पकालिक राजनीतिक लाभ लंबे समय का ऋण संकुचन पैदा करता है। इसका खामियाजा यह होता है कि बिल भविष्य के उधारकर्ताओं को चुकाना पड़ता है। यही तर्क कारपोरेट रियायतों पर भी लागू होता है। जब सरकारें बड़े नियामक बकाया माफ करती हैं या बैलआउट देती हैं, तो दायित्व गायब नहीं होता। एक प्रकार से वह सामाजिकृत हो जाता है। मुनाफा निजी रहता है, जबकि नुकसान सबको उठाना पड़ता है। औचित्य अक्सर प्रणालीगत जोखिम का होता है। प्रभाव अक्सर नैतिक खतरे का। एक बार बाजार सीख जाते हैं कि आकार छूट दिलाता है, अनुशासन ढीला पड़ जाता है।

पेंशन : गलत प्राथमिकताओं का सबसे खराब उदाहरण पेंशन सुधार का उलटफेर है। कई राज्य योगदान-आधारित पेंशन प्रणालियों को पुराने-शैली के निश्चित-लाभ योजनाओं के पक्ष में रद्द कर चुके हैं। सरकारी कर्मचारी देश की आबादी का मुश्किल से दो प्रतिशत हैं। इसमें पेंशनभोगियों को शामिल करें, जैसा कि राजकोषीय दायित्व मांगते हैं तो लाभार्थी समूह बड़ा हो जाता है। उन्हें नौकरी की सुरक्षा, नियमित वेतन और सूचकांकित लाभ मिलते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र कार्यबल का 90 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा होने के बावजूद अभी तक संगठित रूप से पेंशन के दायरे से बाहर ही है। असल में, देश के लगभग 95 प्रतिशत नागरिकों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है।

छिपे हुए कर का बोझ : यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि हर मुफ्तखोरी एक छिपा हुआ कर ढोती है। कभी भविष्य के ऊंचे करों के रूप में, कभी खराब सार्वजनिक सेवाओं के रूप में। यही कारण है कि सड़कों का समय पर मरम्मत नहीं किया जाता, अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी दिखती है। सुविधाओं के अभाव में स्कूलों में बच्चे कुछ नया नहीं सीख पाते हैं। शहरी व्यवस्थाएं विस्तार नहीं ले पाती हैं। इसलिए योजनाओं का निर्धारण किए जाते समय रकम का आवंटन इस हिसाब से किया जाना चाहिए ताकि उससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। यदि अपेक्षाकृत अधिक रकम के आवंटन से कम लोगों को उसका लाभ हो और उनके जीवन स्तर में सुधार होने की संभावना हो, तो इन योजनाओं की नए सिरे से समीक्षा की जानी चाहिए।

अधिकतम लोगों तक पहुंचे लाभ का दायरा

देश के कई राज्यों में विविध राजनीतिक दलों की ओर से चुनावों के दौरान ऐसे अनेक वादे किए जाते हैं, जिनके लिए धन का इंतजाम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण से कई राज्यों में पिछले दशक में कुल राज्य कर्ज लगातार बढ़ा है। यहां तक कि कुछ राज्यों में अनेक प्रकार के पूंजीगत खर्चों में कटौती भी की जा रही है। कई बड़े राज्य अब अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत से ऊपर कर्ज ढो रहे हैं। राजस्व घाटे निवेश के बजाय उपभोग फंड करने के लिए उधार- अब सामान्य हो गए हैं, जबकि पहले इन्हें असाधारण घटना के रूप में समझा जाता था। कुछ राज्य अपने नागरिकों को जीवन जीने के लिए आवश्यक खपत से कहीं अधिक मुफ्त या लगभग मुफ्त बिजली देते हैं, जो बिजली विभागों पर नुकसान थोपते हैं। इसका खामियाजा अंततः राज्य के खजाने को भुगतना पड़ता है। कई राज्य नागरिकों को मुफ्त सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से सेवा गुणवत्ता बिगड़ती जाती है। नकद हस्तांतरण योजनाएं अस्थायी राहत को स्थायी बनाने का हक बना देती हैं। ऐसे में सरकारों को इस तरह की योजनाओं के लिए कोई समयसीमा भी तय करनी चाहिए।

इस मामले में यदि दक्षिणी यूरोप के एक उदाहरण को समझने का प्रयास करें तो वह एक चेतावनी की कहानी पेश करता है। वस्तुतः इस सदी के आरंभिक दशक में ग्रीस में उप-राष्ट्रीय इकाइयों ने दायित्व चुपचाप जमा किए- उदार पेंशन, अधिक कर्मचारी और कम कीमत वाली सेवाओं के माध्यम से। इसका परिणाम बहुत बेहतर रहा। सभी प्रकार के ठहरे हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े। अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार के अविश्वास का संकट पैदा हो गया था, उसे दूर किया गया। इस प्रकार संकट में भी यह देश देश आगे बढ़ा। इस उदाहरण से यह भी समझा जा सकता है कि नरम बजट बाधाएं राजकोषीय साहसिकता को बढ़ावा देती हैं। दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी यूरोप का सबक साफ हैः उप-राष्ट्रीय कर्ज संकट स्वयं को नाटकीय ढंग से घोषित नहीं करते। वे चुपचाप आते हैं- विलंबित भुगतान, रुके प्रोजेक्ट्स और गिरती सेवा गुणवत्ता से। जब घबराहट पसरती है, तब विकल्प सीमित रह जाते हैं।

इस तरह की स्थितियां पैदा होने पर अमेरिका भी विशेष व्यवस्था करता है। देखा गया है कि मंदी के दौरान वाशिंगटन नियमित रूप से राज्य बजटों में ऐसे कई प्रविधान करता है, जिसका लाभ निचले स्तर तक अधिक से अधिक लोगों को मिल पाता है। भारत को भी इस तरह की नीतियों से सीखना होगा यानी रकम का आवंटन ऐसे करना होगा जिसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचे।

(डा. विकास सिंह)

खरी-खरी

बिल की तलाश

प्रकाश हेमावत

विभाग में पहले "मांगीलाल" की कृपा से बिल साधारण रूप से पास हो जाता था। मेरा बिल, बिल है किसी का दिल नहीं है जिसके टुकड़े-टुकड़े कर दो। उसमें मेरे द्वारा किए गए मेहनती कार्यों का अर्थ रकम के रूप में खून-पसीना छिपा हुआ है। इस बार बिल पास करवाने के लिए मुझे तपस्या क्यों करनी पड़ रही है।

पीडब्ल्यूडी आफिस में बड़े बाबू की टेबल के सामने बैठे झलक दादा अपने दर्द की कथा सुन रहे थे।

धीरज धरें दादा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं।

पीडब्ल्यूडी आफिस से झलक सिंह का सड़क बनाने का बिल गायब हो गया। विभाग की जिस टेबल पर बिल पास करने के लिए रखा था, उस टेबल पर कोई "परिंदा" भी पर नहीं मार सकता है तो फिर झलक दादा का बिल कैसे गायब हो गया?

बिल पास करने वाले बाबू साहब का विभाग में रुतबा और दबदबा देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इनके आगे ये सभी बातें केवल बातें हैं और इन बातों का क्या अर्थ है? लेकिन, इनके चक्कर में झलक सिंह का रुपये वाला अटका हुआ बिल विभाग से गायब हो गया। अब इस बिल को ढूंढने के लिए मुझे किस प्रकार का अर्थ कहां, कब, किस वक्त, कैसे लगाना होगा इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन लगता है। किसी अर्थ की वजह से अगर सही अर्थ लगाने से मेरे बिल का अर्थ इनको समझ में आ जाए तो सोने पे सुहागा जैसी बात होगी और मेरे कुछ सांकेतिक अर्थ समझकर इसका हल निकाल कर सार्थक परिणाम सामने आ जाएं तो मैं गंगा नहा जाऊं।

आखिरकार कई महीने बीत जाने के बाद भी बिल पास नहीं होने पर विभाग और देवताओं पर झलक दादा का अटूट विश्वास बना हुआ था, वह नव निर्मित पुल की तरह टूटता हुआ दिखाई देने लगा? बिल कहीं चोरी तो नहीं हो गया? कहीं किसी फाइल में गुम, किसी ने दबा तो नहीं दिया होगा? बाबू जी के कुभाव से बिल के कई सपने आंखों के सामने दिखाई देने लगे। झलक दादा बिल के बारे में हुई सभी बातचीत का घटनाक्रम का चिंतन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जैसे तैसे मेरा बिल पास करवा देना तो मैं आपको हजार रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा।

X पोस्ट

आज जब दुनिया अपने इतिहास के सबसे उथल-पुथल भरे दौर से गुजर रही है, तब अमेरिका में सभी प्रकार की विचारधाराएं और नैरेटिव एक साथ विकसित हो रही हैं-बिना किसी दंड या प्रतिशोध के भय के। यही एक विशेषता अमेरिका को दुनिया के अन्य देशों से आगे बनाए रखेगी।

आरती टिक्कू सिंह@AartiTikoo

आज हमारे देश की राजनीति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ में निवेश और आर्थिक विकास राजनीतिक दलों को वोट नहीं दिलाते, जबकि मुफ्त की योजनाएं दिलाती हैं। जब देश में विकास की तुलना में रियायतें अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो उसका भविष्य खतरे में पड़ जाता है।

हर्ष गोयनका@hvgoenka

सरकार के पास जितने फ्लोर तक आग बुझाने और बचाव के साधन हों, उतने फ्लोर तक ही टावर या अपार्टमेंट बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी में सबकी भलाई है।

नवनीत मिश्र@navneetmishra99

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या बंगाल में भारी मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है?

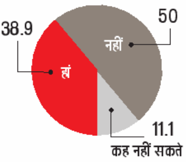

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में वृद्धि से महंगाई बढ़ने की आशंका है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

सुनकर एक्जिट पोल तो सूंघ गया है सांप,
करके 'कल की' कल्पना लोग रहे हैं कांप।
लोग रहे हैं कांप पाप का घड़ा भर गया,
ममता जी का खेत स्वयं का अहं चर गया!
बैठी थीं निश्चिन्त सुनहरे सपने बुनकर,
आया एक्जिट पोल हो गईं मूर्छित सुनकर!!

–ओम प्रकाश तिवारी

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार डायरी

शून्य अपराध और पूर्ण विकास का लक्ष्य

बिहार में भाजपा की अगुआई वाली पहली सरकार का कामकाज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की देह भाषा बता रही है कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के काम कर रहे हैं। शून्य अपराध और पूर्ण विकास सरकार की प्राथमिकता सूची में है। निश्चित रूप से बिहार के लिए ये दोनों मुद्दे प्रमुख हैं। विकास का मतलब है- उद्योग और रोजगार, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार। एनडीए ने 2025 के विधानसभा चुनाव के अपने घोषणा पत्र में एक करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देने का भरोसा दिया है। यहां नौकरी का अभिप्राय सरकारी नौकरी से होता है। सरकार इतनी नौकरियां दे नहीं सकती है। रोजगार पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

इस साल 20 नवंबर (2025 में नीतीश सरकार का गठन इसी दिन हुआ था) को सरकार सालगिरह मनाएगी। तब तक राज्य में पांच लाख करोड़ रुपये तक के निवेश आ जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि वह एमओयू की बात नहीं कर रहे हैं। ठोस निवेश के बारे में कह रहे हैं। इतनी मोटी रकम के निवेश के लिए सबसे जरूरी जमीन का प्रबंध कर लिया गया है। उनका कहना था कि आंतरिक संसाधनों से अधिक धन जुटाने का लक्ष्य औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ा कर ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने 11 उपनगर बनाने की भी घोषणा की है। इसे भी विकास के लक्ष्य के साथ जोड़ कर देखा जा रहा है।

अच्छी बात यह है कि सम्राट चौधरी तंत्र के जाल को समझते हैं। वह पंचायत से लेकर सचिवालय तक विकास के गतिरोधकों को जानते हैं। उन्हें यह भी पता है कि उद्योगों को गति देने के लिए राज्य में आजतक एकल खिड़की ढंग से क्यों नहीं काम कर पाई? कानून व्यवस्था, भूमि प्रबंधन और विकास के काम सरकार की बुनियादी इकाइयों की सक्रियता पर निर्भर हैं। इसे ध्यान में रखकर सरकार प्रखंड, अंचल और थाना को अधिक जवाबदेह बनाने जा रही है। इन इकाइयों से अगर आम लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो वे सचिवालय तक पहुंच जाते हैं। सरकार की बदनामी अलग से होती है।

जिला पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते सम्राट चौधरी। फाइल

सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों कुछ पत्रकारों से निजी बातचीत में अपना अनुभव साझा किया था। उनके मुताबिक प्रशासन की बुनियादी इकाइयां यदि अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वहन करें तो ऊपर तक शिकायतें नहीं पहुंचती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने शुरुआती कार्यकाल में कुछ ऐसी ही व्यवस्था की थी। अपने लोकप्रिय कार्यक्रम 'जनता के दरबार में मुख्यमंत्री' में वह आम लोगों की शिकायतें सुनते थे। कार्रवाई के लिए जिलों को निर्देश देते थे। इसका अच्छा प्रभाव पड़ा था। सम्राट भी उसी तर्ज पर कार्यक्रम करेंगे। उसका नाम और स्वरूप बदला हुआ होगा।

जनता से फीडबैक लेने का यह अच्छा तरीका साबित हुआ है। मुख्यमंत्री ने सरकारी सेवकों के भ्रष्टाचार पर काबू पाने का निश्चय किया है। इस मामले में भी उन्होंने जड़ की खोज की है। सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण-पदस्थापन जब योग्यता और कार्य क्षमता के बदले अन्य मूल्यों पर होता है तो भ्रष्टाचार पर रोक लगाना संभव नहीं रह जाता है। यह तार्किक भी है। अगर कोई अधिकारी पदस्थापन में निवेश करेगा तो वह वसूली भी करेगा। इसी वसूली के फेर में कार्यपालक नियमावली खंडित हो जाती है। अपराध को भी राज्य के विकास में अवरोधक माना गया है। राज्य में अपराध बेकाबू नहीं है। लेकिन, हत्या की लक्षित वारदातें हो रही हैं। कई मामलों में अपराधियों की शून्य सहनशीलता भी सामने आई है। मामूली झड़प में गोलियां चल जाती हैं। तीन दिन पहले सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हुई। पुलिस ने 14 घंटे के भीतर रामधनी यादव नामक एक अपराधी को ढेर कर दिया।

गुरुवार को सिवान में एक अपराधी को पुलिस ने गोली मार कर लंगड़ा कर दिया। अपराध नियंत्रण के लिए यह तरीका लोकप्रिय नहीं है। लेकिन, अपराधियों का मनोबल तोड़ने के लिए सीमित रूप से इसे कारगर भी माना जाता है। राज्य की सामाजिक संरचना और विमर्श की यह विशेषता है। लोग शांति चाहते हैं। लेकिन, नेताओं की तरह अपराधियों को भी जाति के नाम पर संरक्षण देते हैं। इस कारण कई दुर्दांत माननीय बन कर विशेषाधिकार का उपयोग कर रहे हैं। अभी रामधनी यादव की एनकाउंटर में मौत पर भी यह विमर्श चल रहा है कि सरकार एक जाति विशेष के अपराधियों को ही क्यों लक्ष्य बना रही है? दूसरी जातियों के दुर्दांतों के नाम गिनाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि पुलिस की गोलियां उन तक क्यों नहीं पहुंचती हैं?

खैर, सरकार के किसी निर्णय की विवेचना राजनीतिक विचार के आधार पर ही होती है। यह सम्राट चौधरी की कार्यशैली के लिए चुनौती है कि वह किस तरह जनता के बड़े हिस्से के विमर्श के केंद्र में सरकार की सकारात्मक छवि के साथ अपनी जगह बनाते हैं। काम करने के लिए उनके पास अभी चार वर्ष से भी अधिक का समय है। वह चाहें तो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लकीर को कुछ और लंबी कर सकते हैं।

मंथन

डा. मुकुल श्रीवास्तव
प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

ओटीटी ने बदली डबिंग की दुनिया

विदेशी भाषाओं की कहानियां आज डबिंग होकर भारत में देखी जा रही हैं। भारतीय कहानियां वैश्विक पहचान बना रही हैं। मनोरंजन वैश्विक संवाद व सांस्कृतिक सेतु का प्रतीक बन रहा है

एक समय था जब डबिंग का मतलब केवल संवादों के शब्दशः अनुवाद से था। विदेशी फिल्मों या धारावाहिकों के संवाद हिंदी में बदले जाते थे, पर उनमें भाव, संदर्भ और सांस्कृतिक अर्थ अक्सर खो जाते थे। भाषा तो बदल जाती थी, लेकिन पात्रों का आत्मा, सामाजिक संकेत और स्थानीय संवेदनाएं अनुवाद की प्रक्रिया में फीकी पड़ जाती थीं। आज की डबिंग इस सीमित दृष्टि से बाहर निकल चुकी है। अब यह केवल भाषा परिवर्तन नहीं, बल्कि स्थानीयकरण और रचनात्मक पुनर्लेखन यानी ट्रांसक्रिएशन का माध्यम बन चुकी है। इस प्रक्रिया में केवल शब्द बदलना नहीं होता, बल्कि भाव-रूप में री-क्रिएशन किया जाता है।

इसलिए कहा जा सकता है कि आधुनिक डबिंग केवल अनुवाद नहीं, बल्कि एक रचनात्मक स्थानिक अनुकूलन बन चुका है। ऐसा नहीं है कि ओटीटी पर डबिंग केवल विदेशी कंटेंट को भारत में लोकप्रिय बना रही है, बल्कि यह भारतीय कंटेंट को भी दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुकी है। सेक्रेड गेम्स ने ओटीटी पर भारतीय कंटेंट की वैश्विक यात्रा की शुरुआत की, जहां अंग्रेजी, स्पैनिश और कोरियन जैसी भाषाओं में डब होकर इसने भारत की राजनीति, अपराध और सत्ता के जटिल यथार्थ को दुनिया के सामने रखा और उसे सार्वभौमिक मानवीय अनुभव के रूप में स्वीकृति मिली।

आज का युवा कोरियन ड्रामा, स्पेनिश थ्रिलर और हाकी सुपरहीरो फिल्में भारतीय घरों में उतनी ही सहजता से देखी जा रही हैं जितने कभी हिंदी धारावाहिक देखे जाते थे। इस बदलाव के केंद्र में सिर्फ ओटीटी प्लेटफार्म ही नहीं, बल्कि डबिंग का वह उभरता हुआ उद्योग भी है, जिसने वैश्विक कंटेंट को स्थानीय अनुभव में बदल दिया है। एक समय फिल्मों का डब होना एक लंबी, महंगी और जुझारू प्रक्रिया होती थी। लेकिन ओटीटी और तेज डबिंग तकनीकों के आने के बाद यह तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। अब फिल्में और वेब सीरीज एक साथ कई भाषाओं में डब होकर रिलीज होती हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता सीमाओं में नहीं बंधती। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कांतारा है, जिसने कन्नड़ में रिलीज होने के साथ ही हिंदी और अन्य भाषाओं में डब होकर देशभर में अपनी मजबूत पहचान बनाई।

भारत जैसे विशाल और भाषाई रूप से विविध मनोरंजन बाजार में क्षेत्रीय भाषाओं की बढ़ती मांग ने इस उद्योग की गति को और तेज कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि अब कंटेंट किसी एक भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया। उदाहरण के तौर पर, साल 2024 में नेटफ्लिक्स ने अपने कंटेंट को दुनिया भर में 34 से अधिक भाषाओं में डब किया, जिनमें भारतीय भाषाओं की हिस्सेदारी उल्लेखनीय रही। भारत का ओटीटी बाजार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। पीडब्लूसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में भारत के ओटीटी बाजार ने 17 हजार करोड़ का आंकड़ा पार किया था, वहीं 2028 में इसके 35 हजार करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस वृद्धि के पीछे सस्ते डाटा पैक्स, बढ़ती इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्थानीय भाषाओं में कंटेंट का उपलब्ध होना प्रमुख कारण हैं।

आर्मैक्स द्वारा प्रकाशित आइबीईएफ रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में भारत में ओटीटी उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 60 करोड़ है जिनमें 14 करोड़ से अधिक पेड सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। वहीं वर्ष 2031 तक भारत का डबिंग बाजार 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारतीय युवा केवल अपनी बोली-संस्कृति के इर्द-गिर्द बने वीडियो कंटेंट तक सीमित नहीं है। वे देश-दुनिया की अन्य संस्कृतियों, भाषाओं में बने कंटेंट को भी बड़े चाव से देख रहे हैं। वहीं ओटीटी और बहुभाषी रिलीज की बढ़ती मांग का प्रत्यक्ष लाभ डबिंग आर्टिस्ट्स को मिला है। ग्लोबल ग्रोथ इंसाइट की फिल्म डबिंग मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में डबिंग का वैश्विक बाजार चार अरब डालर पहुंच गया है जो साल 2033 तक सात अरब डालर तक पहुंच सकता है। भारत में भी पोस्ट-प्रोडक्शन और डबिंग सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण डबिंग आर्टिस्ट्स के लिए अवसर और पारिश्रमिक दोनों में वृद्धि हुई है। इस बदलाव ने उन्हें न केवल स्थिर रोजगार और बेहतर पैकेज दिया है, बल्कि उनके पेशेवर सम्मान और प्रसिद्धि में भी बढ़ोतरी की है।

ओटीटी और डबिंग की इस क्रांति ने यह साबित कर दिया है कि भाषा, सीमा और संस्कृति किसी कहानी को देखने या समझने में बाधक नहीं हैं। दर्शक अब वैश्विक कहानियों को अपने घर की सहजता में अनुभव कर सकते हैं और कलाकार अपनी कला की उपस्थिति दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा सकते हैं। यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं, बल्कि अनुभव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का भी युग है, जहां एक ओर युवा कोरियन, स्पैनिश और हालीवुड कंटेंट का आनंद ले रहे हैं, वहीं भारतीय कहानियां भी बहुभाषी डबिंग के माध्यम से दुनिया भर में अपनी पहचान बना रही हैं।

प्रतीकात्मक

कुल मिलाकर आज का मनोरंजन केवल देखने का माध्यम नहीं, बल्कि एक वैश्विक संवाद, सांस्कृतिक पुल और रचनात्मक साझा अनुभव का प्रतीक बन चुका है। यही ओटीटी और डबिंग की असली ताकत और भविष्य की संभावनाएं हैं।

दो हजार रुपये के 98.47 प्रतिशत नोट वापस आए

मुंबई : आरबीआइ ने शुक्रवार को बताया कि चलन में मौजूद 2000 रुपये के 98.47 प्रतिशत नोट वापस आ चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। तब चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था जो 30 अप्रैल, 2026 को कारोबार बंद होने के समय घटकर 5,451 करोड़ रुपये रह गया है। (प्रेट्र)

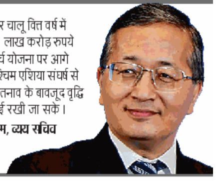

सरकार चालू वित्त वर्ष में 12.22 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत खर्च योजना पर आगे बढ़ेगी ताकि पश्चिम एशिया संघर्ष से पैदा हुए वित्तीय तनाव के बावजूद वृद्धि की रफ्तार बनाई रखी जा सके।

- वी. वुअलनाम, व्यय सचिव

अप्रैल में रिकार्ड 4.5 लाख यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री

जीएसटी दरों में कटौती और आयकर सीमा बढ़ाए जाने से घरेलू स्तर पर कारों की बिक्री को मिला समर्थन

नई दिल्ली, प्रेट्र : नए वित्त वर्ष 2026-27 का पहला महीना कार बनाने वाली कंपनियों के लिए बहुत अच्छा रहा। अप्रैल में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की अनुमानित बिक्री 4.5 लाख यूनिट रही, जो किसी एक माह में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। मारुति सुजुकी, हुंडई और किआ जैसी कंपनियों ने इस दौरान रिकार्ड बिक्री दर्ज की। पिछले साल अप्रैल में घरेलू बाजार में यात्री वाहनों की बिक्री 3.54 लाख यूनिट रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने, रेपो रेट में कटौती करने और आयकर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख करने से यात्री वाहनों की बिक्री में इजाफा हुआ।

- मारुति को 1.65 लाख कारों की देनी है डिलीवरी, छोटी कारों का वेटिंग पीरियड एक महीने
- पेट्रोल की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी का कारों की मांग पर पड़ सकता है असर : पार्थो बनर्जी

मारुति सुजुकी इंडिया ने अप्रैल में 1,91,122 यूनिट की रिकार्ड घरेलू बिक्री दर्ज की। पिछले साल इसी महीने में यह 1,42,053 यूनिट थी। इससे पहले इसकी सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री दिसंबर, 2025 में 1,82,165 यूनिट थी। कंपनी के सीनियर एक्जीक्यूटिव पार्थो बनर्जी ने कहा, हम इस साल की शुरुआत बड़े धमाके के साथ कर रहे हैं। छोटी कारों ने इस बिक्री वृद्धि में अहम योगदान दिया है। कंपनी की छोटी कारों आल्टो, एस-प्रेसो, सेलेरियो और वैगनआर की बिक्री 74.4 प्रतिशत बढ़ी है, जिससे लोगों के मन में छोटी कारों के भविष्य को लेकर जो शक था, वह दूर हो गया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी से डिमांड पर असर पड़ सकता है। बनर्जी ने कहा कि कंपनी को 1.65 लाख कारों की डिलीवरी देनी है और छोटी कारों की डिलीवरी का इंतजार समय (वेटिंग पीरियड) एक महीने तक बढ़ गया है।

घरेलू बाजार में महिंद्रा से ज्यादा टाटा मोटर्स ने बेचे यात्री वाहन

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की पिछले महीने घरेलू बाजार में बिक्री 30.50 प्रतिशत बढ़कर 59,000 यूनिट रही, जबकि पिछले साल इसी समय में यह 45,199 यूनिट थी। महिंद्रा एंड महिंद्रा की घरेलू यात्री वाहन बिक्री आठ प्रतिशत बढ़कर 56,331 यूनिट हो गई। नीतिगत समर्थन का फायदा उठाते हुए हुंडई मोटर की अप्रैल, 2026 में घरेलू बिक्री साल-दर-साल 17 प्रतिशत बढ़कर 51,902 यूनिट रही। यह कंपनी की शुरुआत के बाद से अप्रैल महीने में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री थी। किआ इंडिया की भी बिक्री 16 प्रतिशत बढ़कर 27,286 यूनिट्स हो गई।

दोपहिया की बिक्री में भी मजबूत वृद्धि

मजबूत मांग और सभी सेगमेंट में वृद्धि के चलते अप्रैल में दोपहिया वाहनों की बिक्री में अच्छा इजाफा हुआ। हीरो मोटोकार्प की घरेलू खुदरा बिक्री आठ प्रतिशत बढ़कर 5,52,713 यूनिट रही। पिछले साल की समान अवधि में कंपनी ने 5,66,086 वाहन बेचे थे। वहीं होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया की अप्रैल में कुल बिक्री 17 प्रतिशत बढ़कर 5.63 लाख यूनिट हो गई, जो एक साल पहले इसी समय में 4.80 लाख यूनिट थी। अप्रैल, 2026 में घरेलू बिक्री 4.84 लाख यूनिट रही, जबकि एक साल पहले यह 4.22 लाख यूनिट थी। उधर, रायल एनफील्ड ने बताया कि अप्रैल, 2026 में उसकी कुल बिक्री 31 प्रतिशत बढ़कर 1,13,164 यूनिट हो गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में 86,559 यूनिट बिकी थीं। कंपनी की घरेलू बिक्री 37 प्रतिशत बढ़कर 1,04,129 यूनिट हो गई, जबकि अप्रैल 2025 में यह 76,002 यूनिट थी।

कंपनीवार यात्री वाहनों की घरेलू बिक्री	
मारुति सुजुकी	1,91,122
टाटा मोटर्स	59,000
महिंद्रा एंड महिंद्रा	56,331
हुंडई	51,902
किआ	27,286
जेएसडब्ल्यू- एमजी मोटर	6,018
रेनो इंडिया	5,413
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर	30,159

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

एफपीआइ ने पहले चार माह में 1.92 लाख करोड़ रुपये निकाले

नई दिल्ली, प्रेट्र : बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआइ) की भारतीय बाजारों से निकासी जारी है और अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री की है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के आंकड़ों के अनुसार, इस ताजा निकासी के साथ कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले चार महीनों में एफपीआइ कुल 1.92 लाख करोड़ रुपये की बिकवाली कर चुके हैं। यह पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 की कुल निकासी 1.66 लाख करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है।

डिपाजिटरी के आंकड़ों के अनुसार, एफपीआइ ने इस वर्ष जनवरी में 35,962 करोड़ रुपये की निकासी की थी। इसके बाद 22,615 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश किया था, जो 17 महीनों में सबसे अधिक निवेश था। इसके बाद मार्च में रिकार्ड 1.17 लाख करोड़ रुपये की निकासी की। अब अप्रैल में यह 60,847 करोड़ रुपये की निकासी की है।

अप्रैल 2026 में विदेशी निवेशकों ने 60,847 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, वर्ष 2025 में कुल 1.66 लाख करोड़ रुपये निकाले थे

मार्निंगस्टार इन्वेस्टमेंट रिसर्च इंडिया के प्रमुख शोध मैनेजर हिमांशु श्रीवास्तव ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं, जिसने वैश्विक महंगाई को लेकर चिंताओं को फिर से बढ़ा दिया। इस कारण अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने भारी बिकवाली की है।

भारत को लेकर 'बेहद उत्साहित', एपल को बड़ी वृद्धि की उम्मीद

नई दिल्ली, प्रेट्र : आइफोन निर्माता एपल के सीईओ टिम कुक ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत को लेकर बहुत खुश और उत्साहित हैं, क्योंकि कंपनी वहां दो अंकों में वृद्धि दर्ज कर रही है। 28 मार्च को खत्म हुए वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के लिए कंपनी के नतीजों का एलान करते हुए कुक ने कहा कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है और तीसरा सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर बाजार है। कंपनी भारत में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसकी बाजार हिस्सेदारी अभी भी बहुत कम है, जो देश में मौजूद मौके को दिखाता है। एपल के सबसे लंबे समय तक सीईओ रहे कुक एक सितंबर को अपने पद से हटने वाले हैं। उसी तारीख को जान टर्नस उनकी जगह लेंगे।

एपल का तिमाही राजस्व 17 प्रतिशत बढ़कर 111.2 अरब डालर हो गया। कुक ने बताया कि कंपनी ने विकसित और उभरते दोनों बाजारों में जनवरी-मार्च तिमाही में रिकार्ड बनाए जिनमें भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज हुई। आइफोन राजस्व साल-दर-साल आधार पर 22 प्रतिशत बढ़कर 57 अरब डालर रहा है।

टिम कुक

- कंपनी का तिमाही राजस्व 17 प्रतिशत बढ़कर 111.20 अरब डालर हो गया
- आइफोन राजस्व साल-दर-साल 22 प्रतिशत बढ़कर 57 अरब डालर रहा

अप्रैल में चार प्रतिशत बढ़ी बिजली की खपत

नई दिल्ली, प्रेट्र : इस वर्ष अप्रैल में पूरे देश में बिजली की खपत 4.04 प्रतिशत बढ़कर 153.99 अरब यूनिट रही है। पिछले महीने पहले पखवाड़े के दौरान बिना मौसम बारिश के कारण बिजली की खपत की वृद्धि दर कम रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 में 148.01 अरब यूनिट बिजली की खपत हुई थी।

हालांकि, तापमान में बढ़ोतरी के कारण महीने के दूसरे पखवाड़े में बिजली की माँग बढ़ गई और पिछले महीने बिजली की अधिकतम मांग अप्रैल 2025 के 235.32 गीगावाट से बढ़कर 256.11 गीगावाट पर पहुंच गई।

बिजली मंत्रालय के अनुसार, इस वर्ष गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 270 गीगावाट तक पहुंच सकती है। पिछली गर्मियों के दौरान जुलाई 2025 में बिजली की अधिकतम मांग 242.77 गीगावाट दर्ज की गई थी। हालांकि, यह सरकारी अनुमान 277 गीगावाट से कम थी।

पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित सप्लायर व कांट्रैक्टर को राहत

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फोर्स मेज्योर(अप्रत्याशित स्थिति) क्लाज को लागू कर दिया है। इस क्लाज के लागू होने पर सरकारी विभाग से जुड़े सप्लायर और कांट्रैक्टर को अपना दायित्व पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यह क्लाज उनके लिए लागू माना जाएगा जिनका काम पश्चिम एशिया संकट के कारण प्रभावित हुआ है।

फोर्स मेज्योर क्लाज अप्रत्याशित या अपने नियंत्रण से बाहर की घटना जैसे कि बाढ़, युद्ध, प्राकृतिक विपदा जैसी स्थिति में लागू किया जाता है और इन वजहों से जब कोई कांट्रैक्टर या सप्लायर अपना दायित्व या अनुबंध को समय पर नहीं पूरा कर पाता है तो भी उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक, फोर्स मेज्योर का लाभ उन एजेंसियों को मिलेगा जो पहले अपने काम को पूरा करने में डिफाल्टर नहीं हुए हैं। उन्हें काम पूरा करने के लिए कम से कम दो महीने और अधिकतम चार महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हालांकि, इस छूट के लिए उनके काम की प्रकृति और पश्चिम एशिया संकट से पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की जाएगी।

- वित्त मंत्रालय ने फोर्स मेज्योर क्लाज को लागू किया
- सप्लायर और कांट्रैक्टर को मिलेगा अतिरिक्त समय

असल में कांट्रैक्ट में समय पर काम पूरा नहीं होने पर भारी जुर्माना या अनुबंध को रद करने का प्रविधान होता है। फोर्स मेज्योर में इस प्रविधान को टाल दिया जाता है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित सप्लायर और कांट्रैक्टर को ही फोर्स मेज्योर का लाभ मिलेगा।

डीजल व एटीएफ निर्यात पर टैक्स घटाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पेट्रो उत्पादों का निर्यात करने वाली कंपनियों को सरकार से कुछ राहत मिली है। डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर लगाए जाने वाले अप्रत्याशित कर (विंडफाल गेन टैक्स) को कम कर दिया गया है। यह नई दर 1 मई 2026 से लागू हुई हैं। अब डीजल निर्यात पर टैक्स घटकर 23 रुपये प्रति लीटर और विमान ईंधन (एटीएफ) पर टैक्स घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। पेट्रोल निर्यात पर टैक्स शून्य ही रहेगा। इस बारे में राजस्व विभाग ने 30 अप्रैल को अधिसूचना जारी की है।

सरकार एक निश्चित अंतराल पर विंडफाल गेन टैक्स लगा रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड महंगा होता है तो उसी आधार पर घरेलू तेल उत्पादक कंपनियों जैसे ओएनजीसी, ओआइएल, वेदांता को भी भुगतान होता है। साथ ही पेट्रो उत्पादों का भारत से बाहर निर्यात करने वाली कंपनियो को भी ज्यादा फायदा होता है। इसलिए सरकार इन पर टैक्स लगाकर उसका समायोजन करती हैं। इससे पेट्रो उत्पादों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि कंपनियों के लिए निर्यात से होने वाला मुनाफा कम हो जाता है। सरकार ने 26 मार्च को डीजल पर 21.50 रुपये प्रति लीटर और एटीएफ पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का निर्यात टैक्स लगाया था। उसे बाद में (11 अप्रैल को) डीजल पर 55.5 रुपये और एटीएफ पर 42 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। अब इन्हें काफी कम कर दिया गया है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर पहले वाला ही टैक्स रहेगा, इसलिए पेट्रोल पंप पर आम आदमी की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। इससे देश में इनका स्टाक और उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कहीं कमी या अचानक महंगाई नहीं होगी। इस फैसले से देश की बड़ी पेट्रोलियम कंपनियों को अब विदेश में डीजल और एटीएफ बेचने पर पहले जितना कम मुनाफा नहीं होगा, लेकिन टैक्स कम होने से उनका निर्यात थोड़ा आसान हो जाएगा। ईरान युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें चार साल के उच्चतम स्तर 126 डालर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इस कारण निर्यात पर टैक्स लगाकर कंपनियों को विदेश भेजने से रोका गया था। अब अंतरराष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से टैक्स की समीक्षा की गई और इसे कम कर दिया। हर 15 दिन में दरों की समीक्षा हो रही है।

- अब डीजल निर्यात पर टैक्स घटकर 23 रुपये प्रति लीटर किया गया
- एक निश्चित अंतराल पर विंडफाल गेन टैक्स लगा रही है सरकार

राष्ट्रीय फलक

पीलीभीत में गबन के करोड़ों रुपये रखने में सात महिलाएं गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत : जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में करोड़ों के गबन के मामले में पुलिस ने सात महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपित इल्हाम शम्सी की दो पत्नी, साली, सलहज, सास और दो परिचित महिलाएं शामिल हैं। इनके खातों में करीब साढ़े पांच करोड़ रुपये फ्रीज कराए जा चुके हैं। इल्हाम की एक पत्नी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इल्हाम अग्रिम जमानत पर बाहर है। जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार ने 13 फरवरी को बताया था कि इल्हाम उर्रहमान शम्सी मूल रूप से जनता टेक्निकल इंटर कालेज बीसलपुर में कार्यरत था। वह आठ वर्षों से डीआइओएस कार्यालय से संबद्ध था। वह वेतन बिल और टोकन जनरेशन का कार्य देख रहा था। उसने 12 सितंबर 2024 से 98 ट्रांजेक्शन के माध्यम से 1.01 करोड़ पत्नी समेत परिचितों के खातों में स्थानांतरित कर गबन किए।

आचार्य का पद धार्मिक व पारंपरिक, सेवा नियम और सेवानिवृत्ति लागू नहीं

जागरण संवाददाता, वाराणसी

'आचार्य का पद धार्मिक व पारंपरिक है, इस पर सेवा नियमावली और सेवानिवृत्ति के नियम नहीं लागू नहीं हो सकते।' श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के आचार्य पद्म भूषण प्रो. देवी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित मामले में एकल पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद करने के निर्णय पर रोक लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से प्रो. द्विवेदी को एक बार फिर श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के रात्रि श्रृंगार शयन आरती और मंदिर के पुजारियों को प्रशिक्षण देने का अधिकार प्राप्त हो गया है।

पूर्व में एकल न्यायाधीश ने प्रो. द्विवेदी के पक्ष में फैसला सुनाया था। बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस फैसले को रद कर दिया था। प्रो. द्विवेदी ने इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली। अब न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अतुल चंदुरकर की पीठ ने नोटिस जारी कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें एकल न्यायाधीश के फैसले को रद किया गया था।

अधिवक्ता विवेक जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी ने सर्वोच्च न्यायालय में प्रो. द्विवेदी की ओर से पैरवी की थी। आचार्य द्विवेदी ने कहा कि यह सत्य की विजय है।

- श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के आचार्य पद्मभूषण आचार्य देवी प्रसाद द्विवेदी अब फिर कर सकेंगे बाबा की सेवा

तेलंगाना में दवा संयंत्र में धमाके से एक की मौत, सात घायल

हैदराबाद, प्रेट्र : तेलंगाना के नालगोंडा जिले में एक दवा संयंत्र में रिएक्टर फटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और सात अन्य घायल हैं। पुलिस ने बताया कि धमाके की सही वजह का अभी पता नहीं चल पाया है।

शुक्रवार दोपहर जब दो मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर धमाका हुआ, तब वहां 10 लोग काम कर रहे थे। इसमें आठ लोग घायल हो गए। दो लोगों को मामूली चोटें आईं। छह अन्य को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के एक सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान इनमें से एक की मौत हो गई। माना जा रहा है कि धमाके के बाद इमारत की दूसरी मंजिल से कूदने की वजह से उसे कई चोटें आई थीं और इसी कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि बाकी घायलों की हालत स्थिर है। अप्रैल में भी इसी संयंत्र में आग लगने से दो लोग घायल हुए थे।

काशी में नव्य-भव्य श्रीजगन्नाथ धाम बनेगा धर्म-चेतना का केंद्र : विजयेंद्र सरस्वती

जागरण संवाददाता, वाराणसी

श्रीकांचीकामकोटि पीठम् के शंकराचार्य स्वामी शंकरविजयेंद्र सरस्वती ने कहा कि धर्म की उन्नति के लिए मंदिरों का विकास आवश्यक है। मंदिर विकसित होंगे तो लोगों का मन विकसित होगा। काशी में बनने वाला श्रीजगन्नाथ मंदिर भी सनातन हिंदू चेतना का प्रमुख केंद्र बनेगा।

शंकराचार्य स्वामी शंकरविजयेंद्र सरस्वती शुक्रवार को असि घाट स्थित प्राचीन श्रीजगन्नाथ मंदिर के प्रस्तावित नव्य-भव्य धाम स्वरूप का पूरे वैदिक विधि-विधान के साथ शिलान्यास करने के पश्चात श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व में शांति और सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी और सीमाओं पर रक्षा का व्यय तभी कम होगा, जब लोग धार्मिक होंगे। धर्म का विकास होगा तो सबका विकास होगा, धार्मिक आस्था लोगों के मन में बढ़ने से राष्ट्र उन्नति के शिखर पर जाएगा। कहा कि हम धर्म के लिए काम करने वाले कानून को मानते हैं। मंदिरों को सरकारी आधिपत्य से मुक्त होना चाहिए और मंदिरों में आने वाले चढ़ावे का सदुपयोग बंधु के लिए नहीं, बंधुत्व के लिए होना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में युवा पीढ़ी का आगमन बढ़ा है। मंदिरों के निर्माण के साथ धर्म का प्रचार भी होना चाहिए। आज धार्मिक विषयों पर बीएचयू, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों से उपाधियां तो मिल ही रही हैं लेकिन उनका सार्थक उपयोग तभी है जब सप्ताह में दो दिन शनिवार व रविवार को धर्म प्रबोधन के कार्यक्रम भी हों।

- श्रीकांचीकामकोटि पीठम् के शंकराचार्य ने किया शिलान्यास
- कहा-सरकारी आधिपत्य से मुक्त हों मंदिर, चढ़ावा का धन बंधु नहीं, बंधुत्व के विकास में लगे

अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित जीर्णोद्धार के लिए शिलान्यास के कार्यक्रम में पद्मभूषण प्रो वशिष्ठ त्रिपाठी को आशीर्वाद देते कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य स्वामी शंकर विजयेंद्र सरस्वती। जागरण

केदारनाथ धाम में वीआइपी दर्शन का विरोध, तीर्थ पुरोहितों ने की नारेबाजी

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

केदारनाथ धाम में वीआइपी दर्शन व्यवस्था पर शुक्रवार को तीर्थ पुरोहितों ने नारेबाजी कर नाराजगी व्यक्त की। उनका आरोप था कि वीआइपी गेट पर तैनात कर्मचारियों ने उन्हें अंदर जाने से रोका। नारेबाजी के कारण माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। हालांकि बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया। बाद में पुलिस अधीक्षक ने केदारनाथ धाम में तैनात पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) और उपनिरीक्षक को तत्काल हटा दिया।

धाम में बड़ी संख्या में एकत्र हुए तीर्थ पुरोहितों का आरोप था कि वीआइपी दर्शन को बंद किया जाना चाहिए। करीब डेढ़ घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद पहुंचे बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने तीर्थ पुरोहितों से वार्ता की। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तीर्थ पुरोहित को जानबूझकर रोका नहीं गया है। गलतफहमी के कारण यह स्थिति पैदा हुई थी। बातचीत के बाद मामला शांत हो गया है।

उधर, केदार सभा ने इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताया है। सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि घटना भ्रामक सूचना के कारण हुई, जिसमें कुछ पुलिस कर्मियों की ओर से तीर्थ पुरोहितों के प्रवेश पर रोक की अफवाह फैलाई गई। उन्होंने कहा कि पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शुक्रवार को उद्योगपति गौतम अदाणी ने निर्धारित प्रोटोकाल के तहत ही बाबा केदार के दर्शन किए।

- वीआइपी गेट पर रोके जाने से भड़के तीर्थ पुरोहित, एसपी ने सीओ और उपनिरीक्षक को हटाया
- केदार सभा ने इसे सुनियोजित षड्यंत्र बताया, कहा- पुलिस कर्मियों ने फैलाई अफवाह

जम्मू के लोअर ठठर क्षेत्र में पुल का बड़ा हिस्सा भरभराकर ढहा, चार श्रमिक दबे

जागरण संवाददाता, जम्मू

जम्मू के साथ सटे लोअर ठठर क्षेत्र में शुक्रवार को एक पुल का बड़ा हिस्सा अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय पुल के नीचे सुरक्षा दीवार की मरम्मत का काम चल रहा था। पहले से कमजोर व नाले में नीचे से खोखली हो चुकी सुरक्षा दीवार धंसने से पुल का एक तरफ का हिस्सा नीचे काम कर रहे एक मिस्त्री व तीन मजदूरों पर आ गिरा। इससे चारों श्रमिक मलबे में दब गए। पहले स्थानीय लोगों और फिर पुलिस, सेना, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बचाव अभियान तेज किया। हादसे में मिस्त्री को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि एक मजदूर का शव बरामद कर लिया गया।

राहत व बचाव अभियान को सात घंटे से ज्यादा बीत गए है। मौके पर पुलिस व प्रशासन के अधिारियों के साथ स्थानीय लोग भी राहत कार्य में सहयोग कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण वर्ष 2002 में किया गया था। पिछले वर्ष अगस्त में आई बाढ़ के दौरान इस नाले में भी तेज बहाव से पुल की सुरक्षा दीवार के नीचे से मलबा निकल जाने से यह असुरक्षित हो गया था। इसके गिरने की आशंका बढ़ गई थी। इस पुल के ऊपर से दिनभर वाहनों का आना-जाना लगा रहता है। इसलिए स्थानीय लोग इसकी मरम्मत की मांग कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मरम्मत कार्य के दौरान पुल के नीचे न तो स्पोर्ट दी गई थी और न ही ऊपर से यातायात रोका गया था।

- मरम्मत का काम कर रहे एक श्रमिक को सुरक्षित निकाला, एक का शव बरामद, दो की तलाश
- बचाव अभियान में पुलिस, सेना, सीआरपीएफ, एसडीआरएफ संग स्थानीय लोग भी जुटे

जम्मू शहर के साथ सटे लोअर ठठर क्षेत्र में शुक्रवार को पुल का एक हिस्सा ढहने से दबे मजदूरों को निकालने के लिए मलबा उठाती जेसीबी मशीन व मौके र जुटर बचाव दल। जागरण

सार्वजनिक भूमि पर नमाज का अधिकार नहीं : हाई कोर्ट

विधि संवाददाता, जागरण • प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज पढ़ने को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि ऐसी भूमि का उपयोग किसी एक पक्ष द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि सार्वजनिक भूमि पर सभी का समान अधिकार होता है। इसका एकतरफा उपयोग कानूनन स्वीकार्य नहीं है।

हाई कोर्ट ने संभल जिले के इकौना निवासी असीन की याचिका खारिज कर दी। कहा कि पूर्व में मुनाजिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में हाई कोर्ट ने निजी परिसरों के भीतर सद्भावनापूर्ण प्रार्थना की रक्षा करते हुए माना था कि व्यक्तिगत धार्मिक प्रथा में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन इस निर्णय को यह मानकर नहीं पढ़ा जा सकता कि निजी परिसरों में संगठित या नियमित सामूहिक गतिविधि की पूरी छूट है। जहां गतिविधि उस क्षेत्र से आगे बढ़ती है और सार्वजनिक क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू करती है, वैध विनियमन लागू होता है। पूर्व निर्णय निजी परिसरों को अनियंत्रित सामूहिक स्थान में बदलने का अधिकार नहीं देता।

कोर्ट का कहना था कि धर्म का पालन करने का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है और इसका प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता कि यह दूसरों के इन अधिकारों में हस्तक्षेप करे। यदि भूमि को निजी मान भी लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता मांगी गई राहत का हकदार नहीं है।

- परंपरा से इतर गतिविधियों पर सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार
- संभल के इकौना निवासी असीन की याचिका कोर्ट ने खारिज की

300 दिनों से ज्यादा की पश्चिम एशिया में रिकार्ड तैनाती के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब अमेरिका लौट रहा है।

अराघची पर 'गार्ड' की छाया, पेजेशकियान नाराज

▸ मसूद पेजेशकियान ने दी विदेश मंत्री की बर्खास्तगी तक की चेतावनी

▸ अमेरिका-ईरान टकराव के बीच सत्ता के भीतर खींचतान तेज

मसूज पेजेशकियान और अब्बास अराघची। फाइल

तेहरान, एएनआइ: पश्चिम एशिया में अमेरिका-ईरान टकराव गहराता जा रहा है और इसके असर से वैश्विक ऊर्जा बाजार दबाव में है। इसी बीच तेहरान से आ रही खबरें बताती हैं कि ईरान की सत्ता के गलियारे में सब कुछ सामान्य नहीं है। राष्ट्रपति मसूज पेजेशकियान और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलीबाफ के बीच विदेश मंत्री अब्बास अराघची को लेकर असहजता खुलकर सामने आने लगी है।

ब्रिटेन स्थित संस्था ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों शीर्ष नेताओं को शिकायत है कि अराघची कूटनीतिक फैसलों में राष्ट्रपति कार्यालय को दरकिनार कर सीधे रिवोल्यूशनरी गार्ड (आइआरजीसी) से तालमेल बना रहे हैं। आरोप यह भी है कि उन्होंने विदेश मंत्री की भूमिका से ज्यादा आइआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी के सहयोगी की तरह काम किया है।

सूत्रों का कहना है कि अराघची कई अहम फैसलों में राष्ट्रपति को भरोसे में लिए बिना ही वाहिदी के साथ समन्वय कर रहे हैं और उन्हीं के निर्देशों पर नीतियां आगे बढ़ा रहे हैं। इससे राष्ट्रपति पेजेशकियान के भीतर नाराजगी गहराती जा रही है। उन्होंने अपने करीबी दायरे में साफ संकेत दिया है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो अराघची को पद से हटाने तक का फैसला लिया जा सकता है। राष्ट्रपति खेमे की चिंता यह भी है कि संवेदनशील कूटनीतिक दौर में विदेश मंत्री का झुकाव सैन्य नेतृत्व की ओर बढ़ने से राजनीतिक नेतृत्व की पकड़ कमजोर पड़ रही है। यह विवाद ऐसे समय उभरा है, जब पहले से ही शासन तंत्र के भीतर मतभेदों की खबरें सामने आ रही थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, वाहिदी का तर्क है कि युद्धकालीन स्थिति में सभी संवेदनशील प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और नियंत्रण सीधे रिवोल्यूशनरी गार्ड के हाथ में होना चाहिए। विधायी मोर्चे पर भी यह खींचतान साफ नजर आई। 27 अप्रैल को कट्टरपंथी सांसदों के एक समूह ने वार्ता टीम के समर्थन में जारी संसदीय बयान पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया। हालांकि 261 सांसद इसके पक्ष में थे, लेकिन सईद जलीली से जुड़े नेताओं के रुख ने संसद के भीतर विभाजन को उजागर कर दिया।

इसी कड़ी में, परमाणु मुद्दे को वार्ता में शामिल करने की कोशिशों पर विवाद बढ़ने के बाद स्पीकर गलीबाफ के इस्तीफे की खबर भी सामने आई। इसके बाद अराघची ने खुद वार्ता की कमान संभालने की कोशिश की और 24 अप्रैल को अकेले इस्लामाबाद जाकर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया।

आठ देशों में 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान

पश्चिम एशिया में करीब 40 दिनों तक चले अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध में भले ही ईरान पर करारी मार पड़ी हो, लेकिन अमेरिका को भी कम नुकसान नहीं उठाना पड़ा है। हाल में आई नई रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने आठ पड़ोसी देशों में स्थित 16 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और वे आपरेशनल स्थिति से बाहर हो चुके हैं। अमेरिकी की इस स्थिति पर ईरान के सुप्रीम लीडर ने चुटकी लेते हुए कागजी शेर की 'उपाधि' दे डाली।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी हमलों में मुख्य रूप से उन्नत राडार ठिकानों, कम्युनिकेशन के ढांचों और विमानों को निशाना बनाया गया है। इन सिस्टम को बदलना या उनकी मरम्मत काफी महंगी साबित हो सकती है। पेंटागन के कंट्रोलर जूल्स जे हर्स्ट तृतीय ने पिछले दिनों संसद में बताया कि ईरान के साथ टकराव में अब तक अमेरिका के 25 अरब डालर खर्च हो चुके हैं। हईरान का दावा है कि यह आंकड़ा 100 अरब डालर से कम नहीं है। रायटर के अनुसार, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को "कागजी शेर" करार देते हुए उनकी सुरक्षा क्षमता पर सवाल उठाए।

एक्स पर एक पोस्ट में खामेनेई ने कहा, "अमेरिका के ये कागजी शेर जैसे ठिकाने खुद की सुरक्षा भी नहीं कर सकते, क्षेत्र के अमेरिकी समर्थकों की तो बात ही छोड़िए।" उनके इस बयान को न सिर्फ वाशिंगटन बल्कि क्षेत्रीय सहयोगियों इजरायल व अरब देशों- पर अप्रत्यक्ष निशाने के रूप में देखा जा रहा है।

ईरान के मसले पर हस्तक्षेप करना बंद करे जर्मनी : ट्रंप

▸ जर्मन चांसलर की बयानबाजी से भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति

कहा, जर्मनी की ऊर्जा व घुसपैठ की समस्याओं को देखें मर्ज

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज पर हमले जारी हैं। ताजा बयान में ट्रंप ने कहा, वाशिंगटन विश्व को ईरान के परमाणु खतरे से बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, इसलिए मर्ज ईरान मसले में हस्तक्षेप करना बंद करें और अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दें।

ईरान पर अमेरिकी हमले को लेकर ट्रंप और मर्ज के बीच इन दिनों कहासुनी चल रही है। मंगलवार को ट्रंप ने कहा, मर्ज को नहीं पता है कि वह क्या कह रहे हैं। इससे पहले मर्ज ने कहा था कि ईरानी इस युद्ध में अमेरिका को अपमानित कर रहे हैं। बुधवार को ओवल हाउस में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप ने मर्ज पर हमला बोला। कहा, जर्मनी ऊर्जा और घुसपैठ की समस्याओं से जूझ रहा है। इतना ही नहीं मर्ज यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में नाकामयाब रहे हैं। वह लगातार भयावह कार्य कर रहे हैं जिससे यूक्रेन बड़ी मुश्किल में फंस गया है। मर्ज वहां हो रही गड़बड़ में शामिल हैं।

इससे पहले मर्ज ने एक सैन्य अड्डे पर आयोजित कार्यक्रम में नाटो सैन्य गठबंधन के महत्व की चर्चा की लेकिन ट्रंप के उस बयान की चर्चा नहीं की जिसमें उन्होंने जर्मनी से हजारों सैनिकों को कम करने की बात कही थी। ये अमेरिकी सैनिक नाटो की ओर से जर्मनी के सैन्य अड्डों पर तैनात हैं।

पिछले दिनों मर्ज ने कहा, जर्मनी सहयोगी देशों के साथ विश्वासपूर्ण संबंध कायम रखने का पक्षधर है और वह होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सहयोग को तैयार है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दो महीनों से होर्मुज स्ट्रेट समुद्री मार्ग को ईरान ने बंद कर रखा है जबकि ईरानी जहाजों के लिए अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है। इसके चलते इस समुद्री मार्ग से विश्व बाजार का करीब 20 प्रतिशत कच्चा तेल नहीं आ पा रहा है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है।

ईरान ने मलबे से निकाले हथियार, ट्रंप कर रहे नए हमलों की तैयारी

युद्ध की तैयारियों के बीच वार्ता पर भी जोर, ईरान ने भेजा नया प्रस्ताव, ट्रंप ने किया खारिज

ट्रंप ने 45 मिनट तक व्हाइट हाउस में की ईरान पर नए हमलों की समीक्षा

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

▸ अमेरिका ने इजरायल को भी भेजे 6500 टन हथियार और सैन्य उपकरण

▸ तेहरान में ड्रोन और छोटे विमानों के हमले का अलर्ट, एयर डिफेंस सक्रिय

करीब 40 दिनों तक चले भीषण संघर्ष के बाद भले ही अमेरिका और इजरायल ने ईरान की सैन्य ताकत को बुरी तरह कमजोर करने के दावे किए हों, लेकिन अब तस्वीर कुछ अलग दिख रही है। ईरान अब भी अमेरिकी-इजरायली हमलों के प्रति सशंकित है और तेजी से तैयारी कर रहा है।

अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, तेहरान ने हमलों में मलबे के नीचे दबे अपने अहम हथियार भंडार को फिर से निकालकर सक्रिय करना शुरू कर दिया है। उधर, अमेरिका ने इजरायल को करीब 6500 टन हथियारों की नई खेप भेजी है और ईरान पर नए हमले की तैयारी को लेकर समीक्षा भी की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को ईरान पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के विकल्प सुझाए। युद्ध की तैयारी के साथ-साथ वार्ता को भी आगे बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। तेहरान ने पाकिस्तान के जरिये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास नया शांति प्रस्ताव भेजा। हालांकि, ट्रंप ने इस प्रस्ताव को भी खारिज करते हुए कहा कि वह नए प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। ईरान के नए प्रस्ताव की रिपोर्ट के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत गिरकर 109 डालर तक नीचे आ गई। एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन भूमिगत ठिकानों पर भारी बमबारी कर उन्हें पूरी तरह नष्ट करने का दावा किया गया था, वहां से ईरान ने हथियारों को बाहर निकालकर दोबारा तैनात करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी व दो अन्य सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि ईरान मौजूदा युद्धविराम का इस्तेमाल तेजी से ड्रोन व मिसाइल क्षमताओं को फिर से खड़ा करने में कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि इन प्रयासों के पीछे मकसद साफ है कि अगर हालात फिर बिगड़ते हैं, तो ईरान जल्द जवाबी हमले के लिए तैयार रहना चाहता है।

ईरान ने पाकिस्तान के जरिये अमेरिका को भेजा नया वार्ता प्रस्ताव

एएनआइ के अनुसार, ईरान ने अमेरिका के साथ चल रही बातचीत को लेकर अपना नया प्रस्ताव पाकिस्तान को सौंप दिया है। इस प्रस्ताव का मुख्य फोकस होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री आवाजाही बहाल करने पर है। पाकिस्तान इस मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि उनका सबसे बड़ा मकसद युद्ध खत्म करना और लंबे समय तक शांति कायम करना है। ईरान का कहना है कि वह बातचीत के जरिए हालात को बेहतर करना चाहता है और शांति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि, अमेरिकी रुख इस पर सख्त नजर आ रहा है और इसकी संभावना कम है कि ट्रंप इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। व्हाइट हाउस ने भी प्रस्ताव के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने इसकी भी पुष्टि नहीं की कि ट्रंप प्रशासन को ईरान का नया प्रस्ताव मिला है या नहीं। उन्होंने कहा कि हम निजी कूटनीतिक बातचीत के बारे में जानकारी नहीं रखते।

तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय

रायटर के अनुसार, ईरान में शुक्रवार को एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया। यह कदम संदिग्ध छोटे विमानों और निगरानी ड्रोन की मौजूदगी के जवाब में उठाया गया। एएफपी ने बताया कि करीब 20 मिनट तक एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय रहा। अज्ञात छोटे विमान और टोही ड्रोन को ट्रैक कर उन्हें निष्क्रिय करने की कोशिश की गई। हालांकि, थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य हो गई और कबड़े नुकसान की सूचना नहीं है।

संसद में युद्ध रोकने की मंजूरी वाला प्रस्ताव टला

न्यूयार्क टाइम्स के अनुसार, ट्रंप ने ईरान युद्ध की मंजूरी के लिए संसद में प्रस्ताव रखने का इरादा अभी टाल दिया है। युद्ध के 60 दिन का समय पूरा होने के बाद इसे जारी रखने के लिए एक मई को प्रस्ताव रखा जाना था। वार पावर एक्ट के तहत सैन्य कार्रवाई जारी रखने के लिए कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। व्हाइट हाउस का कहना है इस 60 दिन की कानूनी समय-सीमा को "रोक" दिया है क्योंकि ईरान के खिलाफ लड़ाई केवल 40 दिन ही चली।

ईरान पर नए हमलों की आहट

व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सैन्य अधिकारियों के बीच करीब 45 मिनट तक बैठक चली। बैठक में सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर और ज्वाइंट चीफ्स आफ स्टाफ के चेयरपर्सन ने ट्रंप को ईरान पर हमले से जुड़ी नई योजना के बारे में जानकारी दी। एक्सियोस के अनुसार, ईरान को समझौते को तैयार करने के लिए छोटा लेकिन ताकतवर हमला किया जा सकता है। इसमें बुनियादी ढांचों के अलावा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा, होर्मुज के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके व्यावसायिक जहाजों के लिए दोबारा खोलने पर भी चर्चा हुई। साथ ही ईरान के संवर्धित यूरेनियम के स्टाक पर कब्जा करने के लिए स्पेशल फोर्सेज का आपरेशन चलाने पर भी बात हुई। एपी के अनुसार, बीते 24 घंटे में इजरायल को 6500 टन हथियार और सैन्य उपकरण का जखीरा भेजा गया है। इसमें हवाई और जमीनी हमलों के लिए गोला-बारूद, सैन्य ट्रक, टैक्टिकल वेहिकल और अन्य उपकरण शामिल हैं। अब तक इजरायल को 1,15,600 टन से ज्यादा सैन्य उपकरण भेजे जा चुके हैं। इनको कार्गो जहाज व कई विमानों से इजरायल पहुंचाया गया है।

ईरान से टक्कर लेगी डेढ़ करोड़ डालर की 'डार्क ईगल'

हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल।

अमेरिकी सेना ईरान के खिलाफ अपने पहले हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम 'डार्क ईगल' को तैनात करने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सेंटकाम ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लांचरों पर हमला करने के लिए 'डार्क ईगल' की मांग की है। मंजूरी के बाद पहली बार डार्क ईगल की तैनाती की जाएगी। 'डार्क ईगल' को लांग-रेंज हाइपरसोनिक वेपन (एलआरएचडब्ल्यू) भी कहा जाता है। इसे लाकहीड मार्टिन कंपनी ने तैयार किया है। यह मिसाइल आवाज से पांच गुना तेज रफ्तार से उड़ान भर सकती है। हर मिसाइल की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ डालर है और ये एक बार में 2776 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकती है।

ट्रंप ने ईयू की कारों और ट्रकों पर लगाया 25 प्रतिशत टैरिफ

वाशिंगटन, रायटर: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ (ईयू) के देशों में बने वाहनों (कार और ट्रक) पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने का एलान किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ईयू के देश अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन पर यह टैरिफ लगाया जाएगा।

ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया पोस्ट में कहा है कि ईयू व्यापार समझौते में निर्धारित बिंदुओं का पालन नहीं कर रहा है। इसलिए ईयू देशों में बनी कार और ट्रकों पर अगले सप्ताह से टैरिफ बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन देशों की जो कंपनियां अमेरिका में कार और ट्रक बना रही हैं उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, इस निर्णय के बाद यूरोपीय कार निर्माता कंपनियां अपने कारखाने अमेरिका में लगाएंगी, इससे अमेरिका को बड़ा लाभ होगा। अगर ये कंपनियां अपने कारखाने अमेरिका में नहीं लगाएंगी तो वे टैरिफ के रूप में हर वर्ष अमेरिका को अरबों डालर देंगी। इससे पहले अगस्त 2025 में अमेरिका और ईयू के बीच व्यापार समझौता हुआ था और उसके तहत 15 प्रतिशत टैरिफ लगाने का निर्णय हुआ था।

पेंटागन ने एंथ्रोपिक को छोड़ सात एआइ कंपनियों के साथ किए समझौते

न्यूयार्क टाइम्स से

वाशिंगटन : पेंटागन ने कहा कि उसने सात एआइ कंपनियों के साथ समझौते किए हैं, ताकि उनकी उन्नत क्षमताओं को रक्षा विभाग के गोपनीय नेटवर्क पर तैनात किया जा सके। पेंटागन का उद्देश्य सैन्य क्षेत्र में एआइ प्रदाताओं की संख्या बढ़ाना है। इस बयान में एंथ्रोपिक का नाम शामिल नहीं है, जिसका पेंटागन के साथ सैन्य उपयोग पर सुरक्षा उपायों को लेकर विवाद चल रहा है।

पेंटागन ने इस एआइ स्टार्टअप को इस वर्ष की शुरुआत में आपूर्ति श्रृंखला के लिए खतरा बताया था और पेंटागन और उसके ठेकेदारों द्वारा इसके उपयोग पर रोक लगा दी थी। पेंटागन ने कहा कि नई वेब सर्विसेज के एआइ सिस्टम को वह अपने गुप्त और अति-गुप्त नेटवर्क में एकीकृत करेगा।

कोहिनूर हीरे की मांग पर ममदानी घिरे, अमेरिकी मीडिया ने पूछा, क्या आप भारत के प्रतिनिधि हैं?

न्यूयार्क, प्रेट्र : कोहिनूर हीरे की वापसी को लेकर बयान देने वाले न्यूयार्क के मेयर जोहरान ममदानी अब तीखे सवालों के घेरे में हैं। उनके बयान को जहां भारत के पक्ष में देखा जा रहा है, वहीं अमेरिका में बहस छिड़ गई है कि क्या एक न्यूयार्क मेयर को इस तरह किसी दूसरे देश के मुद्दे पर खुलकर बोलना चाहिए।

दरअसल, किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला के दौरे से पहले ममदानी ने कहा था कि मौका मिलने पर वे कोहिनूर की वापसी की बात उठाएंगे। हालांकि, 9/11 स्मारक पर कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। इसके बावजूद, अमेरिकी मीडिया खासतौर पर न्यूयार्क पोस्ट ने उनके बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संपादकीय में लिखा गया कि ममदानी ने किंग के प्रति फीका व्यवहार किया और औपचारिक स्वागत के दौरान

जोहरान ममदानी। फाइल

कूटनीतिक मर्यादा नहीं निभाई। अन्य रिपोर्टों में सवाल उठाया गया कि क्या ममदानी खुद को भारत का प्रतिनिधि मान रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि ममदानी ने औपनिवेशिक मुद्दों के एजेंडे को अलग नहीं रखा। इससे संदेश गया कि वे निजी विचारों को आधिकारिक भूमिका से ऊपर रख रहे हैं। यह विवाद ऐसे समय में उभरा है जब कोहिनूर पर वैश्विक स्तर पर बहस तेज हो रही है।

ट्रंप ने किंग चार्ल्स के सम्मान में दे दिया व्हिस्की गिफ्ट, हटाया टैरिफ

वाशिंगटन, रायटर : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की स्काच व्हिस्की पर लगे टैरिफ हटाने का ऐलान किया है। यह फैसला किंग चार्ल्स तृतीय और क्वीन कैमिला के चार दिन के अमेरिकी दौरे के समापन पर लिया गया। ट्रंप ने कहा कि यह कदम किंग और क्वीन के सम्मान में है और मुलाकात ने फैसले को प्रभावित किया। इस फैसले के पीछे तीन बड़ी वजहें रहीं पहली, ब्रिटेन के साथ रिश्तों में आई खटास को कम करना, दूसरी, लंबे समय से जारी व्यापारिक दबाव और तीसरी, 250वीं वर्षगांठ जैसा प्रतीकात्मक मौका। स्काच व्हिस्की इंडस्ट्री लंबे समय से 10 प्रतिशत टैरिफ हटाने की मांग कर रही थी, क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा बाजार है।

यूक्रेन के हमले में रूस के पोर्ट टर्मिनल में लगी भीषण आग

कीव, रायटर: यूक्रेन ने शुक्रवार को काला सागर के तट पर स्थित रूस के तुआप्से बंदरगाह पर फिर से ड्रोन हमला किया। हमले में बंदरगाह का टर्मिनल क्षतिग्रस्त हुआ जिससे कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने नजदीक स्थित आयल रिफायनरी को भी निशाना बनाया है। बताया गया है कि तेल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण इस बंदरगाह को गत 16 अप्रैल से यूक्रेन ने चौथी बार निशाना बनाया है।

हमले से लगी आग से उठ रहे धुएं और तेल के समुद्र के पानी में मिलने से इलाके के पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है। लोगों से घरों के दरवाजे-खिड़की बंद करके रहने के लिए कहा गया है। नजदीक के समुद्र के किनारों पर बने रिजार्ट और अन्य पर्यटन स्थल भी आग व तेल रिसाव से प्रभावित हुए हैं।

अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की निगरानी सूची में भारत को बरकरार रखा

▸ अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने रिपोर्ट में वियतनाम को सबसे अधिक चिंताजनक देश बताया

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत को बरकरार रखा है। प्राथमिकता निगरानी सूची में भारत के अलावा चीन, इंडोनेशिया, चिली, रूस और वेनेजुएला शामिल हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, "बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रवर्तन के मामले में भारत दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है।" अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि सभा द्वारा गुरुवार को जारी बौद्धिक संपदा संरक्षण और प्रवर्तन 2026 पर विशेष रिपोर्ट में वियतनाम को प्राथमिकता प्राप्त विदेशी देश (पीएफसी) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

पिछले 13 वर्षों में यह पहली बार है कि किसी देश को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। पीएफसी की पहचान उन देशों के लिए आरक्षित है, जिनके बौद्धिक संपदा संबंधी कृत्य, नीतियां और प्रथाएं सबसे गंभीर हैं और जिनका संबंधित अमेरिकी उत्पादों पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।" यह विशेष 301 रिपोर्ट अमेरिका द्वारा हर साल जारी की जाती है जिसमें 100 से अधिक व्यापारिक देशों में बौद्धिक संपदा अधिकारों की स्थिति का आकलन किया जाता है। इस निगरानी सूची में शामिल करने का अर्थ है कि उस देश में बौद्धिक संपदा संरक्षण, प्रवर्तन या बौद्धिक संपदा पर निर्भर अमेरिकी व्यक्तियों के लिए बाजार पहुंच के संबंध में विशेष समस्याएं मौजूद हैं। इस निगरानी सूची में यूरोपीय संघ, तुर्किये और पाकिस्तान सहित 19 देश शामिल हैं।

भारतीय अर्थशास्त्री केवी सुब्रमण्यम को शिकागो यूनिवर्सिटी का बड़ा सम्मान

वाशिंगटन, प्रेट्र : भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम को शिकागो विश्वविद्यालय ने प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए एलुमनाई अवार्ड से सम्मानित किया है। 1941 में शुरू हुए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाले वह पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं। कोविड-19 संकट के दौरान भारत की आर्थिक नीतियों में उनकी अहम भूमिका को विश्वविद्यालय ने खास तौर पर सराहा। उनके द्वारा तैयार किए गए आर्थिक सर्वेक्षणों को लैंडमार्क बताया गया, जिसने आत्मनिर्भरता, प्रतिस्पर्धी बाजार और समावेशी विकास की दिशा तय की।

वर्तमान में, केवी सुब्रमण्यम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने पीएचडी शिकागो विश्वविद्यालय के बूथ स्कूल आफबिजनेस से की है। पुरस्कार प्राप्त करने पर सुब्रमण्यम ने कहा कि यह उनके लिए अत्यंत गर्व की बात है कि यह सम्मान भारत से और भारत के लिए किए गए कार्यों के लिए मिला है।

अमेरिका के हाई स्कूल में हुई चाकूबाजी, छह घायल

▸ घायलों में सुरक्षा गार्ड और आरोपित छात्र भी, संदिग्ध छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया

वाशिंगटन, एपी : अमेरिका में गुरुवार को एक हाई स्कूल में चाकूबाजी की घटना में छह लोग घायल हो गए। घायलों में सुरक्षा गार्ड और आरोपित छात्र भी शामिल है। यह घटना वाशिंगटन के टैकोमा में हुई। पुलिस विभाग की प्रवक्ता शेल्बी बायड ने बताया कि संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है।

बायड ने कहा, "स्कूल सुरक्षित है और हम फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं।" टाकोमा पब्लिक स्कूल्स ने एक ईमेल बयान में बताया कि सोमवार को स्कूल फिर से खुलेगा और छात्रों व कर्मचारियों की सहायता के लिए काउंसलर मौजूद रहेंगे।

टेक्सास में छोटा विमान क्रैश, पांच लोगों की मौत : विंबरली : अमेरिका के विंबरली इलाके में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी पांच लोगों की मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार देर रात हुआ। शुरुआती जानकारी में विमान की गति काफी तेज बताई जा रही है, जिससे हादसा गंभीर हो गया। संघीय विमानन प्रशासन व राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है।

लंदन में यहूदी शख्स पर हमला करने वाले पर केस दर्ज

लंदन में दो यहूदी पुरुषों पर चाकू से हमला करने के आरोप में शुक्रवार को एक व्यक्ति पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। एस्सा सुलेमान पर गोल्डर्स ग्रीन में हुए हमले से संबंधित दो आरोप हैं। उसी दिन शहर में ही हुई अन्य घटना को लेकर उस पर हत्या के प्रयास का तीसरा आरोप भी लगाया गया है। उसका जन्म सोमालिया में हुआ था और वह ब्रिटिश नागरिक है।

ईरान युद्ध की आलोचना पर अमेरिका ने मालदीव से मांगा स्पष्टीकरण

वाशिंगटन, प्रेट्र: मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की कई बार आलोचना कर चुके हैं। उनके इस तल्ख रुख के बीच अमेरिका ने मालदीव की सरकार से संपर्क साधा और उस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत सर्जियो गोर और विदेश मंत्रालय की उप सहायक मंत्री बेथनी मारिसन ने मालदीव की विदेश मंत्री इरुथिशम आदम से बुधवार को बातचीत की और अमेरिका-मालदीव संबंधों पर चर्चा की। इसी दौरान मुइज्जू के बयान का मुद्दा उठाया गया। मुइज्जू ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका-इजरायल की आलोचना करते रहे और उन्होंने कई बार कहा है कि वह मुस्लिम बहुल मालदीव के किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल किसी भी रूप में युद्ध में मदद के लिए नहीं होने देंगे। बता दें कि गोर ने मार्च में मालदीव का दौरा किया था। मुइज्जू ने गोर से मिलने से मना कर दिया था। हालांकि तब उन्होंने मालदीव के विदेश और रक्षा मंत्रियों से मुलाकात की थी।

आम्यांमार की नेता आंग सान सू की को जेल से निकालकर घर में किया नजरबंद

▸ सैन्य शासन वाले देश को लोकतंत्र का आभास देने के उद्देश्य से उठाया गया कदम

संयुक्त राष्ट्र, आइएएनएस : म्यांमार की नेता आंग सान सू की को जेल से निकालकर घरम में नजरबंद कर दिया गया है। यह कदम सैन्य नेता मिन आंग ह्लाइंग के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सैन्य शासन वाले देश को लोकतंत्र का आभास देने के उद्देश्य से उठाया गया है। म्यांमार के सूचना मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने नाय प्यी ताव जेल में बंद आंग सान सू की की शेष सजा को नजरबंदी में बदलने का फैसला किया है। आंग सान सू की चुनी गई सरकार की स्टेट काउंसलर और वास्तविक नेता थीं, जिसे 2021 के तख्तापलट में सेना द्वारा उखाड़ फेंका गया था।

तख्तापलट का नेतृत्व करने वाले और सैन्य शासन के प्रमुख रहे वरिष्ठ जनरल आंग ह्लाइंग को तीन अप्रैल को संसद द्वारा राष्ट्रपति चुना गया। संसद का चुनाव इस साल हुआ, जिसमें आंग सान सू की की नेशनल लीग फार डेमोक्रेसी की भागीदारी नहीं थी, जिसे तख्तापलट के बाद 2021 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। चुनाव के बाद, अलगाव का सामना कर रही सरकार के लिए व्यापक अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति हासिल करने के प्रयास में आंग ह्लाइंग ने सामाजिक सुलह को बढ़ावा देने के लिए आम माफी का वादा किया था।

होर्मुज को बाईपास करके दुनिया को तेल बेचेगा यूएई

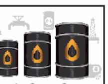

यूएई ने तेल निर्यात के लिए होर्मुल जलडमरूमध्य रूट का तोड़ निकाल लिया है। अब वह हबशान- फुजैराह तेल पाइपलाइन के जरिये तेल फुजैराह बंदरगाह तक पहुंचा सकता है और इसके बाद समुद्री मार्ग के जरिये कहीं भी तेल भेज सकता है। उसे इसके लिए होर्मुज जलडमरूमध्य पार करने की जरूरत नहीं है। भारत को इससे खास तौर से फायदा हो सकता है क्योंकि हाल में यूएई ने तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक से निकलने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर तेल उत्पादन की कोई सीमा लागू नहीं होगी और वह अपनी क्षमता के हिसाब से उत्पादन कर सकेगा। यह घटनाक्रम भारत के लिए भी बेहद सकारात्मक है क्योंकि होर्मुज जलमडमरूमध्य ब्लाक होने से खाड़ी देशों से तेल आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

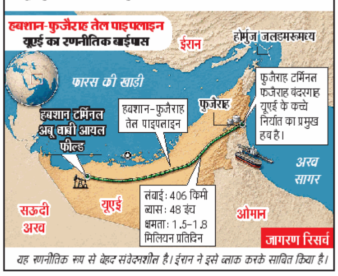

यह रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। ईरान ने इसे ब्लाक करके साबित किया है।

बल्लेबाज	रन
केएल राहुल	433
अभिषेक शर्मा	425
हेनरिक क्लासिन	414

दैनिक जागरण आइपीएल 19
धूम धड़ाका
www.jagran.com शनिवार 2 मई, 2026

गेंदबाज	विकेट
भुवनेश्वर कुमार	17
जोफ्रा आर्चर	15
इशान मलिंगा	15

रायल्स के गढ़ में दिल्ली का हल्ला बोल

दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रायल्स को सात विकेट से हराया पथुम निसंका और केएल राहुल ने खेली अर्धशतकीय पारी

शाट लगाते केएल राहुल ● प्रेट्र

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: गत चैंपियन रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध महज 75 रन पर सिमटने वाली दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार वापसी करते हुए राजस्थान रायल्स के घरेलू मैदान पर जमकर हल्ला बोला। पथुम निसंका (62) और केएल राहुल (75) की दमदार पारियों की बदौलत दिल्ली ने राजस्थान को सात विकेट से हराकर जीत की पटरी पर वापसी की। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी कर टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में राजस्थान ने टास जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। 12 रन पर यशस्वी जयसवाल और वैभव सूर्यवंशी के विकेट गंवाने के बाद भी राजस्थान ने छह विकेट पर 225 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने पांच गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। पिछले सत्र से इस मैदान पर राजस्थान ने सात में से छह मुकाबले गंवाए हैं।

राहुल की शानदार फार्म जारी: पंजाब के विरुद्ध 157 रन की बड़ी पारी खेलने के बाद राहुल ने एक बार फिर टीम के लिए अहम योगदान दिया। राहुल ने 40 गेंदों में 75 रन बनाए और यह उनका मौजूदा सीजन का तीसरा अर्धशतक रहा। वहीं, निसंका ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों में 62 रन ठोके, जो इस सत्र का उनका पहला अर्धशतक है। अंतिम दो ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 14 रन चाहिए थे, जिसे ट्रिस्टन स्टब्स (18) और आशुतोष शर्मा (25) ने बेहतरीन बल्लेबाजी से आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में आशुतोष को खिलाने का दांव सफल रहा।

उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं: पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान को उम्मीद के मुताबिक शुरुआत नहीं मिली। यशस्वी और वैभव टीम को तेज शुरुआत दिलाने में नाकाम रहे। जायसवाल ने तीन गेंदों पर छह रन बनाए, जबकि वैभव दो गेंदों में चार रन बनाकर आउट हो गए। काइल जैमीसन ने शानदार यार्कर डालते हुए वैभव को चकमा दिया। वैभव गेंद को रोकने के लिए बल्ला नीचे लाए, लेकिन हल्का किनारा लगने के बाद गेंद सीधे स्टंप से जा टकराई। विकेट लेने के बाद जैमीसन ने आपा खो दिया और वह कुछ ज्यादा ही आक्रामक अंदाज में जश्न मनाते नजर आए।

रियान ने खेली कप्तानी पारी: ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करते हुए पाए जाने के बाद चर्चा में आए कप्तान रियान पराग (90) ने अपने घरेलू मैदान पर शानदार वापसी की। दिल्ली के विरुद्ध उनका बल्ला जमकर चला। उन्होंने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न केवल कप्तानी पारी खेली, बल्कि मुश्किल परिस्थिति में टीम को संभालने का काम भी किया। शुरुआती झटकों के बाद रियान ने संयम के साथ खेलते हुए पारी को आगे बढ़ाया और टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। इस सीजन में अब तक उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था, लेकिन दिल्ली के विरुद्ध उन्होंने 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर फार्म में वापसी के संकेत दिए। हालांकि, वह अपने अर्धशतक को शतक में तब्दील नहीं कर सके। रियान ने 50 गेंदों का सामना करते हुए 90 रन की बेहतरीन पारी खेली, जो इस सीजन में उनका पहला अर्धशतक भी रहा। ध्रुव जुरैल और पराग के बीच तीसरे विकेट के लिए 59 गेंदों में 102 रन की अहम साझेदारी हुई। इसके बाद रियान ने स्टार आलराउंडर रवींद्र जडेजा के साथ चौथे विकेट के लिए 28 गेंदों में 53 रन की एक और उपयोगी साझेदारी की। अंतिम ओवरों में डोनोवन फरेरा ने तेजी से रन बटोरते हुए टीम के स्कोर को मजबूत किया। फरेरा ने 335.71 के जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए महज 14 गेंदों में दो चौके और छह छक्कों की मदद से 47 रन बनाए। वह अपने अर्धशतक से सिर्फ तीन रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस तूफानी पारी ने टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

स्टार्क ने दिलाई शुरुआती सफलता: इस सीजन में राजस्थान के विरुद्ध अपना पहला मैच खेल रहे मिशेल स्टार्क ने अपने पहले ही ओवर में विकेट हासिल किया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को आउट कर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। हालांकि, यशस्वी ने स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर बड़ा शाट खेलने के प्रयास में कैच आउट हो गए, जिसे खुद स्टार्क ने लपका। वहीं, स्टार्क ने अपने पहले ओवर में एक विकेट लेकर सात रन खर्च किए। हालांकि, उन्होंने अपने चार ओवर में 40 रन देकर सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए। दिलचस्प बात यह है कि वह आइपीएल इतिहास में पहली गेंद पर छक्का खाने वाले पांचवें गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले 2009 में ब्रैड हाज (केकेआर), 2019 में वरुण आरोन (आरआर), 2024 में नुवान तुषारा (एमआइ) और 2025 में खलील अहमद (सीएसके) भी यह अनुभव झेल चुके हैं।

8 वीं बार केएल राहुल ने आइपीएल में राजस्थान के विरुद्ध 50 या उससे अधिक रनों की पारी खेली। उन्होंने एबी डिविलियर्स (8) की बराबरी की। शिखर धवन और विराट कोहली 7-7 बार यह कारनामा कर चुके हैं

स्कोर बोर्ड

टास: राजस्थान (बल्लेबाजी) परिणाम: दिल्ली सात विकेट से जीती

राजस्थान रायल्स: 225/6 (20 ओवर)

	रन	गेंद	4/6
यशस्वी का. एंड बो. स्टार्क	6	3	0/1
सूर्यवंशी बो. जेमिसन	4	2	1/0
जुरैल का. स्टब्स बो. अक्षर	42	30	4/1
रियान का. अक्षर बो. स्टार्क	90	50	8/5
जडेजा का. आशुतोष बो. स्टार्क	20	14	1/1
फरेरा अविजित	47	14	2/6
शुभम का. आशुतोष बो. नटराजन	6	6	1/0
आर्चर अविजित	1	1	0/0

अतिरिक्त: 9 (लेबा: 3, वा: 6) विकेटपतन: 1-6 (जायसवाल, 0.3), 2-12 (सूर्यवंशी, 1.5), 3-114 (जुरैल, 11.4), 4-167 (जडेजा, 16.2), 5-168 (रियान, 16.4), 6-208 (शुभम, 19.1) गेंदबाजी: स्टार्क 4-0-40-3, जेमिसन 4-0-48-1, अक्षर 4-0-39-1, कुलदीप 4-0-41-0, नटराजन 4-0-54-1

दिल्ली कैपिटल्स : 226/3 (19.1 ओवर)

निसंका एलबीडब्ल्यू जडेजा	62	33	6/3
राहुल का. फरेरा बो. आर्चर	75	40	6/5
नीतीश का. जुरैल बो. देशपांडे	33	17	3/2
स्टब्स अविजित	18	11	1/1
आशुतोष अविजित	25	15	4/0

अतिरिक्त: 13 (बा: 4, लेबा: 1, वा: 7, नोबा: 1)

विकेटपतन: 1-110 (निसंका, 9.3), 2-171 (नीतीश, 14.3), 3-177 (राहुल, 15.2), गेंदबाजी: आर्चर 4-0-46-1, बर्गर 3-0-41-0, देशपांडे 4-0-38-1, ब्रिजेश 3.1-0-35-0, बिश्नोई 2-0-28-0, जडेजा 3-0-33-1

अंक तालिका		मैच	जीत	हार	रद	नेट रन रेट	अंक
1	पंजाब	8	6	1	1	+1.043	13
2	आरसीबी	9	6	3	0	+1.420	12
3	हैदराबाद	9	6	3	0	+0.832	12
4	राजस्थान	10	6	4	0	+0.510	12
5	गुजरात	9	5	4	0	-0.192	10
6	दिल्ली	9	4	5	0	-0.895	8
7	चेन्नई	8	3	5	0	-0.121	6
8	कोलकाता	8	2	5	1	-0.751	5
9	मुंबई	8	2	6	0	-0.784	4
10	लखनऊ	8	2	6	0	-1.106	4

चेन्नई-मुंबई में आज करो या मरो की होगी टक्कर

एमएस धौनी, सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा ● एक्स

चेन्नई, प्रेट्र: अब तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और मुंबई इंडियंस की टीमों के बीच आइपीएल में शनिवार को यहां करो या मरो का मुकाबला होगा, जिसमें दोनों का लक्ष्य प्लेआफ की दौड़ में बने रहने की उम्मीद जीवंत रखना होगा। आइपीएल इतिहास की दो सबसे सफल टीम का अब तक का अभियान निराशाजनक रहा है और वे लय हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हैं। सीएसके के लिए एमए चिदंबरम स्टेडियम की परिस्थितियां अनुकूल रही हैं लेकिन उनके प्रदर्शन में वह प्रभाव देखने को नहीं मिला है जो वर्षों से उसकी पहचान रही है।

सीएसके की बल्लेबाजी में निरंतरता का अभाव: सीएसके की बल्लेबाजी में निरंतरता का अभाव रहा है। विशेषकर उसके बल्लेबाज बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। उसके गेंदबाज भी दबाव वाली परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जूझ रहे हैं। मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन भी इस सत्र में उतार-चढ़ाव वाला रहा है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बावजूद पांच बार की चैंपियन टीम को कमजोर मध्य क्रम और गेंदबाजों ने निराश किया है। उसके गेंदबाज स्कोर का बचाव करने, महत्वपूर्ण मौकों पर बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में विफल रहे।

चेन्नई सुपर किंग्स: रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), एमएस धौनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल, अमन खान, शिवम दुबे, जैक फाल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, ओवरटन, मैथ्यू शार्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजपनीत, हेनरी, अकील, जानसन, मुकेश, नूर अहमद।

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पांड्या (कप्तान), क्विंटन डिकाक (विकेटकीपर), रियान रिकेल्टन (विकेटकीपर), राबिन मिंज, दानिश मालेवार, शेरफेन रदरफोर्ड, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक, राज बावा, कार्बिन बाश, विल जैक, मयंक रावत, नमन धीर, शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, कृष भगत, एएम गजनफर, केशव महाराज, मयंक मारकंडे, मोहम्मद इजहार, रघु शर्मा।

खेल डायरी

एक महीने तक नहीं खेल पाएंगे सेंटनर

सेंटनर ● फाइल फोटो, आइएएनएस

आकलैंड, प्रेट्र: न्यूजीलैंड की सीमित ओवरों की टीम के कप्तान मिशेल सेंटनर आईपीएल के दौरान कंधे में लगी चोट के कारण कम से कम एक महीने तक मैदान से बाहर रहेंगे। इस 34 वर्षीय खिलाड़ी को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बीच 23 अप्रैल को खेले गए मैच के दौरान फील्डिंग करते समय बाएं कंधे में चोट लग गई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने शुक्रवार को कहा कि सेंटनर इस सप्ताह न्यूजीलैंड लौट आए हैं और आज सुबह एक विशेषज्ञ से मिले, जिन्होंने बताया कि उन्हें कम से कम एक महीने के आराम और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है। सेंटनर ने आइपीएल मैच के दौरान जसप्रीत बुमराह की गेंद पर सीएसके के कार्तिक शर्मा का डाइव लगाकर कैच लिया, लेकिन इस दौरान उनके कंधे और सिर में चोट लग गई। इस कारण वह आयरलैंड के विरुद्ध एकमात्र टेस्ट और इंग्लैंड के विरुद्ध पहले टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। एनजेडसी ने कहा कि दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए उनकी उपलब्धता पर फैसला बाद में किया जाएगा। न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच एकमात्र चार दिवसीय टेस्ट मैच 27 मई से होगा।

आकाश व हर्षित का अफगानिस्तान-इंग्लैंड दौरे के लिए फिट होना मुश्किल

आकाश दीप

हर्षित राणा

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज आकाश दीप और हर्षित राणा का अफगानिस्तान के विरुद्ध होने वाली घरेलू सीरीज और इंग्लैंड के सफेद गेंद के दौरे के लिए फिट होना मुश्किल है। इन दोनों को पूरी तरह से मैच फिट होने में अभी कुछ समय लगेगा। आकाश दीप फिलहाल पीठ की चोट से उबर रहे हैं जबकि राणा की घुटने की सर्जरी हुई थी। यह सर्जरी भारत में टी-20 विश्व कप शुरू होने से कुछ ही दिन पहले 'लिगामेंट' फटने के कारण हुई थी।

कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अनुबंधित ये दोनों खिलाड़ी आइपीएल में नहीं खेल रहे हैं। इस मामले पर नजर रख रहे बीसीसीआइ के एक सूत्र ने बताया कि आकाश और हर्षित का रिहैबिलिटेशन सही ट्रैक पर है, लेकिन उन्हें मैच खेलने के लिए मंजूरी मिलने में अभी काफी समय लगेगा। अगर हम अफगानिस्तान और ब्रिटेन दौरे की बात करें तो इन दोनों के उस समय तक फिट होने की कोई संभावना नहीं है। वे अभी भी मजबूती बढ़ाने वाला व्यायाम कर रहे हैं। उसके बाद जागिंग, तेज चलना, स्प्रिंट और फिर 'रिटर्न टू प्ले' प्रोटोकाल से जुड़े कौशल का अभ्यास होगा।

टेस्ट रैंकिंग में इंग्लैंड को पछाड़कर तीसरे स्थान पर भारत

शुभमन गिल

नई दिल्ली, एएनआइ: आइसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम बड़ी छलांग लगाई है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। वहीं आस्ट्रेलिया टीम शीर्ष पर बनी हुई है। सालाना रैंकिंग अपडेट में मई 2025 के बाद खेले गए सभी मुकाबलों को पूरा वेटेज दिया जाता है, जबकि पुराने मुकाबलों के नतीजों का असर घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाता है। इस वार्षिक अपडेट के चलते शीर्ष-2 टीमों के नीचे की रैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें भारत को फायदा हुआ। आस्ट्रेलियाई टीम 131 रेटिंग अंक के साथ शीर्ष पर मजबूती से कायम है। इस टीम ने तीन अंक की मामूली बढ़त के साथ अपना दबदबा बढ़ा लिया है। दूसरे पायदान पर मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका भी दूसरे स्थान पर स्थिर है। इस टीम के पास 119 रेटिंग अंक हैं। वहीं तीसरे पायदान पर पहुंची भारत टीम के पास 104 अंक हैं। वहीं, एक स्थान नीचे लुढ़कने के बाद इंग्लैंड की टीम 102 रेटिंग अंक के साथ चौथे पायदान पर है। इंग्लैंड के एक पायदान नीचे फिसलने की वजह यह रही कि उसे अपनी कई पुरानी सीरीज के नतीजों से मिलने वाला फायदा अब नहीं मिल रहा है।

इस तालिका में न्यूजीलैंड 101 रेटिंग अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बना हुआ है, जबकि पाकिस्तानी टीम ने एक स्थान की छलांग लगाते हुए छठा पायदान अपने नाम कर लिया है। श्रीलंकाई टीम एक पायदान नीचे खिसककर सातवें स्थान पर पहुंच गई है। जबकि शीर्ष-10 की बाकी टीमें जस की तस बनी हुई हैं। जिनमें वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, आयरलैंड क्रमशः 8वें, 9वें और 10वें पायदान पर हैं। हालांकि भारतीय टीम आइसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025-27 में फिलहाल छठे स्थान पर है। भारत का अंकों का प्रतिशत (पीसीटी) 48.15 है, जिसका कारण इस चक्र में घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध सीरीज और आस्ट्रेलिया दौरे पर बार्डर-गावस्कर ट्राफी में हार है।

रैंकिंग में इंग्लैंड महिला टीम ने भारत पर बढ़त मजबूत की

नई दिल्ली, प्रेट्र: इंग्लैंड ने ताजा महिला वनडे रैंकिंग में मौजूदा विश्व चैंपियन भारत पर अपनी बढ़त बढ़ा ली है और चार अंक की बढ़त से दूसरे स्थान पर है जबकि हरमनप्रीत कौर की टीम भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर है। आस्ट्रेलिया 163 रैंकिंग अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर बरकरार है। पिछले साल दक्षिण अफ्रीका पर जीत के साथ अपना पहला वनडे विश्व कप खिताब जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने तब से तीन वनडे खेले हैं जिसमें आस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से क्लीन स्वीप की। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आइसीसी) ने कहा कि इंग्लैंड ने भारत पर अपनी बढ़त एक अंक से बढ़ाकर चार अंक कर ली है।

हैदराबाद टीम में मावी की जगह अंबरीश शामिल

नई दिल्ली, प्रेट्र: सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार को चोटिल खिलाड़ी शिवम माही की जगह आइपीएल के बाकी मैचों के लिए आरएस अंबरीश को अपनी टीम में शामिल किया। आइपीएल ने एक बयान में कहा कि दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज मावी ग्रोइन चोट के कारण इस सत्र से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह पर आलराउंडर अंबरीश टीम में आएंगे, अंबरीश इस साल की शुरुआत में विश्व कप जीतने वाली भारतीय अंडर-19 टीम का हिस्सा थे। वह इस टूर्नामेंट में भारतीय अंडर-19 के लिए संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी थे, जिसमें उनके नाम 11 विकेट थे। आरएस अंबरीश दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। वह सनराइजर्स हैदराबाद में 30 लाख रुपये में शामिल होंगे।

आगे भी पढ़ाई जारी रखेंगे क्रिकेटर इशान किशन

जागरण संवाददाता, जालंधर: भारतीय क्रिकेटर इशान किशन जल्द ही लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में दाखिला लेने जा रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि वे किस प्रोग्राम या डिप्लोमा में दाखिला लेंगे। इशान ने पटना के कालेज आफ कामर्स से बीकाम किया है और वर्तमान में आइपीएल में व्यस्त हैं। संभावना है कि आइपीएल के बाद वे दाखिले की प्रक्रिया पूरी करेंगे। हाल ही में इशान किशन को एलपीयू में आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की इच्छा व्यक्त की थी। उन्होंने कैंपस के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और यूनिवर्सिटी के प्रोग्रामों और डिप्लोमा के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इशान ने कमर्शियल कांप्लेक्स, फूड कोर्ट, रिटेल स्टोर और मनोरंजन क्षेत्र का भी अवलोकन किया था। उन्होंने कहा था कि अपने जीवन का अधिकांश समय होटल के कमरों और क्रिकेट स्टेडियमों में बिताने के बाद यूनिवर्सिटी आकर एक नया अनुभव मिला। इशान ने अपने जीवन अनुभव साझा किए।

शाट गन विश्व कप में खेलेगी 12 सदस्यीय टीम

नई दिल्ली, प्रेट्र: कजाकिस्तान के अल्माटी में होने वाले इस साल के दूसरे आइएसएसएफ शाटगन विश्व कप में भारत की 12 सदस्यीय निशानेबाजी टीम भाग लेगी। भारतीय टीम शनिवार को आयोजन स्थल पर पहुंचेगी। दस दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 42 देशों के 284 खिलाड़ी भाग लेंगे। भारतीय टीम के आठ सदस्य भी आरपीओ (केवल रैंकिंग अंक के लिए) निशानेबाज के रूप में प्रतिस्पर्धा करने के लिए इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता सोमवार (चार मई) को पुरुषों और महिलाओं के स्कीट क्वालीफायर के साथ शुरू होंगी। इस स्पर्धा के फाइनल पांच मई को होंगे। ट्रैप स्पर्धा के दो फाइनल नौ मई को जबकि ट्रैप मिक्स्ड टीम का फाइनल अगले शनिवार यानी 10 मई को होगा। विश्व कप का पहला चरण मार्च में मोरक्को के तांजियर में खेला गया था। दूसरे चरण की प्रतियोगिता के पहले दिन तीन भारतीय ओलिंपियन में पुरुष स्कीट स्पर्धा में मैराज अहमद खान और अनंतजीत सिंह नारुका तथा महिला स्कीट स्पर्धा में रायजा ढिल्लों हिस्सा लेंगी।

सिनर ने दर्ज की करियर की 350वीं जीत

जानिक सिनर ● रायटर

मैड्रिड, एपी: शीर्ष रैंकिंग वाले जानिक सिनर ने शुक्रवार को आर्थर फिल्स को 6-2, 6-4 से हराकर मैड्रिड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई और अपनी जीत का सिलसिला 22 मैचों तक बढ़ा दिया। इस इतालवी खिलाड़ी के करियर की यह 350वीं जीत है, जिसके साथ वह 2000 के दशक में जन्मे पहले ऐसे पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। सेमीफाइनल में एक भी ब्रेक पाइंट का सामना न करने के बाद कोर्ट पर दिए एक इंटरव्यू में सिनर ने कहा कि मैं आज के अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हूं। मैं अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन टेनिस खेलने की कोशिश कर रहा हूं। आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। सिनर लगातार पांच मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। वह रविवार को होने वाले फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव या बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लाक्स का सामना करेंगे।

इस साल के आखिर में संन्यास लेंगे निशिकोरी

टोक्यो, एपी: विश्व के पूर्व चौथे नंबर के खिलाड़ी और 2014 में यूएस ओपन के फाइनलिस्ट केई निशिकोरी ने कहा कि वह इस टेनिस सत्र के आखिर में संन्यास लेने की योजना बना रहे हैं। जापान के 36 वर्षीय निशिकोरी दाहिने कंधे में दर्द के कारण जनवरी में आस्ट्रेलियाई ओपन में नहीं खेल पाए थे। वह पिछले कई वर्षों से चोटों से जूझ रहे हैं और पिछले साल यूएस ओपन में भी नहीं खेल पाए थे।

फेड कप में हिस्सा न लेने पर लग सकता है प्रतिबंध: एएफआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र: 22 से 25 मई तक रांची में होने वाले राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कप में प्रविष्टि मिलने के बाद बिना किसी ठोस वजह के शामिल न होने वाले एथलीटों पर बाद की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (एएफआइ) ने इसकी घोषणा की है। पिछले कुछ साल से एएफआइ को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है । इसकी वजह शायद यह डर है कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी उनका डोप परीक्षण कर सकती है। फेडरेशन कप में सिर्फ वही एथलीट हिस्सा ले पाएंगे, जिन्होंने इस साल के दौरान एएफआइ की कम से कम दो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया हो।

चीनी ताइपे को हराकर थामस कप के सेमीफाइनल में भारत

आयुष शेट्टी ● बैडमिंटन फोटो

होर्सेंस, प्रेट्र: लक्ष्य सेन की जोरदार वापसी के बाद सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की डबल्स जोड़ी तथा युवा आयुष शेट्टी के बेहतरीन खेल के प्रदर्शन से भारत ने शुक्रवार को चीनी ताइपे के विरुद्ध 3-0 की अजेय बढ़त हासिल करके थामस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल्स के सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इस जीत से भारत का इस टूर्नामेंट में पदक भी पक्का हो गया है।

लक्ष्य अधिकतर समय पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्होंने एक घंटे और 28 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में 18-21, 22-20, 21-17 से जीत दर्ज की। इसके बाद सात्विक और चिराग की डबल्स जोड़ी ने चियू सियांग चिएह और वांग ची-लिन को एक घंटे और 15 मिनट में 23-21 19-21 21-12 से हराया। फिर आयुष शेट्टी ने दूसरे सिंगल्स में विश्व में नंबर आठ और मौजूदा आल इंग्लैंड ओपन चैंपियन लिन चुन-यी को 21-16, 21-17 से हरा दिया।

कूपर कोनोली के खेल का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं: जैक मेडालेना

जैक मेडालेना ● यूएफसी

खेल संवाददाता, नई दिल्ली: आइपीएल में अपनी बल्लेबाजी से धमाल मचा रहे पंजाब किंग्स के आस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कूपर कोनोली के प्रशंसकों में आस्ट्रेलियाई एमएमए फाइटर जैक डेला मेडालेना भी हैं और उनका खेल बहुत भाता है। जैक शनिवार को पर्थ में यूएफसी फाइट नाइट में वेल्टरवेट वर्ग में ब्राजीली कार्लोस प्रेट्स से भिड़ेंगे। इस फाइट का प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर शाम 4:30 बजे से होगा।

जैक डेला मेडालेना ने फाइट से पहले दैनिक जागरण से विशेष बातचीत की। उन्होंने कहा कि एमएमए के अलावा मुझे क्रिकेट काफी पसंद है। हर आस्ट्रेलियाई की तरह मैं भी टेस्ट क्रिकेट का बड़ा प्रशंसक हूं और बड़े मुकाबले देखना मुझे पसंद है। जब जैक से उनके पसंदीदा क्रिकेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में उन्हें कूपर कोनोली का खेल बहुत पसंद है। वह भी मेरी तरह पर्थ से आते हैं और तेजी से अपना नाम बना रहे हैं। मुझे उन्हें खेलते देखना अच्छा लगता है।

पर्थ में आज होने वाली यूएफसी फाइट नाइट में ब्राजील के प्रेट्स से होगा जैक का सामना

फिलिस्तीन-इजरायल फुटबाल अधिकारियों ने नहीं मिलाया हाथ

फुटबाल डायरी

फिलिस्तीन के राजौब (बाएं), फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो और इजरायल के बासिम ● एपी

वैंकूवर, एपी: जून में होने वाले फुटबाल विश्व कप से पहले फीफा कांग्रेस में एक मंच पर जुटे इस वैश्विक फुटबाल संस्था के पदाधिकारियों के बीच माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया, जब फिलिस्तीन फुटबाल एसोसिएशन (पीएफए) के अध्यक्ष जिब्रिल राजौब ने इजरायल की फुटबाल शासी निकाय के उपाध्यक्ष बासिम शेख सुलेमान से हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया।

दोनों पदाधिकारियों द्वारा कांग्रेस को संबोधित करने के बाद इन्हें फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने मंच पर बुलाया। इस दौरान वे एक-दूसरे से काफी दूरी पर खड़े रहे और मंच छोड़ने से पहले राजौब ने माइक्रोफोन से दूर हटकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। इससे पहले कांग्रेस को संबोधित करते हुए, राजौब ने फीफा से फिलिस्तीन फुटबाल एसोसिएशन के उन आरोपों पर ध्यान देने का आग्रह किया, जिनमें कहा गया था कि इजरायल ने वेस्ट बैंक बस्तियों में स्थित क्लबों को अनुमति देकर भेदभाव-विरोधी नियमों का उल्लंघन किया है। हालांकि फीफा अध्यक्ष इन्फेंटिनो ने दोनों पदाधिकारियों से कहा आइए हम मिलकर काम करें।

ईरान विश्व कप में हिस्सा लेगा: इन्फेंटिनो: इन्फेंटिनो ने फीफा कांग्रेस में अपने भाषण की शुरुआत इस बात की पुष्टि करते हुए की कि ईरान वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा और दोनों देशों के बीच विवाद के बावजूद ईरान अमेरिका में खेलेगा।

वुड के पेनाल्टी गोल से सेमीफाइनल में जीता फारेस्ट

नाटिंघम, एपी: क्रिस वुड ने पेनाल्टी गोल करके नाटिंघम फारेस्ट को यूरोपा लीग सेमीफाइनल के पहले लेग में एस्टन विला पर 1-0 से जीत दिलाई। इस जीत ने फारेस्ट को 46 साल में अपने पहले कान्टिनेंटल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के एक कदम और करीब ला दिया है। वुड ने 71वें मिनट में मिली पेनाल्टी को गोल के ऊपरी हिस्से में जोर से मारा, जिससे गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को इसे बचाने का कोई मौका नहीं मिला। विला के डिफेंडर लुकास डिग्ने के हैंडबाल करने पर यह पेनाल्टी मिली थी। दूसरा लेग बर्मिंघम में अगले गुरुवार को होगा।

क्रिकेट और स्पोर्ट्स की अन्य खबरों के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

बीफार्मा से कई गुना बढ़ जाएंगे करियर विकल्प

काउंसलर

अपर्णा गौतम
councelor@nda.jagran.com

मैंने डीफार्मा किया है। आगे किस डिप्लोमा या डिग्री कोर्स में एडमिशन लेना सही रहेगा, ताकि अच्छा करियर बनाया जा सके?

विवेक साहू

डीफार्मा के बाद आपके पास कई स्पष्ट और मजबूत रास्ते हैं, लेकिन सही चुनाव इस पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आप क्लीनिकल या मेडिकल फील्ड में गहराई चाहते हैं तो बीफार्मा करना सबसे बेहतर अगला कदम है, यह आपके करियर के विकल्पों को कई गुना बढ़ा देगा, जैसे- फार्मा कंपनियां, रिसर्च या हास्पिटल सेक्टर। अगर आप जल्दी कमाई शुरू करना चाहते हैं तो रिटेल या हास्पिटल फार्मेसी में काम शुरू कर सकते हैं और साथ में आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

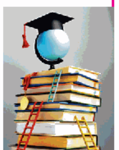

मैंने बीकाम, एमकाम और मास्टर आफ लाइब्रेरी एंड इन्फार्मेशन साइंस किया है। लाइब्रेरी साइंस में नेट भी क्वालिफाई हूं। अब समझ में नहीं आ रहा कि कालेज लाइब्रेरियन या लिपिकीय (क्लेरिकल) जाब में से कौन सा विकल्प चुनूं। कृपया बताएं।

जतिन बावेजा

लिपिकीय नौकरी स्थिर हो सकती है, लेकिन उसमें ग्रोथ, प्रोफेशनल पहचान और पे-स्केल की ऊपरी सीमा सीमित रहती है। दूसरी ओर, लाइब्रेरियन के रूप में आप अकादमिक इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं, जहां अनुभव के साथ पे-लेवल, प्रमोशन और सम्मान तीनों बढ़ते हैं। मेरी सलाह है कि अगर आपको अपने विषय में रुचि है तो लाइब्रेरियन की दिशा में ही आगे बढ़ें।

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत चार वर्षीय डिग्री के बाद एक वर्षीय पोस्टग्रेजुएशन (एमए) का प्रविधान है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी भी दो वर्षीय पीजी ही चल रहा है। ऐसे में एक वर्षीय पीजी करना चाहें तो क्या करें?

मीना धानिया

आपके पास अभी दो विकल्प हैं- पहला, आप डीयू में ही दो वर्षीय पीजी करें, जो पूरी तरह मान्य और स्थिर विकल्प है। दूसरा, आप ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थानों की तलाश करें, जहां एनईपी के तहत एक वर्षीय पीजी प्रोग्राम लागू हो चुका है। यह समझना जरूरी है कि करियर में डिग्री की अवधि से ज्यादा डिग्री की गुणवत्ता और आपकी समझ मायने रखती है। इसलिए सोच-समझकर संस्थान का चयन करें।

इस पेज के बारे में अपनी राय और सुझाव भेजें
-feature@jagran.com

संभावनाओं से भरा क्षेत्र कोर इंजीनियरिंग

टर्निंग प्वाइंट

फोटो : फ्रीपिक

आज आइटी सेक्टर तेजी से बदलते डिजिटल युग की रीढ़ बन चुका है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं की रुचि बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कोर इंजीनियरिंग की मांग और संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं, ऐसा क्यों? इस बारे में बता रहे हैं बीएचयू के वाइस चांसलर **प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी**...

भले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) या प्राम्प्ट इंजीनियरिंग में आजकल युवाओं को आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ ग्लोबल एक्सपोजर और अच्छी करियर ग्रोथ मिल रही है, फिर भी कोर इंजीनियरिंग यानी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स जैसे ट्रेड का महत्व आज भी कम नहीं है। देश की प्रगति और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आज भी यही बुनियादी फील्ड माने जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में न केवल तकनीकी समझ विकसित हो रही है, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स के जरिये स्थायी करियर की संभावनाएं भी मजबूत हो रही हैं।

इंसान के बिना अपंग है एआइ: अगर हमें लगता है कि एआइ अकेले हर काम कर सकता है तो हम गलत हैं। कोर इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रिज है, जो तकनीक का इस्तेमाल करके बुनियादी आधार पर विकास करता है, जैसे-अगर आपको कोई सड़क, एयरपोर्ट या फिर रेलवे स्टेशन बनाना है तो इसके लिए इंजीनियर्स की जरूरत होगी। हां, एआइ की मदद से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी बन सकते हैं, इनकी गुणवत्ता में सुधार आ सकता है, लेकिन अकेले एआइ मानव सभ्यता का विकास नहीं कर सकता है। इसलिए आज के युवाओं को एआइ से डरने की नहीं, बल्कि एआइ को साथ लेकर चलने की जरूरत है। इससे उनके कार्य में तेजी आएगी और सफलता की राह आसान होगी।

युवाओं में बढ़ रही तकनीकी समझ

एआइ के आने से एक अच्छी बात यह हुई है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल और तकनीकी प्रशिक्षक बनते जा रहे हैं। उनमें जानकारी हासिल करने की ललक बढ़ गई है। वे काफी कुछ जानने और सीखने लगे हैं। यह आज के समय की जरूरत भी है।

मानवीय समझ व रचनात्मकता जरूरी: तकनीक के दुरुपयोग को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि आंख बंद करके एआइ पर भरोसा न किया जाए। ऐसा करने वालों को पछतावे का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति एआइ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए भी अपनी समझ और रचनात्मकता को भूलता नहीं है, वही सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है। उदाहरण के तौर पर जब भी देश में कोई तकनीकी क्रांति आई है, तब रोजगार संबंधित कई सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, लेकिन धीरे-धीरे उन तकनीकों को अपनाते हुए लोग आगे बढ़ते गए। एक वक्त था, जब कंप्यूटर आने से लोगों के मन में डर के बादल छा गए थे, लेकिन आज कंप्यूटर के बदलते वर्जन मनुष्य जाति को स्पेस तक पहुंचाने में सक्षम हैं। इसलिए किसी भी नई चीज से घबराने या उसे दूर हटाने से समाधान नहीं मिलता है, बल्कि उसे साथ लेकर चलने से विकास की गति और तेज होती है।

आर्थिक विकास से बढ़ेगा रोजगार: किसी भी देश के आर्थिक विकास में युवाओं का बड़ा योगदान है। ऐसे में अगर देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो रोजगार के अवसर भी जरूर बढ़ेंगे। हां, युवाओं को बेचैनी होना स्वाभाविक है कि एआइ उनकी जाब्स न छीन ले या इससे कहीं जाब्स खत्म न हो जाए, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि एआइ रास्ते बंद नहीं कर रहा है, बल्कि कई नए रास्ते खोल रहा है। एआइ की मदद से आर्थिक विकास को गति मिल रही है और इससे रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती नजर आ रही हैं। इसलिए आप भी इसकी जरूरत को पहचानें।

बातचीत : सुमन अग्रवाल

इन क्षेत्रों में बढ़ेगी मांग

एआइ के बढ़ते प्रभाव के बावजूद इंजीनियरिंग के निम्न पेशेवरों की मांग आगे भी बनी रहेगी, जैसे कि:

- मैकेनिकल इंजीनियर
- सिविल साइट इंजीनियर
- इलेक्ट्रिकल मेंटिनेंस इंजीनियर
- प्रोडक्शन इंजीनियर
- क्वालिटी एनालिस्ट
- विनिर्माण- आटोमोबाइल, रक्षा, एयरोस्पेस, ऊर्जा और निर्माण प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसके छात्रों का चयन करने के लिए आज भी हर साल तमाम बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं।

लाइफ स्किल

सीखें भविष्य का हुनर

आज का दौर तकनीकी क्रांति का है। जहां एक ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) को नौकरियों के लिए खतरा माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर वर्ल्ड इकोनामिक फोरम की फ्यूचर आफ जाब्स रिपोर्ट की मानें तो एआइ इंसानी क्षमताओं को खत्म नहीं, बल्कि री-डिफाइन करेगा यानी अब केवल डिग्री या किताबी ज्ञान काफी नहीं है। आज के युवाओं के लिए 'एआइ-एन्हांस्ड साफ्ट स्किल्स' सफलता की नई कुंजी है।

संवित श्रीवास्तव
लाइफ कोच

क्या है यह नया ट्रेंड?: रिपोर्ट्स की मानें तो आने वाले समय में उन युवाओं की मांग सबसे अधिक होगी, जो तकनीक के साथ अपनी मानवीय संवेदनाओं और तर्कशक्ति का सही संतुलन बना सकेंगे। इसे 'को-पायलट वर्किंग कल्चर' कहा जा रहा है। इसका अर्थ है कि मशीन आपका काम नहीं करेगी, बल्कि मशीन आपकी सहायक होगी, लेकिन उस सहायक से श्रेष्ठ परिणाम निकलवाना एक कला है, जिसे आपको सीखना होगा।

कौशल के नए क्षेत्र: आज के समय में कई ऐसे उभरते क्षेत्र हैं, जहां अवसर ही अवसर हैं, जैसे कि:

प्राम्प्ट इंजीनियरिंग और एआइ साक्षरता: अब कोडिंग जानना ही अनिवार्य नहीं है। अगर आप एआइ से सही सवाल पूछना जानते हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन से लेकर डाटा एनालिसिस तक किसी भी क्षेत्र में अपनी उत्पादकता को 10 गुना बढ़ा सकते हैं।

क्रिटिकल थिंकिंग और प्राब्लम साल्विंग: एआइ आपको जानकारी दे सकता है, लेकिन निर्णय और नैतिकता की परख केवल एक इंसान ही कर सकता है। यही कारण है कि आज उद्योगों को ऐसे युवाओं/प्रोफेशनल्स की तलाश है, जो डाटा के पीछे की कहानी समझ सकें।

डिजिटल एथिक्स और प्राइवेसी: जैसे-जैसे तकनीक बढ़ रही है, साइबर सुरक्षा और एथिकल एआइ के क्षेत्र में करियर के नए द्वार खुल रहे हैं। साथ ही अंग्रेजी भाषा का आप जितना अच्छे से अभ्यास करेंगे, उतनी ही अच्छी कमाई के अवसर भी मिलेंगे।

तकनीक का सही उपयोग: आज के युवाओं को यह बात समझनी होगी कि अपनी पसंद का करियर बनाने के लिए केवल इंटरनेट मीडिया पर स्क्राल करना ही अब काफी नहीं है। तकनीक को अपना 'करियर कोच' बनाएं। लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्म्स का उपयोग केवल नेटवर्किंग के लिए नहीं, बल्कि 'स्किल-गैप एनालिसिस' के लिए करें। देखें कि आपके ड्रीम जाब प्रोफाइल में कौन से नए टूल्स मांगे जा रहे हैं और उन्हें आनलाइन कोर्सेज के जरिये सीखें।

बदल रहा आफिस एटिकेट: डिजिटल युग के आफिस एटिकेट बदल रहे हैं। अब वर्चुअल प्रेजेंस भी उतनी ही मायने रखती है, जितना फिजिकल उपस्थिति। ऐसे में वीडियो काल के दौरान बाडी लैंग्वेज और समय प्रबंधन आज के अनिवार्य लाइफ स्किल्स हैं।

मनोबल न खोएं

अक्सर नए ट्रेंड्स को देखकर युवा घबरा जाते हैं कि क्या वे इस रेस में टिक पाएंगे? याद रखें, तकनीक केवल एक साधन है। ऐसे में आपकी सीखने की ललक ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगी। बदलाव से डरें नहीं, बदलाव के सारथी बनें।

आज का भविष्यफल : 2 मई, 2026 शनिवार

पं. के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा का राशिफल। **राहुकाल:** प्रातः 09 बजे से 10 बजकर 30 मिनट तक। **दिशाशूल :** पूर्व। **विशेष :** ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष प्रारंभ।

कल 3 मई, 2026 का पंचांग

कल का दिशाशूल : पश्चिम **विशेष :** देवर्षि नारद जयंती।

उत्तरगोल, वसंत ऋतु ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की द्वितीया 27 घंटे 03 मिनट तक, तत्पश्चात तृतीया, विशाखा नक्षत्र 07 घंटे 10 मिनट तक तत्पश्चात अनुराधा नक्षत्र, वरियान योग 22 घंटे 28 मिनट तक, तत्पश्चात परिघ योग, वृश्चिक में चंद्रमा।

मेष : मौसमी रोगों के प्रति सचेत रहें। आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं।

वृष: दांपत्य जीवन सुखमय होगा। नेत्र या उदर विकार से सचेत रहें।

मिथुन : शाही खर्च से बचना होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कर्क: जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

सिंह: आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। संपत्ति में वृद्धि के योग हैं।

कन्या : भाई-बहन का सहयोग मिलेगा। प्रयास फलीभूत होगा।

तुला : आर्थिक मामलों में सुधार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

वृश्चिक: धन, सम्मान में वृद्धि होगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे।

धनु : मन अशांत रहेगा। व्यर्थ का भय भी हो सकता है।

मकर: शैक्षिक सफलता मिलेगी। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

कुंभ : महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। रिश्तों में निकटता आएगी।

मीन : सम्मान का लाभ मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ से मुक्ति मिलेगी।

संदेश : एक मई के अवकाश के कारण आज वर्ग पहेली और सुडोकू स्थगित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय फलक

दुधवा के गैंडा क्षेत्र में पर्यटकों के भ्रमण पर अस्थायी रोक

जागरण संवाददाता, लखीमपुर

- दुधवा प्रशासन हाथियों के व्यवहार में आए बदलाव को लेकर गंभीर
- हाथी विनायक के हिंसक होने के बाद विशेषज्ञों की टीम रखेगी नजर

दुधवा टाइगर रिजर्व के गैंडा पुनर्वास क्षेत्र में अब कुछ समय तक पर्यटकों की चहल-पहल नहीं रहेगी। वन्यजीवों और पर्यटकों की सुरक्षा के मद्देनजर पार्क प्रशासन ने गैंडा क्षेत्र के भ्रमण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय हाथियों के बदले हुए व्यवहार और हाल ही में हुई एक दुखद घटना के बाद एहतियातन लिया गया है। पार्क सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में दुधवा के हाथी विनायक ने अपने ही चारा कटर को पटक-पटक कर मार डाला था। दुधवा प्रशासन का मानना है कि हाथी बेहद संवेदनशील और बुद्धिमान प्राणी होते हैं।

पर्यटकों के लिए खतरा केवल पालतू हाथियों से ही नहीं, बल्कि जंगली हाथियों की आमद से भी है। सलूकापुर बेस कैंप के आसपास इन दिनों जंगली हाथियों के झुंड ने डेरा डाला है। ऐसे में पालतू हाथियों को जंगल में ले जाना जोखिम भरा है, क्योंकि जंगली हाथी उन पर हमला कर सकते हैं। चूंकि गैंडा क्षेत्र का भ्रमण हाथियों की पीठ पर सवार होकर ही किया जाता है, इसलिए सुरक्षा कारणों से इस गतिविधि को फिलहाल बंद कर दिया गया है।

करनाल के निजी अस्पताल में दाखिल घायल कपिल। जागरण

केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद तेजी से विकास कर रहा लद्दाख : शाह

राज्य ब्यूरो, जागरण • जम्मू

- बुद्ध पूर्णिमा पर शांति के संदेश के साथ लद्दाख में दुग्ध क्रांति की रखी नींव
- जुवेत्सल में भगवान बुद्ध के पवित्र स्मृति चिह्न को किया नमन, प्रदर्शनी का किया शुभारंभ

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा पर शांति का संदेश देने के साथ लद्दाख में दुग्ध क्रांति की नींव रखी। इसके साथ लेह के जेवेत्सल में भगवान बुद्ध की पवित्र स्मृति चिह्नों को नमन करते हुए प्रदर्शनी का शुभारंभ कर कहा कि बौद्ध धर्म की जीवंत भूमि लद्दाख ने बौद्ध शिक्षाओं को सदियों से संरक्षित व पोषित किया है। उन्होंने कहा कि शांति, करुणा से ही अशांति का समाधान संभव हो सकता है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। यह प्रदेश मोदी सरकार की प्राथमिकता है।

लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद पहली बार दो दिवसीय दौरे पर आए गृह मंत्री ने प्रदर्शनी के शुभारंभ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विकास में नजरअंदाज होने से लद्दाख लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मांग रहा था। यह मांग पूरी होने के बाद अब लद्दाख के हर क्षेत्र में बेहतर बदलाव आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि लद्दाखियों की देशभक्ति पर सबको गर्व है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से लद्दाख में खुशहाली व आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रही है।

शाह का यह बयान लद्दाख में उन संगठनों के लिए एक संदेश था, जो प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा व संविधान की छठी अनुसूची की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर सितंबर 2025 को लेह में हिंसक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें चार लोगों की मौत और कई घायल हो गए थे।

गृह मंत्री ने कहा कि देश में 75 सालों के बाद लौटे भगवान बुद्ध की पवित्र स्मृतियों के दर्शन एक ऐतिहासिक आयोजन है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से भारत पूरी दुनिया में शांति व भाईचारे का संदेश फैला रहा है। लद्दाख में आधुनिक विकास व सांस्कृतिक धरोहर का संगम हो रहा है।

लेह में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के उद्घाटन पर बौद्ध साधु का अभिवादन करते अमित शाह। एएनआइ

गिरफ्तारी के डर से मलेशिया में 10वीं मंजिल से कूदा दंपती, पत्नी की मौत

जागरण संवाददाता, करनाल

- अवैध रूप से रह रहे दंपती ने इमिग्रेशन की कार्रवाई के कारण उठाया यह कदम

मलेशिया में अवैध रूप से रह रहे करनाल (हरियाणा) के दंपती ने गिरफ्तारी के डर से 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। इस हादसे में पत्नी अनुष्का (25) की मौत हो गई, जबकि पति कपिल (28) गंभीर रूप से घायल हो गए। सामाजिक और सरकारी प्रयासों से अनुष्का का शव भारत लाया गया है। कपिल को भी स्वदेश लाया गया है। उसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

यह दंपती करीब ढाई वर्ष पहले टूरिस्ट वीजा पर मलेशिया गया था। वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद दोनों अवैध रूप से वहां रहकर काम कर रहे थे। हाल ही में मलेशिया की सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। 15 दिन पहले इमिग्रेशन टीम ने पुलिस के साथ मिलकर उस भवन में छापेमारी की, जहां यह दंपती रह रहा था। गिरफ्तारी के डर से दोनों ने बिल्डिंग की 10वीं मंजिल से कूदने का निर्णय लिया। इस हादसे में अनुष्का की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कपिल गंभीर रूप से घायल होकर कोमा में चला गया।

कपिल के परिवार को जब इस घटना की जानकारी मिली, तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के पास न तो पासपोर्ट था और न ही आर्थिक संसाधन। इसी बीच, मलेशिया के एक एनजीओ संचालक ने परिवार से संपर्क किया और मदद का भरोसा दिया।

उसने कपिल के इलाज के लिए धनराशि की आवश्यकता बताई। परेशान परिवार ने कर्ज लेकर एक लाख, 80 हजार रुपये आनलाइन भेज दिए, लेकिन आरोप है कि एनजीओ ने केवल 70 हजार रुपये अस्पताल में जमा कराए। कपिल के भाई दीपक और जीजा मुकेश ने एडवोकेट विकास सुखीजा से संपर्क किया। विकास सुखीजा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर मदद की अपील की।

आदि कैलास यात्रा शुरू, उच्च हिमालय में लौटी रौनक

जागरण संवाददाता.पिथौरागढ़

- पहले दिन 250 श्रद्धालुओं ने किए आदि कैलास के दर्शन

चार धाम के बाद शुक्रवार से आदि कैलास व ओम पर्वत दर्शन यात्रा शुरू हो गई है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर समुद्र तल से 14500 फीट की ऊंचाई पर स्थित आदि कैलास में शिव मंदिर के कपाट जनजातीय रं रीति रिवाज से पूजा-अर्चना एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। पहले दिन पिथौरागढ़ के धारचूला से पहुंचे 250 से अधिक श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के दर्शन किए। दोपहर बाद ज्योलिंगकांग (आदि कैलास) क्षेत्र में हिमपात भी हुआ। आदि कैलास यात्रा शुरू होने के साथ ही उच्च हिमालय में रौनक लौट आई है।

शुक्रवार सुबह 10:41 बजे मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही इस वर्ष की आदि कैलास और ओम पर्वत दर्शन यात्रा शुरू हुई। श्रद्धालुओं ने चारों तरफ बर्फ से चमकती चोटियां के बीच आदि कैलास के दिव्य दर्शन किए। शिव मंदिर में रं समाज (व्यास, चौदास व दारमा घाटी के निवासी), आइटीबीपी की 36वाहिनी के सेनानी संजय कुमार की मौजूदगी में मंदिर के धामी (पुजारी) गोपाल सिंह कुटियाल, विरेंद्र सिंह कुटियाल, चैत सिंह कुटियाल ने रं परंपरा के तहत अनुष्ठान किए। आदि कैलास दर्शन के बाद सभी श्रद्धालु गुंजी और नाबी की ओर लौट गए, जो शनिवार को ओम पर्वत दर्शन के लिए जाएंगे।

इससे पहले पिथौरागढ़ के धारचूला में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे यात्रियों को एसडीएम आशीष जोशी ने हरी झंडी दिखाकर आदि कैलास के लिए रवाना किया। एसडीएम ने बताया कि अब तक आदि कैलाश दर्शन के लिए 350 लोगों को परमिट जारी कर दिए गए हैं। इनरलाइन परमिट जारी करने की प्रक्रिया जारी है। आदि कैलास यात्रा के लिए इनर लाइन परिमिट लेना अनिवार्य है। 2025 में 36,600 श्रद्धालुओं ने आदि कैलास यात्रा की थी।

पिथौरागढ़ में आदि कैलास स्थित शिव मंदिर के कपाट खुलने के दौरान मौजूद मंदिर के पुजारी और आइटीबीपी के अधिकारी। जागरण

विंध्याचल में दर्शनार्थियों पर मधुमक्खियों का हमला, नौ घायल

जागरण संवाददाता, मीरजापुर : विंध्याचल धाम में शुक्रवार दोपहर बालक का मुंडन कराने रायबरेली से आए दर्शनार्थियों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसमें नौ लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विंध्याचल में भर्ती कराया गया है।

रायबरेली निवासी रामआसरे यादव अपने नाती अभिनव का मुंडन संस्कार कराने करीब 25 परिवारजन और रिश्तेदारों के साथ निजी वाहन से विंध्याचल आए थे। गंगा स्नान और मां विंध्यवासिनी मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद दोपहर करीब एक बजे सभी मीरजापुर-प्रयागराज मार्ग स्थित अटल चौक के पास पीपल के पेड़ के नीचे भोजन बनाने लगे। इसी दौरान चूल्हे से निकले धुएं के कारण पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते में हलचल मच गई और मधुमक्खियां उग्र होकर श्रद्धालुओं पर टूट पड़ीं। हमले से वहां अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाने के लिए आसपास के घरों और दुकानों में भागकर छिप गए।

उद्योगपति गौतम अदाणी ने किए केदारनाथ धाम के दर्शन

रुद्रप्रयाग स्थित विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में शुक्रवार को दर्शनों के बाद पत्नी संग मंदिर से बाहर आते उद्योगपति गौतम अदाणी (मध्य में)। फोटो : बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग

प्रमुख उद्योगपति गौतम अदाणी शुक्रवार को पत्नी प्रीति अदाणी के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर जलाभिषेक किया। शादी की 40वीं वर्षगांठ पर धाम पहुंचे गौतम अदाणी ने प्रस्तावित सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे परियोजना का हवाई सर्वे भी किया। इस परियोजना का निर्माण अदाणी समूह कर रहा है।

अदाणी निजी हेलीकाप्टर से केदारनाथ पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। धाम पहुंचने पर बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने उनका स्वागत किया और दर्शन के बाद भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया। हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे परियोजना केदारनाथ यात्रा को और अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। 13 किलोमीटर लंबे सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे के निर्माण पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। डीपीआर तैयार हो चुकी है। परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

दर्शन पास निश्शुल्क, फिर भी ठगे जा रहे श्रीराम के भक्त

जागरण संवाददाता, अयोध्या : श्रीराम मंदिर में प्रभु रामलला के दर्शन की अभिलाषा लेकर देश-दुनिया से आ रहे श्रद्धालु जालसाजों के आसान निशाने पर हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने विशिष्ट दर्शन और आरती के लिए पास की सुविधा पूरी तरह निश्शुल्क रखी है, इसके बावजूद बाहरी श्रद्धालुओं से अवैध वसूली का खेल थम नहीं रहा है। ताजा मामला ओडिशा की एक महिला श्रद्धालु से जुड़ा है, आनलाइन पास के नाम पर दो हजार रुपये ऐंठ लिए।

रामलला के दर्शन के लिए ट्रस्ट तीन श्रेणियों में पास जारी करता है। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु समय बचाने और सुलभ दर्शन की चाह में अक्सर उन होटलों या होम स्टे के जाल में फंस जाते हैं, जहां दलाल सक्रिय हैं। पिछले साल कर्नाटक के मैसूर और न्यूजीलैंड से आए पर्यटकों के साथ भी ऐसी ही ठगी हुई थी, इस पर पुलिस ने छापेमारी कर कुछ गिरफ्तारियां की थी। हालांकि, कुछ समय की शांति के बाद अब यह सिंडिकेट फिर सक्रिय हो गया है।

डी हैविलैंड कामेट 1 की पहली उड़ान के साथ जेट युग की हुई शुरुआत

1952 में आज ही ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन ने लंदन से जोहान्सबर्ग के लिए पहली यात्री जेट(डी हैविलैंड कामेट 1) सेवा शुरू की थी। यह उस समय के प्रोपेलर विमानों की तुलना में दोगुना तेज और आरामदायक था। इसने विमानन के जेट युग की शुरुआत की।

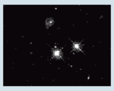

विलियम हर्शेल ने पहले बाइनरी स्टार की खोज की

1780 में आज ही ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने पहली बार बाइनरी स्टार या द्विआधारी तारे 'जी उर्से मेजरिस' की खोज की थी। ये तारे अकेले नहीं, बल्कि जोड़े में एक-दूसरे की परिक्रमा करते हैं। इससे साबित हुआ कि न्यूटन के नियम सौर मंडल के बाहर भी लागू होते हैं।

ब्रज बासी लाल ने दिए थे अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने के साक्ष्य

प्रख्यात पुरातत्वविद् ब्रज बासी लाल का जन्म 1921 में आज ही झांसी में हुआ था। 1943 में सर मोर्टिमर व्हीलर के तहत तक्षशिला में प्रशिक्षण हासिल किया। बाद में एएसआइ में शामिल हुए। 1968 से 1972 तक एएसआइ के महानिदेशक पद पर रहे। उन्होंने अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, चित्रकूट व श्रृंगवेरपुरा जैसे रामायण से जुड़े स्थलों की खुदाई की। ब्रज बासी लाल ने ही अयोध्या में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर होने के पुरातात्विक साक्ष्य उजागर किए थे। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता और महाभारत से जुड़े स्थलों पर भी व्यापक कार्य किया। 50 से अधिक किताबें और 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए।

गोरा करने वाली क्रीम व स्टेरायड से बिगड़ सकता है चेहरा व त्वचा

चिकित्सकीय सलाह जरूरी, नहीं तो बढ़ जाता है त्वचा का लालपन व गहरा दाग

26वें अंतरराष्ट्रीय पिगमेंट सेल सम्मेलन में विशेषज्ञों ने दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **क्लोबेटासोल, बेटामेथासोन और हाइड्रोक्विनोन जैसे तत्व वाली क्रीम का लंबे समय तक बिना निगरानी इस्तेमाल से त्वचा को स्थायी रूप से प्रभावित**

प्रतीकात्मक

बिना चिकित्सकीय सलाह के स्टेरायड युक्त और गोरा या त्वचा को निखार देने वाली क्रीमों का इस्तेमाल चेहरे और त्वचा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। इसके गलत उपयोग से त्वचा का पतला होना, लालपन, मुंहासे और गहरे दाग जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। यह चेतावनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 26वें अंतरराष्ट्रीय पिगमेंट सेल सम्मेलन (आइपीसीसी 2026) के पहले दिन में त्वचा रोग विशेषज्ञों ने दी।

विशेषज्ञों ने बताया कि बाजार में इन दिनों क्रीमों के बड़े-बड़े विज्ञापन टीवी और इंटरनेट मीडिया पर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। दुकानों पर ये उत्पाद आसानी से बिना किसी चिकित्सीय पर्चे के उपलब्ध हैं, जिससे लोग बिना किसी विशेषज्ञ सलाह के इन्हें इस्तेमाल करने लगते हैं। हालांकि कई बार दावों के विपरीत इनका अनियंत्रित उपयोग त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचाता है।

विशेषज्ञों के अनुसार कई काम्बिनेशन क्रीमों में क्लोबेटासोल, बेटामेथासोन और हाइड्रोक्विनोन जैसे शक्तिशाली तत्व होते हैं, जिनका लंबे समय तक बिना निगरानी इस्तेमाल त्वचा को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है। शुरुआत में त्वचा साफ या चमकदार दिख सकती है, लेकिन धीरे-धीरे इसके दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं।

डाक्टरों ने बताया कि ऐसे उत्पादों के दुरुपयोग से त्वचा पतली होना, लालपन, जलन, मुंहासों का बढ़ना और गहरे दाग पड़ना आम हो जाता है। कई मामलों में मरीज स्टेरायड डैमेज्ड फेस की स्थिति में अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उपचार जटिल और लंबा हो जाता है।

विशेषज्ञों ने यह भी रेखांकित किया कि सोशल मीडिया, दोस्तों या केमिस्ट की सलाह पर क्रीम लेने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है, जिससे पिगमेंटरी विकार जैसे मेलास्मा और हाइपरपिगमेंटेशन और गंभीर हो रहे हैं। जोर दिया कि त्वचा से जुड़ी किसी भी समस्या में स्वयं दवा लेने से बचना चाहिए।

योग्य त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श कर ही उपचार शुरू करना सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। साथ ही सुरक्षित उपचार पद्धतियों और जन-जागरूकता को बढ़ावा देना समय की जरूरत बताया गया, ताकि मरीजों को सही और समय पर उपचार मिल सके।

अल्ट्रा प्रोसेस्ड व जंक फूड की आदत देश में बढ़ा रही कैंसर का जोखिम

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- **फोर्टिस हेल्थकेयर के फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट की ओर से दिल्ली में दो व तीन मई को आयोजित हो रही फोर्टिस कैंसर समिट 2026 में जुट रहे हैं वैश्विक कैंसर विशेषज्ञ**
- **समिट में कैंसर उपचार में आने वाली बाधाओं को नई तकनीकी से दूर करने, एकीकृत व साक्ष्य-आधारित कैंसर केयर पर होगा मंथन**

प्रतीकात्मक

बदलती जीवनशैली विशेषकर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड और जंक फूड की बढ़ती आदत देश में कैंसर के जोखिम को बढ़ा रही है। कैंसर विशेषज्ञों के अनुसार इनका अत्यधिक सेवन मोटापा, हार्मोनल असंतुलन और शरीर में सूजन जैसी स्थितियां पैदा करता है। अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड ऐसे पैकेज्ड खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनमें अधिक मात्रा में नमक, चीनी, वसा और कृत्रिम एडिटिव्स शामिल होते हैं, जो कैंसर के जोखिम को बढ़ाते हैं। इसे देखते हुए कैंसर केयर के भविष्य व बदलते स्वरूप, कैंसर उपचार में आने वाली बाधाओं को नई तकनीकी से दूर करने पर मंथन करने के लिए दो मई से दिल्ली में दो दिवसीय फोर्टिस कैंसर समिट-2026 में बड़ी संख्या में देश-विदेश के कैंसर विशेषज्ञ जुट रहे हैं।

फोर्टिस कैंसर इंस्टीट्यूट के कैंसर विशेषज्ञों ने बताया कि समिट में देश के 50 से अधिक कैंसर सेंटर, 500 से ज्यादा फैकल्टी व 25 देशों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। भारत में हर वर्ष लगभग 15 लाख नए कैंसर मामले सामने आ रहे हैं, जबकि करीब 40 लाख लोग किसी न किसी कैंसर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अध्ययनों से पता चला है कि अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की खपत में हर 10% की वृद्धि से कैंसर का समग्र जोखिम 12% और स्तन कैंसर का जोखिम 11% तक बढ़ सकता है। प्रोसेस्ड फूड में चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट की अधिकता होती है, जो वजन बढ़ाता है। मोटापा खुद कई प्रकार के कैंसर के जोखिम को बढ़ाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि देश में जागरूकता की कमी के कारण कई लोग शरीर में पनप रही इस बीमारी के बारे में समय पर जान नहीं पाते, जिससे उपचार में देरी होती है। शुरुआती जांच, स्क्रीनिंग व जागरूकता बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।

रोबोटिक कुत्ते

रबर्लिन स्थित न्यू नेशनल गैलरी में डिजिटल आर्टिस्ट बीपल(माइक विंकलमैन) की इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टालेशन दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां रोबोटिक कुत्ते घूम रहे हैं, जिनके सिर जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, एंडी वारहोल और अन्य हस्तियों जैसे बनाए गए हैं। रायटर

पार्किंसंस से पीड़ित पुरुषों और महिलाओं के लक्षणों में कई अंतर

अनुसंधान

हाल ही में पार्किंसंस रोग से पीड़ित 11,000 लोगों पर किए गए अध्ययन से इसके लक्षणों और जोखिम कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली हैं। इसमें इस बात का पता चला है कि पुरुषों और महिलाओं पर इसके लक्षण किस प्रकार सें भिन्न होते हैं।

शोध के दौरान पाया गया कि यह बीमारी पुरुषों में महिलाओं की तुलना में डेढ़ गुना अधिक आम पाई जाती है है। सर्वेक्षण में शामिल 63 प्रतिशत लोग पुरुष थे। पार्किंसंस रोग पुरुषों और महिलाओं में अलग-अलग तरह से प्रकट होता है और बढ़ता है।

अध्ययन में पाया गया कि पार्किंसंस के लक्षण शुरू होने के समय महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम उम्र की थीं (63.7 बनाम 64.4 वर्ष) और निदान के समय भी (67.6 बनाम 68.1 वर्ष)। साथ ही, उनमें दर्द (70 प्रतिशत बनाम 63 प्रतिशत) और गिरने (45 प्रतिशत बनाम 41 प्रतिशत) की आशंका भी पुरुषों की तुलना में अधिक थी। पुरुषों में महिलाओं की तुलना में स्मृति परिवर्तन (67 प्रतिशत बनाम 61 प्रतिशत) और आवेगपूर्ण व्यवहार (56 प्रतिशत बनाम 19 प्रतिशत) अधिक देखा गया।

इस तरह के अध्ययन पार्किंसंस रोग से जुड़े जोखिम कारकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये हमें लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले लक्षणों को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्किंसंस रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं। हर किसी को एक जैसे लक्षण एक ही हद तक अनुभव नहीं होंगे। इसी तरह, समय के साथ रोग की प्रगति भी अलग-अलग लोगों में भिन्न पाई जाती है। उनका इलाज भी भिन्न होता है। (द कन्वर्सेशन)

इधर-उधर

एयरपोर्ट पर आस्कर ट्राफी को समझ लिया हथियार

गायब हो गई पाशा तालिनकिन को मिली ट्राफी। इंटरनेट मीडिया

वाशिंगटन, प्रेट्र : रूसी फिल्ममेकर पाशा तालिनकिन ने डाक्यूमेंट्री मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन के लिए आस्कर अवार्ड जीता था। न्यूयार्क के जेएफके एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों ने ट्राफी को यह कहकर विमान में ले जाने से रोक दिया कि इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। अंततः उन्हें ट्राफी को कार्गो के रूप में ले जाना पड़ा। लेकिन जब वह लुफ्थांसा एयरलाइन से जर्मनी के फ्रैंकफर्ट पहुंचे, तो अवार्ड गायब था। पाशा ने कहा कि वह अवार्ड के साथ कई बार हवाई यात्रा कर चुके हैं। उन्हें पहली बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा।

100 वर्ष में ढाई किमी पीछे खिसका पिंडारी ग्लेशियर

जागरण संवाददाता, बागेश्वर

- **राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान और ईआइएसीपी के सर्वे के बाद सामने आई स्थिति**
- **वर्ष 1916 के आसपास पिंडारी जीरो प्वाइंट तक जमी रहने वाली बर्फ धीरे-धीरे गई पिघलती**

बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर के सर्वेक्षण को पहुंची टीम। सौ. डा. महेशानंद।

पिंडारी ग्लेशियर पिछले 100 वर्ष में लगभग ढाई किमी पीछे खिसक गया है। ग्लेशियर से ढाई किमी पूर्व जीरो प्वाइंट तक रहने वाली बर्फ का अब नामोनिशान नहीं है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही आपदा व मानवीय दखल के कारण उपजी स्थिति क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है। ऐसे में जरूरत अब ईको-फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने की है।

अल्मोड़ा के गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान की ओर से पर्यावरण सूचना जागरूकता क्षमता निर्माण व आजीविका कार्यक्रम (ईआइएसीपी) के तहत पिंडारी ग्लेशियर भू-क्षेत्र के पर्यावरणीय सर्वेक्षण के बाद यह स्थिति सामने आई है।

संस्थान की पांच सदस्यीय टीम 24 से 28 अप्रैल तक पिंडारी ग्लेशियर में रही। टीम में शामिल ईआइएसीपी अधिकारी डा. महेशानंद ने बताया कि पांच दिनों तक ग्लेशियर का अध्ययन किया। ग्रामीणों के साथ ही ग्लेशियर तक जाने वाले पोर्टरों को भी इसमें शामिल किया गया। पूर्व के फोटोग्राफ व डाटा एकत्र किया गया। इससे निष्कर्ष निकला कि वर्ष 1916 के आसपास पिंडारी जीरो प्वाइंट तक जमी रहने वाली बर्फ धीरे-धीरे पिघलती गई। इससे ग्लेशियर लगातार पीछे खिसकता गया, जो कि चिंता का विषय है। उच्च हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहां समय-समय पर तीव्र वर्षा होती रहती है, जिससे भूमि कटाव की समस्या भी बढ़ रही है। इस चुनौती से निपटने के लिए वन विभाग ने विभिन्न स्थानों पर नारियल की रस्सियों से बने जाल लगाए हैं ताकि मृदा क्षरण तथा भू-कटाव को रोका जा सके।

मेघालय के सबसे स्वच्छ गांव माव्लिन्नोंग में नई जुगनू प्रजाति की खोज

शिलांग, प्रेट्र : मेघालय के माव्लिन्नोंग को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। यहां एक नई जुगनू प्रजाति की खोज के साथ अपने नाम में एक और विशेषता जोड़ ली है। शोधकर्ताओं ने मेघालय के पहले वैज्ञानिक रूप से दर्ज किए गए चमकदार कीड़ों का दस्तावेजीकरण किया है। असम डान बोस्को विश्वविद्यालय की एम्मा मैगडलेन नोंगलोंग के नेतृत्व में किए गए अध्ययन में दो पहले से अज्ञात प्रजातियों डियाफेनेस मेघालयनस और डियाफेनेस माव्लिन्नोंग की पहचान की गई, जिसमें से बाद की नामकरण उस गांव के नाम पर किया गया, जहां इसे पहली बार दर्ज किया गया। जहां डी मेघालयनस राज्य के विभिन्न आवासों में पाया गया, वहीं डी माव्लिन्नोंग को भारत-बांग्लादेश सीमा के निकट माव्लिन्नोंग गांव के घने वन क्षेत्र में देखा गया। जुगनू अव्यवस्थित आवासों में पाए गए, जिसमें अर्ध वन और चट्टानी नदियों के निकट बांस के पैच शामिल हैं।

फिल्म रिव्यू

राजा शिवाजी ✪✪✪✪◖

मुख्य कलाकार : रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, विद्या बालन, अभिषेक बच्चन, महेश मांजरेकर, सचिन खेड़ेकर, अमोल गुप्ते **निर्देशक** : रितेश देशमुख **अवधि** : तीन घंटे सात मिनट

शिवाजी राजे की गौरवगाथा

रितेश देशमुख ने शिवाजी की भूमिका को जिया है। चित्र सौ.: फिल्म टीम

एक छोटा-सा बच्चा मुगलों, निजामशाही और आदिलशाही का झंडा देखकर अपने झंडे के बारे में पूछता है। जवाब मिलता है कि उसके लिए स्वराज्य चाहिए। वह सपना महासंग्राम का रूप लेता है, जब मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज अपना जीवन हिंदवी स्वराज्य पाने के लिए समर्पित करते हैं। उनकी कहानी अभिनेता रितेश देशमुख फिल्म राजा शिवाजी में लेकर आए हैं।

कहानी शुरू होती है दक्कन को पाने की मुगलों, निजामशाही और आदिलशाह की चाह से। लखुजी राव जाधव (महेश मांजरेकर) और शाहजी राजे भोसले (सचिन खेड़ेकर) निजामशाही में काम करते हैं। उन्हें आदिलशाह और मुगल अपनी तरफ लेने का प्रयास करते हैं, ताकि वे दक्कन पर कब्जा कर पाएं। इसी बीच शाहजी के दोनों बेटे संभाजी राजे (अभिषेक बच्चन) और शिवाजी राजे (रितेश देशमुख) गुलामी के सामने झुकाने से इन्कार करते हैं। आदिलशाही में काम कर रहा अफजल खान (संजय दत्त), मोहम्मद आदिल शाह (अमोल गुप्ते) के इशारे पर शिवाजी राजे और संभाजी राजे को खत्म करना चाहता है। आगे क्या होता है, उसके लिए फिल्म देखनी होगी।

फिल्म के लेखन, निर्देशन और निर्माण की जिम्मेदारी रितेश देशमुख पर थी। शिवाजी राजे के बचपन से लेकर अफजल खान को मार गिराने तक की भव्य कहानी में उनकी दस साल की रिसर्च दिखती है। फिल्म की प्रोडक्शन वैल्यू शानदार है। भव्य सेट हैं, क्लाइमेक्स दमदार है, जिसमें अफजल धोखे से छत्रपति शिवाजी को मारने की कोशिश करता है। इतने पात्रों के बीच भी रितेश की निर्देशन पर पकड़ मजबूत है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन, किशोरावस्था, पत्नी सईबाई और मां जीजाबाई के साथ उनका मजबूत रिश्ता, भाई संभाजी राजे के साथ भावनात्मक जुड़ाव, स्वराज्य में भगवा लहराने का आत्मविश्वास, अद्भुत युद्ध नीतियों को रितेश ने फिल्म में विश्वसनीयता से दर्शाया है। अजय-अतुल का संगीत फिल्म की जान है। संतोष सिवन जैसे अनुभवी सिनेमैटोग्राफर का साथ इसे एक स्तर ऊपर ले जाता है।

अगर स्वराज्य समझने जाओगे, तो खुद भगवा लहराओगे... स्वराज्य गुलामी नहीं, वफादारी मांगता है.... जैसे संवाद तालियां बटोरते हैं। अभिनेता रितेश देशमुख ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पात्र को जिया है। हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे, ही तर श्रींची इच्छा... बोलकर जब वह अफजल पर अपने बघनख से वार करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

शिवाजी राजे के बचपन के रोल में रितेश के बेटे राहिल देशमुख चौंकाते हैं। संभाजी राजे के रोल में अभिषेक बच्चन का काम बढ़िया है। सईबाई की छोटी-सी भूमिका में जेनेलिया देशमुख और जीजाबाई के रोल में भाग्यश्री याद रह जाती हैं। विद्या बालन का निभाया बड़ी बेगम का पात्र और बेहतर लिखा जा सकता था। सचिन खेड़ेकर और महेश मांजरेकर का अनुभव फिल्म में नजर आता है। अपनी 63 बेगमों को एक साथ मौत के घाट उतारने वाले अफजल खान की क्रूर भूमिका में संजय दत्त जंचते हैं। शिवाजी राजे के अंगरक्षक जिवा महाले की भूमिका में सलमान खान जब पर्दे पर आते हैं, तो थिएटर तालियों से गूंज उठता है।

प्रियंका सिंह

✪✪✪✪✪ उत्कृष्ट ✪✪✪✪ बहुत अच्छी ✪✪✪ अच्छी ✪✪ औसत ✪ औसत से कम

अपनी राय हमें जरूर बताएं: feature@jagran.com

स्क्रीन शाट

सिनेमा में धर्मेंद्र के योगदान को याद किया हेमामालिनी ने। फाइल

धर्मेंद्र को याद कर भावुक हुईं हेमामालिनी

हमसफर का साथ छूटने का दर्द कभी नहीं जाता, तभी अपने पति व अभिनेता धर्मेंद्र को याद करते हुए अभिनेत्री हेमामालिनी भावुक हो गईं। गुरुवार को मुंबई में हुए लेंस एंड लेगेसी : बालीवुड इन फोकस के उद्घाटन समारोह में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई। उनके सिनेमा के प्रति अपार प्रेम के बारे में बात करते हुए हेमामालिनी ने कहा कि यह श्रद्धांजलि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान की पहचान नहीं है, बल्कि उनकी उस यात्रा की भी है, जो जुनून, समर्पण और दर्शकों के प्रति अपार प्रेम से भरी रही। वह हमेशा कहा करते थे, फिल्म दिल से जुड़ने का एक माध्यम है। उन्हें फिल्मों में काम करने और कैमरे के सामने रहने का जुनून था। एक जीवनसाथी के रूप में मैं यह देख पाती थी कि वह काम को लेकर कितने जुनूनी थे। उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और सभी के प्रति अपने व्यवहार से लाखों लोगों के दिलों को छुआ। उन्होंने एक अभिनेता, दोस्त और पिता के रूप में, खासकर युवा पीढ़ी सहित कई लोगों को प्रेरित किया। वह एक महान इंसान थे। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, लेकिन अब मैं उन्हें बहुत याद करती हूं। वह अब नहीं हैं, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी कैसे बिताऊंगी। इसके बाद वह भावुक हो गईं। उल्लेखनीय है कि पिछले साल 24 नवंबर को बीमारी के बाद धर्मेंद्र का निधन हो गया। उनके निधन के बाद अभी भी उनके प्रशंसक उन्हें याद कर रहे हैं।

सलमान खान की सुपरहीरो फिल्म को मिली हरी झंडी, जल्द शुरू होगी शूटिंग

कुछ समय पहले खबरें आई थी कि अभिनेता सलमान खान अपने करियर की पहली सुपरहीरो फिल्म करने वाले हैं, जिसे द फैमिली मैन वेब सीरीज के मेकर्स राज निदिमोरु और कृष्णा डीके बनाएंगे। हालांकि उसके बाद इस फिल्म को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अब खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म को हरी झंडी मिल गई है और सलमान यह फिल्म कर रहे हैं। इन दिनों दक्षिण भारतीय निर्देशक वामसी पेडिपल्ली के निर्देशन में एक्शन फिल्म कर रहे सलमान उसके बाद एक्शन कामेडी सुपरहीरो फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार फिलहाल फिल्म अपने प्री-प्रोडक्शन चरण में हैं, जहां फिल्म के लुक और तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह एक बड़े बजट की सुपरहीरो फिल्म होगी, जिसे वैश्विक दर्शकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। टीम का लक्ष्य है कि सभी तैयारी पूरी होने के बाद अक्टूबर से इसकी शूटिंग शुरू कर दी जाए। फिल्म की अभिनेत्री को लेकर सामंथा रुथ प्रभु का नाम सामने आ रहा था, हालांकि फिर सुनने में आया है कि वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं और उनके फिल्म में कास्ट होने की खबरें केवल अफवाह है। फिल्म की टीम अब दूसरे कुछ नामों पर विचार कर रहे हैं और अगले कुछ महीनों में लीड एक्ट्रेस की तलाश भी पूरी हो जाएगी। सलमान की यह पहली सुपरहीरो फिल्म होगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो शूटिंग तय समय पर शुरू हो जाएगी।

पहली बार सलमान करेंगे सुपरहीरो फिल्म। इंटरनेट मीडिया

नहीं तो कह देंगे कि टीवी वाली एक्टिंग मत करो : तेजस्वी प्रकाश

वेब सीरीज या फिल्में कर लेने के बाद कई टीवी कलाकार फिर धारावाहिकों की ओर नहीं लौटते हैं। हालांकि अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश ऐसा नहीं सोचती हैं। वह डिजिटल प्लेटफार्म के साथ टीवी पर भी काम कर रही हैं। उनका मानना हैं कि कलाकारों से काम निकलवाना निर्देशकों का काम है। ऐसे में टीवी और सिनेमा के कलाकारों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। तेजस्वी कहती हैं कि मुझे टीवी पर काम करना बेहद पसंद है। मैं जो भी हूं, वो टीवी की वजह से हूं। अगर लोग मुझे जानते हैं, पसंद करते हैं, तो वह केवल टीवी की वजह से ही है। मुझे ओटीटी और टीवी के बीच कोई खास फर्क नहीं दिखता है। मैं जो अभिनय टीवी पर करती आई हूं, वही वेब सीरीज में भी कर रही हूं। यह बस, लोगों का नजरिया है। मेरा मानना है कि अगर निर्देशक सही मिले, तो वह आपके भीतर के कलाकार को समझेगा, नहीं तो फिर वह भी आसानी से कह देगा की टीवी वाली एक्टिंग नहीं चाहिए। काफी कुछ निर्देशकों पर निर्भर करता है। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे अच्छे निर्देशक मिले हैं। इन दिनों लाफ्टर शेफ के तीसरे सीजन में काम कर रहीं तेजस्वी अभिनय के साथ रियलिटी शो करने को लेकर आगे कहती हैं कि मैं वो रियलिटी शोज करती हूं, जो मेरे बहुत ज्यादा दिन न ले।

अभिनय के साथ रियलिटी शोज भी करती हैं तेजस्वी। इंस्टाग्राम - @tejasswiprakash

अनिल कपूर ने बताया मजनू भाई की प्रेरणा कहां से मिली

कुछ किरदार के बनने के पीछे दिलचस्प कहानी होती है। अभिनेता अनिल कपूर द्वारा साल 2007 की सुपरहिट फिल्म वेलकम में निभाया किरदार मजनू भाई के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। कम लोगों को पता होगा कि अनिल ने मजनू भाई के किरदार के लिए प्रेरणा अपनी फिल्म आवारगी से ली थी। एक फैन के एक्स पर किए पोस्ट का जवाब देते हुए अनिल ने बताया कि उनका किरदार आजाद ही मजनू भाई की प्रेरणा बना। उन्होंने लिखा कि आवारगी मेरे करियर की सबसे चर्चित फिल्म नहीं रही, लेकिन यह किरदार मेरे साथ हमेशा रहा। कई साल बाद यही किरदार मजनू भाई के रूप में लौटा, बस एक हल्के अंदाज के साथ... कंधे का झुकाव, हाव-भाव, पागलपन। पहले महेश भट्ट की दुनिया में, और बाद में अनीस बज्मी के स्टाइल में। जिंदगी सच में पूरा चक्कर लगा लेती है। साल 1990 में रिलीज फिल्म आवारगी का निर्देशन महेश भट्ट ने किया था। फिल्म की कहानी आजाद नाम के एक गैंगस्टर की थी, जो मीना (मीनाक्षी शेषाद्रि) को एक कोठे से बचाता है। इसके बाद वह उसकी मदद करने का फैसला करता है और धीरेन (गोविंदा) को भी इसमें शामिल करता है, लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है, जब दोनों पुरुष मीना से प्यार करने लगते हैं और गैंगस्टरों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। इसका प्रभाव फिल्म वेलकम के किरदार मजनू भाई में भी देखा जा सकता है।

आगामी दिनों में किंग और अल्फा फिल्मों में नजर आएंगे अनिल। फाइल